चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

बंगाल ने बढ़ाई चुनाव आयोग की चिंता

पेज-3

कुर्सी का रिश्ता दिखावे का टकराव

पेज-4

अब भारत में तालिबानी फ़रमान

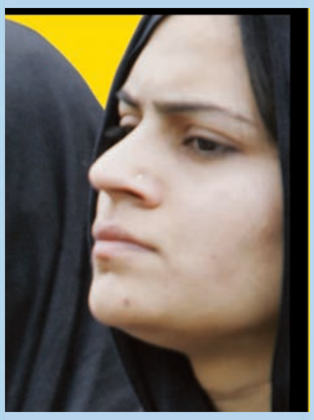

पेज-6

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 07 फरवरी-13 फरवरी 2011 | मूल्य 5 रुपये

आज़ाद भारत के महान घोटाले

एक पौधे को वटवृक्ष बनने के लिए भरपूर खाद-पानी की भी ज़रूरत होती है. आज़ादी के ठीक बाद हमारे राजनेताओं ने घोटालों के फलने-फूलने का पूरा इंतजाम कर दिया था. अगर जीप घोटाले के आरोपी वी के कृष्णमेनन को रक्षा मंत्री नहीं बनाया जाता, प्रताप सिंह कैरों को क्लीन चिट नहीं दी जाती और नागरवाला कांड की सच्चाई जनता के बीच आ जाती तथा असली गुनहगारों का पता चल जाता तो शायद फिर कोई प्रभावशाली आदमी घोटाला करने से डरता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नतीजतन, इस देश को जीप से लेकर 2-जी स्पेक्ट्रम तक सैकड़ों घोटाले सहने पड़े. और न जाने कब तक यह सब सहना पड़ेगा.

सिद्धार्थ राय

किसी भी लोकतंत्र का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके तीनों अंगों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध कैसे हैं और इन तीनों में जवाबदेही बची है या नहीं. आज भारत की दुर्दशा भी इन्ही दो कारकों पर आंकी जा सकती है. पिछले साल भारत में भ्रष्टाचार और घोटालों का बोलबाला रहा. ऐसा लगा, जैसे भारत में घोटाले नहीं, घोटालों में भारत है. आम जनता जहां महंगाई से बदहाल हुई जा रही है, वहीं हमारे नेता और सरकारी अफ़सर नियमों को ताक पर रखकर बेशर्मी से जनता का पैसा दबाए जा रहे हैं. देखने में आया कि भारतीय प्रजातंत्र के तीनों अंग आपस में ही लड़ते रहे. लड़ ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपने भीतर के ही विरोधाभासों से जंग भी कर रहे हैं. मंत्री प्रधानमंत्री की बात नहीं मानते हैं और सुप्रीमकोर्ट हाईकोर्ट में हो रहे भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहा है. सरकारी अफ़सर घोटालों में लिप्त होने के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं. भारत में आज ये सारी घटनाएं एक साथ ऊपरी सतह पर और जनता के सामने आ गई हैं, इसलिए आश्चर्य होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि घोटाला और अनियमितता कोई नई बात है. इस देश में घोटालों की पूरी श्रृंखला है और वह भी बहुत लंबी. भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहां घोटाले नहीं हुए हैं. पहले ये सारे घोटाले जनता की नज़र से या तो बच जाते थे या दबा दिए जाते थे. बात यह भी है कि आपस में ही फूट पड़ने की वजह से राज्य के तीनों तंत्रों में झगड़ा हो गया है और सब एक-दूसरे का गिरेबान पकड़ने में लग गए हैं. अच्छी बात यह है कि इस वजह से जनता को घोटालों के बारे में पता भी चल गया है. आज के भारत में किसी को भी ईमानदार कहना एक ज़ोखिम की बात बन गई है. कल के जो ईमानदार थे, आज उनकी कलई खुल गई है. आज भी मनमोहन सिंह अपने आप को जितना पाक-साफ़ बताएं, लेकिन जनता ने सबसे बड़े घोटाले तो उन्हीं की नाक के नीचे होते देखे हैं. यही हाल शुरू से रहा है. कोई नई बात नहीं है यह. वी के कृष्णमेनन का मुस्तक़बिल इतना ऊंचा था कि ख़ुद नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था और उन्हें भारत के रचयिताओं में जगह दी. लेकिन भारत का पहला घोटाला भी उन्होंने ही कर डाला था, यह भी सच है. आज़ाद होने के बाद से अब तक हमारे प्रजातंत्र का बुरा हाल हो गया है. जवाबदेही धीरे-धीरे सामाजिक जीवन से ग़ायब होती जा रही है. देशप्रेम की कोई जगह नहीं बची है. देश के नेताओं और सरकारी अफसरों के मूल्य घटते जा रहे हैं और आज स्थिति यह आ गई है कि सभी जनता को ठगने में लगे हुए हैं. आइए, हम आपको बताते हैं कि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की नींव इतिहास में कितनी दूर तक जाती है और भारत के सबसे बड़े घोटालों के इतिहास से आपका परिचय कराते हैं.

सिर्फ़ 1992 से लेकर अब तक घोटालों की वजह से देश की आम जनता का लगभग एक करोड़ करोड़ रुपये (10000000 रुपये) का नुक़सान हो चुका है या कहें, आम आदमी का एक करोड़ करोड़ रुपया लूटा जा चुका है.

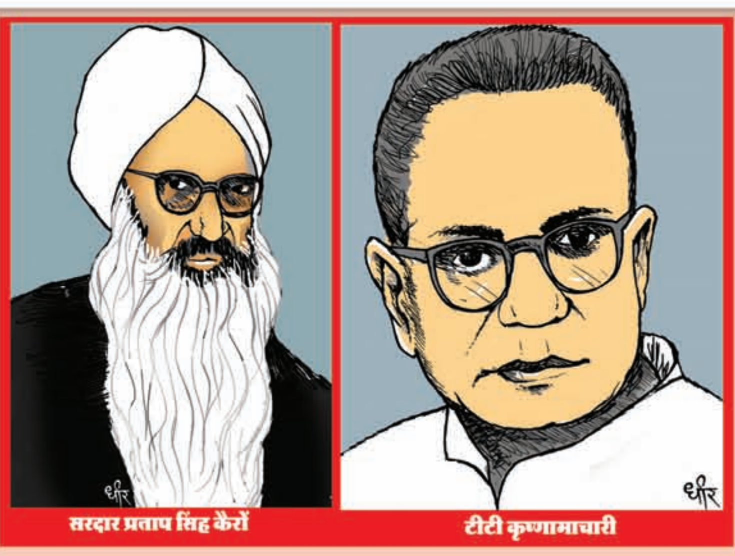

सरदार प्रताप सिंह कैरों | टीटी कृष्णामाचारी

जीप घोटाला आज़ाद हिंदुस्तान का पहला घोटाला था. देश अभी आज़ादी के बाद कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से दो-दो हाथ कर चुका था. तब वी के मेनन ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे. पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को क़रीब 4603 जीपों की जरूरत थी. मेनन इस सौदे में कूद पड़े. उनके कहने पर रक्षा मंत्रालय ने उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दे दिया, लेकिन 9 महीने तक जीपें नहीं आईं. 1949 में जाकर महज 155 जीपें मद्रास बंदरगाह पर पहुंचीं. इनमें से ज्यादातर जीपें तय मानक पर खरी नहीं उतरीं. जांच हुई तो मेनन दोषी पाए गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ. आगे चलकर उन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया गया. ज़ाहिर है, जीप घोटाले ने भारत को घोटालों के देश में तब्दील करने के लिए बीजारोपण तो कर ही दिया था, क्योंकि इससे यह साबित हुआ कि आप भले ही घोटाले कर लो, लेकिन सत्ता पक्ष का समर्थन आपके पास है तो आपको कुछ नहीं होगा. इसमें बाद में कुछ भी नहीं हुआ.

अब जीप के बाद बारी थी साइकिल की, जो साइकिल इंपोर्ट्स घोटाले के रूप में सामने आई. 1951 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव एस ए वेंकटरमण थे. ग़लत तरीक़े से एक कंपनी को साइकिल आयात करने का कोटा जारी करने का आरोप लगा. इसके बदले उन्होंने रिश्वत भी ली. इस मामले में उन्हें जेल भी भेजा गया. लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हर मामले में आरोपी को जेल भेजा ही गया. जैसे सिराजुद्दीन की डायरियों का मामला. साइकिल घोटाले के 6 साल बाद यानी 1956 में यह ख़बर आई कि उड़ीसा के कुछ नेता व्यापारियों के काम कराने के बदले उनसे दलाली ले रहे थे. जब इस संबंध में छापेमारी हुई. पूर्वी भारत केएक बड़े व्यवसायी मुहम्मद सिराजुद्दीन एंड कंपनी के कोलकाता और उड़ीसा स्थित दफ्तरों में भी छापेमारी हुई. पता चला कि सिराजुद्दीन कई खानों का मालिक है और उसके पास से एक ऐसी डायरी मिली, जिससे साबित हो रहा था कि उसके संबंध कई जाने-माने राजनेताओं से थे. लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई. कुछ समय बाद जब यह ख़बर मीडिया के हाथ लगी और छपने लगी, तब तत्कालीन खान और ईंधन मंत्री केशव देव मालवीय ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने उड़ीसा के एक खान मालिक से 10,000 रुपये की दलाली ली थी. बाद में नेहरू के दबाव में मालवीय को इस्तीफ़ा देना पड़ा. लेकिन इस सबके बीच एक अच्छी बात यह रही कि उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग

(शेष पृष्ठ 2 पर)

ये थे बड़े घोटाले...

1948 जीप घोटाला, आज़ाद भारत का पहला घोटाला

1951 साइकिल घोटाला, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव फंसे

1956 बीएचयू फंड घोटाला, आज़ाद भारत का पहला शैक्षणिक घोटाला

1958 मूंध्रा घोटाला, फ़िरोज़ गांधी ने किया ख़ुलासा, फंसे वित्त मंत्री

1963 आज़ाद भारत में मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग का पहला मामला, आरोप प्रताप सिंह कैरों (पंजाब) पर

1965 उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर अपनी ही कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का आरोप

1971 नागरवाला कांड. दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक शाखा से लाखों रुपये मांगने का मामला, इसमें इंदिरा गांधी का नाम भी उछला

1976 कुओ तेल घोटाला. आईओसी ने हांगकांग की फ़र्ज़ी कंपनी के साथ डील की, बड़े स्तर पर घूस का लेनदेन

1995 जूता घोटाला. जूता व्यापारियों ने फ़र्ज़ी सोसाइटी बनाकर सरकार को चूना लगाया

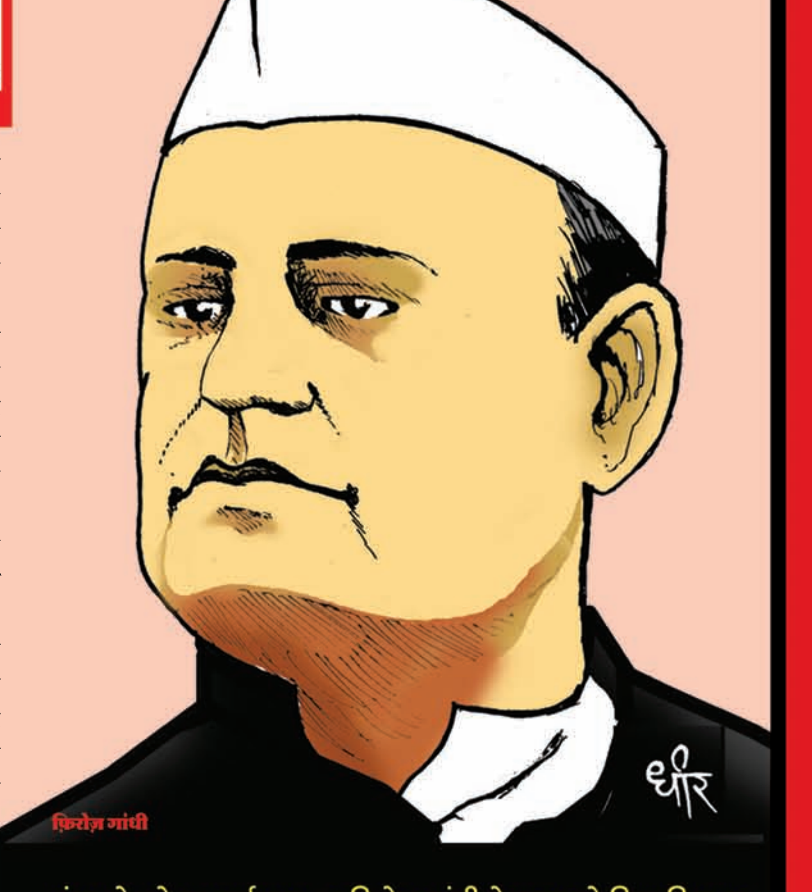

फ़िरोज़ गांधी

मूंधा घोटाले का पर्दाफ़ाश कर फ़िरोज़ गांधी ने सदन को हिला दिया था

स्टांप पेपर घोटाला जब सामने आया था, तब इसे सबसे बड़े घोटाले का ताज मिला था. इसके पीछे अब्दुल करीम तेलगी को मास्टर माइंड बताया गया.

आज़ाद भारत के महान घोटाले

पृष्ठ 1 का शेष

थे, जो भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लिख–बोल सकते थे. उदाहरण के लिए मूंध्रा कांड. 1957 में फिरोज गांधी ने एक सनसनीखेज कांड का खुलासा कर संसद को हिला दिया. उन्होंने बताया कि उद्योगपति हरिदास मूंध्रा की कई कंपनियों को मदद पहुंचाने के लिए उनके शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा 1.25 करोड़ रुपये में खरीदवाए गए. निगम द्वारा शेयरों की बढ़ी हुई कीमत दी गई. जांच हुई तो उस मामले में वित्त मंत्री टी टी कृष्णामाचारी, वित्त सचिव एच एम पटेल और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष दोषी पाए गए. मूंध्रा पर 160 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप था. 180 अपराधों के मामले थे. दबाव बढ़ा तो वित्त मंत्री को पद से हटा दिया गया. मूंध्रा को 22 साल की सजा मिली. कृष्णामाचारी को तो उनके पद से हटा दिया गया, लेकिन प्रताप सिंह कैरों के मामले में सरकार ने ऐसी तेज़ी नहीं दिखाई. 1963 में पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के ख़िलाफ़ कांग्रेसी नेता प्रबोध चंद्र ने आरोपपत्र पेश किया. आरोपपत्र में ये बातें शामिल थीं कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अनाप–शनाप धन–संपत्ति जमा किया. इसमें उनके परिवारीजन शामिल थे. मसलन, अमृतसर कोऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लि., प्रकाश सिनेमा, कैरों ब्रिक सोसायटी, मुकुट हाउस, नेशनल मोटर्स अमृतसर, नीलम सिनेमा चंडीगढ़, कैपिटल सिनेमा जैसी संपत्तियों पर प्रताप सिंह कैरों के रिश्तेदारों का मालिकाना हक़ था. जब जांच हुई तो रिपोर्ट में कहा गया कि कैरों के पुत्र एवं पत्नी ने पैसा कमाया है. लेकिन इस सब के लिए प्रताप सिंह कैरों को साफ़–साफ़ बरी कर दिया गया. कैरों तो बच गए, लेकिन एक और मुख्यमंत्री बीजू पटनायक अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए. उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक पर यह आरोप लगा कि उन्होंने अपनी ही एक निजी कंपनी कलिंगा ट्यूब्स को एक सरकारी ठेका दिया. इस आरोप के बाद उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर होना पड़ा. इतने सालों में राजनेताओं और घोटालों का मानो एक अनकहा संबंध स्थापित हो गया था और इसमें प्रधानमंत्री तक का नाम सामने आने लगा. जैसे नागरवाला कांड. 1971 की 24 मई को दिल्ली में एसबीआई की संसद मार्ग शाखा के कैशियर के पास एक फोन आया. फोन पर उक्त कैशियर से बांग्लादेश के एक गुप्त मिशन के लिए 60 लाख रुपये की मांग की गई और कहा गया कि इसकी रसीद प्रधानमंत्री कार्यालय से ले जाएं. यह ख़बर आई कि फोन पर सुनी जाने वाली आवाज़ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पी एन हक्सर की थी. बाद में पता चला कि यह कोई और आदमी था. रुपये लेने वाले और नकली आवाज निकाल कर रुपये की मांग करने वाले व्यक्ति रुस्तम सोहराबनागरवाला को गिरफ्तार कर लिया गया. 1972 में संदेहास्पद हालात में नागरवाला की मृत्यु हो गई. उसकी मौत के साथ ही मामले की असलियत भी जनता के सामने नहीं आ सकी. इस मामले को रफा–दफा कर दिया गया. घोटालों को दबाने का यह काम अब ज़ोर पकड़ने लगा था. आपातकाल के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के क़रीब 25 आरोप लगे. उन पर 20 एकड़ जमीन अपने दामाद को आवंटित करने, अपने परिवार को बेंगलुरू की पॉश कालोनी में चार कीमती भूखंड आवंटित करने, अपने भाई को राज्य फिल्मोद्योग का प्रभारी बनाने आदि सगे–संबंधियों को अवैध तरीकों से फ़ायदा पहुंचाने के कई आरोप लगे, लेकिन मामला सामने आने के बाद भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ.

1980 का दशक भी घोटालों के लिहाज़ से 2010 की टक्कर ले रहा था. कुओ तेल कांड. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 3 लाख टन शोधित तेल और 5 लाख टन हाई स्पीड डीजल की खरीद के लिए टेंडर निकाला. यह टेंडर हरीश जैन को मिला. जैन की पहुंच राजनैतिक गलियारों तक थी. इस सौदे में 9 करोड़ रुपये से ज़्यादा की हेराफेरी का आरोप लगा. जांच भी हुई. लेकिन कहा जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ही इस मामले से जुड़ी फाइलें गुम हो गईं. तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री पी सी सेठी को इस्तीफ़ा देना पड़ा. बाद में उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया. 1982 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए आर अंतुले का नाम एक घोटाले में सामने आया. उन पर आरोप यह था कि उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान, संजय गांधी निराधार योजना, स्वावलंबन योजना आदि ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा किया था. जो लोग, खासकर बड़े व्यापारी या मिल मालिक ट्रस्ट को पैसा देते थे, उन्हें सीमेंट का कोटा दिया जाता था. ऐसे लोगों के लिए नियम–क़ानून में ढील दे दी जाती थी. ऐसे लोगों के लिए नियम–क़ानून का कोई मतलब नहीं होता था. इस मामले में मुख्यमंत्री पद से ए आर अंतुले को हटना पड़ा. इसके बाद इस दशक के सबसे हाई प्रोफाइल घोटाले से लोगों का परिचय हुआ. बोफोर्स. 1986 में स्वीडन की ए बी बोफोर्स कंपनी से 155 तोपें ख़रीदने का सौदा तय किया गया. कहा गया कि इस सौदे को पाने के लिए 64 करोड़ रुपये की दलाली दी गई थी. ओटावियो क्वात्रोची और राजीव गांधी का नाम इसमें सामने आया. सीबीआई को जांच भी सौंपी गई, लेकिन अंतिम परिणाम अब तक सामने नहीं आ सका है. उल्टे सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी लगाकर इस मामले को बंद करने की गुहार भी लगाई. हालांकि इसमें रक्षा राज्यमंत्री अरुण सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा. यह दशक इसलिए भी चर्चा में रहा कि घोटाला पैदा करने के लिए भी घोटाला किया गया. मसलन, सेंट किट्स धोखाधड़ी. इस मामले में वी पी सिंह की साफ छवि को धूमिल करने के लिए नरसिम्हाराव ने एक षड्यंत्र रचा. उस वक्त नरसिम्हाराव विदेश मंत्री थे. उन्होंने वी पी सिंह पर अवैध पैसा लेने का आरोप लगवाया. बाद में पता चला कि जिन दस्तावेजों के सहारे वी पी सिंह को फंसाने की कोशिश की गई थी, उन पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर थे, जबकि सच्चाई यह थी कि वी पी सिंह किसी भी सरकारी दस्तावेज पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर नहीं करते थे. नतीजतन, वी पी सिंह इस मामले में निर्दोष साबित हुए. नब्बे के दशक तक आते–आते घोटालों का स्वरूप भी बदलने लगा. घोटालेबाज़ चारे जैसी चीज से भी पैसा पैदा करने लगे. जैसे बिहार का चारा घोटाला. लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो यह घोटाला सामने आया. पहली बार लोगों को लगा कि पशुओं को खिलाए जाने वाले चारे में भी घोटाला करके सैकड़ों करोड़ कमाए जा सकते हैं. करीब एक हज़ार करोड़ रुपये के इस घोटाले में राज्य के दो मुख्यमंत्रियों की संलिप्तता की बात सामने आई. उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और 1980 में मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्र दोनों के नाम इस घोटाले से प्रमुख रूप से जुड़े. सीबीआई को इस घोटाले की जांच करने का ज़िम्मा दिया गया. 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है.

नब्बे के दशक में अर्थव्यवस्था तो मुक्त हो गई, लेकिन मुक्त अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई क़ानून नहीं बन सका. नतीजतन, हमें प्रतिभूति जैसे क्षेत्र यानी शेयर मार्केट में भी घोटाला देखने को मिला. यह घोटाला बैंक अफसरों, नेताओं और शेयर दलालों की मिलीभगत का नतीजा था. शातिराना ढंग से ये सारे लोग मिलकर सरकारी नियम–क़ायदों को तोड़कर करोड़ों रुपये की हेराफेरी करते रहे. यह घोटाला 10 हज़ार करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का था. इस मामले में सबसे चर्चित नाम रहा शेयर दलाल हर्षद मेहता का. हर्षद ने इस मामले में नरसिम्हाराव पर भी आरोप लगाया था, लेकिन अंत तक असली अपराधियों का नाम सामने नहीं आ सका. हर्षद मेहता की मृत्यु जेल में रहने के दौरान ही हो गई. शीर्ष राजनेताओं की संलिप्तता का एक और नमूना था लक्खू भाई पाठक केस. अचार व्यापारी लक्खू भाई पाठक ने नरसिम्हाराव और चंद्रा स्वामी पर 10 लाख रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया. लक्खू भाई पाठक इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय व्यापारी थे. उन्होंने यह आरोप लगाया कि 100 हजार पाउंड उन्हें बेवक़ूफ बनाकर इन दोनों ने ठग लिए थे. लक्खू भाई पाठक की मृत्यु हो गई और राव एवं चंद्रा स्वामी 2003 में सबूतों के अभाव में बरी हो गए. एक–एक करके मंत्री और नेता घोटाले पर घोटाले करते गए. सुखराम जो कि दूरसंचार मंत्री थे, पर आरोप लगा कि उन्होंने हैदराबाद की एक निजी कंपनी को टेंडर दिलाने में मदद की, जिसकी वजह से सरकार को 1.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. 2002 में उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा. फिर यूरिया घोटाला हुआ. नेशनल फर्टिलाइजर के एमडी सी एस रामकृष्णन ने कई अन्य व्यापारियों, जो कि नरसिम्हाराव के नजदीकी थे, के साथ मिलकर दो लाख टन यूरिया आयात करने के मामले में सरकार को 133 करोड़ रुपये का चूना लगा दिया. यह यूरिया कभी भारत तक पहुंच ही नहीं पाई. इस मामले में अब तक कुछ भी नहीं हुआ.

नित नए तरीके खोजे जाने लगे. इसी क्रम में हवाला भी सामने आया. देश से बाहर धन भेजने की इस कला से आम हिंदुस्तानियों का परिचय इसी घोटाले की वजह से हुआ. 1991 में सीबीआई ने कई हवाला ऑपरेटरों के ठिकानों पर छापे मारे. इस छापे में एस के जैन की डायरी बरामद हुई. इस तरह यह घोटाला 1996 में सामने आया. इस घोटाले में 18 मिलियन डॉलर घूस के रूप में देने का मामला सामने आया, जो कि बड़े–बड़े राजनेताओं को दी गई थी. आरोपियों में से एक लालकृष्ण आडवाणी भी थे, जो उस समय नेता विपक्ष थे. इस घोटाले से पहली बार यह बात सामने आई कि सत्ताशीन ही नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता भी चारों ओर से पैसा लूटने में लगे हैं. दिलचस्प बात यह थी कि यह पैसा कश्मीरी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को गया था. कई नामों के खुलासे हुए, लेकिन सीबीआई किसी के भी ख़िलाफ़ सबूत नहीं जुटा सकी. नरसिम्हाराव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शैलेंद्र महतो ने यह खुलासा किया कि उन्हें और उनके तीन सांसद साथियों को 30–30 लाख रुपये दिए गए, ताकि नरसिम्हाराव की सरकार को समर्थन देकर बचाया जा सके. यह घटना 1993 की है. इस मामले में शिबू सोरेन को जेल भी जाना पड़ा. 1994 में खाद्य आपूर्ति मंत्री कल्पनाथ राय ने बाज़ार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात का फ़ैसला लिया. यानी चीनी घोटाला. इस कारण सरकार को 650 करोड़ रुपये का चूना लगा. अंतत: उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा. उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा.

बहरहाल, नब्बे के दशक में घोटाले भी अजीबोग़रीब शक्ल लेने लगे. जैसे जूता घोटाला. सोहिन दया नामक एक व्यापारी ने मेट्रो शूज के रफीक तेजानी और मिलानो शूज के किशोर सिगनापुरकर के साथ मिलकर कई सारी फर्जी चमड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाईं और सरकारी धन लूटा. 1995 में इसका खुलासा हुआ और बहुत सारे सरकारी अफसर, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन के अफसर, सिटी बैंक, बैंक ऑफ ओमान, देना बैंक आदि भी इस मामले में लिप्त पाए गए. इन सबके ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाखिल किया गया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आ सका. तब तक देश 21वीं सदी में पहुंच चुका था. अब घोटाले कैमरे पर भी होने लगे और सीधे दुनिया ने इसे होते हुए देखा. इसका एक उदाहरण तहलका कांड है. एक मीडिया हाउस तहलका के स्टिंग ऑपरेशन ने यह खुलासा किया कि कैसे कुछ वरिष्ठ नेता रक्षा समझौते में गड़बड़ी करते हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिश्वत लेते हुए लोगों ने टेलीविजन और अख़बारों में देखा. इस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार का नाम भी सामने आया. इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी ने जॉर्ज फर्नांडीज का इस्तीफ़ा मंजूर करने से इंकार कर दिया. हालांकि बाद में जॉर्ज ने इस्तीफ़ा दे दिया.

इन घोटालों से खेल जगत भी नहीं बच सका. साल 2000 का मैच फिक्सिंग याद कीजिए. जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का धब्बा पहली बार भारतीय खिलाड़ियों पर लगा. इसमें प्रमुख रूप से अज़हरुद्दीन और अजय जडेजा का नाम सामने आया. अजय शर्मा और अजहर पर आजीवन प्रतिबंध लगा तो जडेजा और मनोज प्रभाकर पर पांच साल का प्रतिबंध.

बराक मिसाइल रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का एक और नमूना बराक मिसाइल की ख़रीदारी में देखने को मिला. इसे इज़रायल से ख़रीदा जाना था, जिसकी क़ीमत लगभग 270 मिलियन डॉलर थी. इस सौदे पर डीआरडीपी के तत्कालीन अध्यक्ष ए पी जे अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी. फिर भी यह सौदा हुआ. इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई. एफआईआर में समता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आर के जैन की गिरफ्तारी भी हुई. जॉर्ज फर्नांडीस, जया जेटली और नौसेना के एक पूर्व अधिकारी सुरेश नंदा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई. सुरेश नंदा पूर्व नौसेना प्रमुख एस एम नंदा के बेटे हैं. जांच जारी है. अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है.

शेयर मार्केट से निकल कर ये घोटाले बैंकिंग सेक्टर में भी घुस गए. यूटीआई घोटाला. 48 हजार करोड़ रुपये का यह घोटाला पूर्व यूटीआई चेयरमैन पी एस सुब्रमण्यम और दो निदेशकों एम एम कपूर और एस के बासु ने मिलकर किया. ये सभी गिरफ्तार हुए, लेकिन सज़ा किसी को नहीं मिली.

स्टांप पेपर घोटाला जब सामने आया था, तब इसे सबसे बड़े घोटाले का ताज मिला था. इसके पीछे अब्दुल करीम तेलगी को मास्टर माइंड बताया गया. इस मामले में उच्च पुलिस अधिकारी से लेकर राजनेता तक शामिल थे. तेलगी की गिरफ्तारी तो ज़रूर हुई, लेकिन इस घोटाले के कुछ और अहम खिलाड़ी साफ बच निकलने में अब तक कामयाब हैं.

तेल के बदले अनाज. वोल्कर रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आई कि तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपने बेटे को तेल का ठेका दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, हालांकि सरकार ने उन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाए रखा. एक के बाद एक नेता घोटालों के सरताज बनते जा रहे थे. इसी कड़ी में एक और घोटाला सामने आया. ताज कॉरिडोर. 175 करोड़ रुपये के इस घोटाले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती पर लगातार तलवार लटकी रही और अब भी लटकी हुई है. सीबीआई के पास यह मामला है, लेकिन राजनीतिक वजहों से कभी जांच की गति तेज हो जाती है तो कभी मंद. कुल मिलाकर इस घोटाले के आरोपी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे या नहीं, कहना मुश्किल है.

अब भला कार्पोरेट जगत इस बहती गंगा में हाथ धोने से पीछे क्यों रहता. अब सामने आया सत्यम घोटाला. कार्पोरेट जगत का शायद सबसे बड़ा घोटाला. 14 हज़ार करोड़ रुपये के इस घोटाले में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के मालिक राम लिंग राजू का नाम आया. राजू ने इस्तीफ़ा दिया और वह अभी भी जेल में हैं. मुकदमा चल रहा है. राजनैतिक घोटालों की कभी न ख़त्म होने वाली शृंखला में एक और नाम शामिल हुआ. मधु कोड़ा का. मुख्यमंत्री रहते हुए कोई अरबों की कमाई कर सकता है, यह साबित किया झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने. 4 हज़ार करोड़ से भी ज्यादा की काली कमाई की कोड़ा ने. बाद में इन पैसों को विदेश भेजकर जमा किया और विदेशों में निवेश किया. इस मामले में केस दर्ज हुआ. कोड़ा फ़िलहाल जेल में हैं. जांच चल रही है. अब बात ऐसे घोटालों की भी, जहां महज़ सौ–दो सौ करोड़ का नहीं, बल्कि हज़ारों करोड़ का खेल होता है. जैसे राष्ट्रमंडल खेल घोटाला. हजारों करोड़ रुपये का घोटाला, जिसमें अधिकारी से लेकर नेता तक शामिल थे. सीवीसी ने अपनी जांच में कहा कि अनियमितताएं हुईं. फ़िलहाल सुरेश कलमाडी को राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. सीबीआई जांच कर रही है. कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. और अब बात एक ऐसे घोटाले की, जिसका नाम ही आदर्श है. यानी आदर्श घोटाला. मतलब अब घोटाले भी आदर्श होने लगे. आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी (लि.) ने ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से कोलाबा के आवासीय क्षेत्र नेवी नगर और रक्षा प्रतिष्ठान के आसपास इमारत का निर्माण किया. यह योजना कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के परिवार वालों के लिए बनाई गई थी, जबकि इसके फ्लैट्स 80 फीसदी असैनिक नागरिकों को आवंटित किए गए. इस कारनामे में सेना के शीर्ष अधिकारी तक शामिल थे. सेना के दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी बाकी है. मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण से इस्तीफ़ा ले लिया गया.

बहरहाल, घोटालों की यह सूची अभी और लंबी है. जिसकी बात फिर कभी, लेकिन इन घोटालों को देखने–पढ़ने के बाद यह सवाल भी उठता है कि आख़िर इस कैंसर को ख़त्म करने के लिए क्या कोई क़दम भी उठाया गया. भारत में समय–समय पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियम और संस्थाएं बनती आई हैं. इसी वजह से सीबीआई और सीवीसी का गठन हुआ, लेकिन ये दोनों ही अपने मक़सद में नाकाम हैं. अलग–अलग कारणों से. आज तक के इतिहास में सीबीआई को अलग–अलग राजनैतिक पार्टियों ने बस इधर–उधर अपने विरोधियों के पीछे ही दौड़ाया है. ऐसा आरोप शुरू से सीबीआई पर विपक्षी लगाते रहे हैं. और सीवीसी को कोई अधिकार ही नहीं है. स्थिति यह हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री इतने मजबूर और कमज़ोर हो गए हैं कि वह अपने ही मंत्रिमंडल के लोगों पर नकेल नहीं कस पा रहे. सरकार बचाना साख बचाने से ऊपर हो गया है. प्रधानमंत्री संसद से लेकर मीडिया तक कठघरे में खड़े किए गए, लेकिन फिर भी सरकार को सुध नहीं आई. सीवीसी पी जे थॉमस ने तो हद कर दी, लेकिन सरकार फिर भी कुछ नहीं कर पाई. आख़िर क्यों? कहां गए लाल बहादुर शास्त्री और वी पी सिंह जैसे नेता, जो जनता के हित में अपनी कुर्सी तक छोड़ देते थे? कहां गए वे दिन, जब राजनीति घोटालेबाज़ों का गढ़ न होकर सम्मानित लोगों के लिए जनता की सेवा करने का एक ज़रिया था?

साथ में शशि शेखर/राजेश एस. कुमार
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार
वर्ष 2 अंक 48
दिल्ली, 07 फरवरी–13 फरवरी 2011
RNI-DELHIN/2009/30467
संपादक
संतोष भारतीय
मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित
संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301
फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9810017924
प्रसार + 91 9013478398
फैक्स न. 0120–4783950
पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड एवं उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

बंगाल ने बढ़ाई चुनाव आयोग की चिंता

अरविंद मायाराम

बिमल राय

बंगाल की लड़ाई के मैदान में आजकल मेडिकल टीमों के दौरे तो ख़ूब हो रहे हैं, पर युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं मिल रहा है. हत्याओं के बाद परिजनों के आंसू पोछने के लिए सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों के नुमाइंदे तांता लगाए हुए हैं तो संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल यह जान रहे हैं कि हालात कैसे हैं? उधर चुनावी चिंता में दुबले हो रहे चुनाव आयोग की टीमें भी गांवों की धूल फांक रही हैं. रेकी हो रही है. पता लग रहा है कि थानों में सैकड़ों वारंटों की तामील अब तक नहीं हुई है और आरोपी सालों से फ़रार चल रहे हैं. चुनाव आयोग को अब समझ में आ गया है कि बंगाल में चुनाव कराना कितना मुश्किल है? गोलियों के घावों पर मुआवजे का कड़वा मरहम लग रहा है. ममता बनर्जी का कहना है कि अगर वह चुनकर आईं तो बंगाल की जनता को बिल्कुल चंगा कर देंगी, पर अमन के रास्ते पर चलने की अपीलें गोलियों की गर्जना के बीच गुम हो रही हैं. माकपा-तृणमूल के बीच लड़ाई ख़त्म होती है तो माओवादी दस्तक देते हैं और बताते हैं कि उन्हें हाशिए पर गया न समझा जाए. यही बताने के लिए बीती 23 जनवरी को माओवादियों ने सानबनी में 3 माकपा नेताओं का ख़ून कर दिया. इसके पहले 7 जनवरी को लालगढ़ के पास निताई गांव में माकपा कॉडरों के हाथों 9 लोग मारे गए थे. हालात ऐसे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट को निताई गांव में मेडिकल टीम भेजने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि वहां घायलों का इलाज करने से भी रोका जा रहा है, ताकि मृतक संख्या और बढ़े, जिससे विरोधियों को करारा सबक मिले.

तनाव के इस माहौल में भी मनोरंजक दांव-पेंच दिख रहे हैं. बीती 19 जनवरी को बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी सुधीर कुमार राकेश और नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के जकी अहमद की अगुवाई में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक पूर्व मिदनापुर के सुनिया गांव में हालात की रेकी करने गए थे. खेजुरी का दौरा करके जैसे ही टीम गांव में घुसने को हुई, पास के नामालडीहा गांव में गोलियां चलने लगीं. डीएम और एसपी के चेहरे लाल हो गए, पर इन लोगों ने टीम को यह कहकर बहलाया कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं. आयोग की टीम उस ओर जाने लगी तो आगे का रास्ता कई जगह से काटा हुआ मिला. काफिला दूसरी ओर बढ़ा तो उसका सामना नारे लगा रहे माकपा कॉडरों से हुआ, जो कोंटाई के एएसपी हृषिकेश मीणा का विरोध कर रहे थे. इस तरह इलाक़ा-दर-इलाक़ा पुलिस अफसरों पर भेदभाव का आरोप लग रहा है और आरोप माकपा और तृणमूल दोनों लगा रहे हैं. हाल में ममता बनर्जी ने चुनावों में जीत मिलने पर एक एसपी को सबक सिखाने की बात कही थी. पिछले साल सितंबर में खेजुरी को तृणमूल कांग्रेस के क़ब्ज़े से छुड़ाने के लिए यहीं से माकपा कॉडरों की फौज गई थी. इस इलाक़े में महीनों से निषेधाज्ञा लगी है, पर पुलिस को रास्ता काटे जाने का पता ही नहीं था. साफ हो गया कि पुलिस इस इलाक़े में गश्त लगाने की ज़रूरत नहीं समझती. इस प्रसंग को एक सूचना ने और रोचक बना दिया. बाद में पता चला कि गाड़ियों और लोगों का हुजूम देखकर सुनिया गांव के माकपा कॉडरों ने सोचा कि तृणमूल की ओर से हमले की तैयारी हो रही है और इसी की प्रतिक्रिया में गोलियां चलाई गईं, ताकि दुश्मन को डराया और अपने कॉडरों को सतर्क किया जा सके. हैरत है कि पुलिस हर्मादवाहिनी एवं उसके अवैध हथियारों का सुराग भले ही न लगा पा रही हो, पर गोली दागने की आवाज़ उसे तुरंत पटाखे जैसी लगती है. प्रतीकात्मक अर्थ में यह सही भी है, क्योंकि बंगाल में आजकल बम और बंदूकें पटाखा समान हैं और चुनाव में इनका उपयोग भी दीवाली के पटाखों की तरह ही होना है.

ठीक दो दिन पहले मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने दिल्ली में गृहमंत्री पी चिदंबरम को भरोसा दिलाया था कि सभी हथियारबंद गुटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, पर चुनाव आयोग की टीम को अपने पांच दिन के दौरे में जो अनुभव हुआ, उससे माथे पर पसीना आना ही था. कभी माकपा का गढ़ रहे हुगली के आरामबाग में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था, जहां चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक पी एस रंतीश और डी के पांडेय से महिलाएं लिपट कर रोईं और उन्हें माकपा कॉडरों के अत्याचार के बारे में बताया. लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी और उनमें इतना गुस्सा था कि स्थानीय माकपा सांसद और विधायक को पुलिस के घेरे में बाहर निकाला गया. इससे उलट हालात खेजुरी एवं पास के इलाक़ों में दिखे, जहां तृणमूल का क़ब्ज़ा है. क़दमदह में जब घर से भागे कुछ माकपा कॉडरों ने आयोग की टीम से बात करने की कोशिश की तो भीड़ में से किसी ने चुप रहने को कहा. इस पर रंतीश ने एसपी अशोक कुमार से पूछा कि हमारे रहते हुए कोई किसी को बोलने से कैसे रोक सकता है? माकपा कॉडर परिमल माइती की पत्नी प्रतिभा माइती को तृणमूल वालों ने पहले से धमका दिया था. चुनाव आयोग की टीम ने जब उनके घर छोड़कर भागने का कारण पूछा तो उन्होंने इसकी वजह बीमारी बताया. टीम के काफी ढांढस बंधाने पर प्रतिभा ने माना कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही उसका परिवार तृणमूल कार्यकर्ताओं के जुल्म से तंग आकर खेजुरी से बाहर रह रहा है.

इसी दौरान राज्यपाल एम के नारायणन ने भी हिंसा प्रभावित निताई गांव का दौरा किया, जहां हर्मादवाहिनी ने नौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. वहां तारुलता सेन नामक एक विधवा ने कहा, सुना है कि मुझे मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये देने की बात कही गई है. अगर बाद में मेरे इकलौते बेटे को मार दिया जाता है और इतना मुआवज़ा फिर मिलता है तो मैं उसका क्या करूंगी. तारुलता ने एक तरह से राज्य में लगातार जारी हिंसा से उपजी भयावह हताशा की एक झलक दिखाई है. हालांकि उसके जैसी सैकड़ों विधवाएं ऐसी हैं, जिनके पति राजनीति की बलि चढ़ चुके हैं और उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं मिला है. तारुलता ने राज्यपाल से एक और सवाल किया कि आपके चले जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा. एसपी मनोज वर्मा की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा कि यह उस दिन कहां थे, जब माकपा कॉडर घायलों को अस्पताल ले जा रही एंबुलेंस को रोक रहे थे और पुलिस ख़बर देने के चार घंटे बाद निताईग्राम पहुंची. निताईग्राम चुनाव आयोग की टीम भी गई और उसे केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर एक अलग राय देखने को मिली. तृणमूल की मुखिया भले ही जंगल महल से बलों को हटाने की मांग करती रही हों, पर सालबनी के तृणमूल के प्रखंड स्तर के नेताओं ने इलाक़े में स्थानीय पुलिस हटाकर सीआरपीएफ तैनात रखने की गुहार की. इसके पहले 9 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने भी कोलकाता दौरे में लगातार जारी राजनीतिक हिंसा को चिंता का विषय बताया था और कहा था कि इस पर अविलंब रोक लगाना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है.

संवैधानिक प्रमुखों के दौरों से इतना तो अंदाज़ लग गया है कि हालात कितने भयावह हैं. सूचना मिली है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में सभी अवैध हथियारों को ज़ब्त करने का आदेश दे सकता है. आयोग बिहार मॉडल लागू करने के अलावा बंगाल में कुछ अतिरिक्त इंतज़ाम करने की योजना पर भी अमल करने वाला है, जिनमें वोटरों को मतदान के पर्चे देने का काम राजनीतिक दलों से ले लेना और चुनाव आयोग की ओर से उन्हें बंटवाना, दागी लोगों एवं अपराधियों की पहचान करके चुनाव से पहले ही उनकी गिरफ़्तारी करना, अवैध हथियारों के ख़िलाफ़ व्यापक अभियान और ज़ब्ती, राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के चुनाव ख़र्च पर नियंत्रण और निगरानी के लिए अलग बैंक एकाउंट खोलने की व्यवस्था आदि शामिल है. पहले तीन उपायों पर तो चुनाव आयोग दृढ़ता के साथ क़दम उठाने को तैयार है, लेकिन बैंक खातों के लिए वह विचार-विमर्श कर रहा है. पिछले चुनाव में यहां केंद्रीय बलों की क़रीब 600 कंपनियां थीं. इस बार 50 फ़ीसदी वृद्धि तय है. यह भी तय है कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा और संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई निगरानी की व्यवस्था होगी.

मई में होने वाले चुनावों के लिए किसी न किसी बहाने प्रचार भी जारी है. माकपा सिंगूर से नैनो कारखाने के गुजरात जाने से लेकर महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोपों के तीर चला रही है तो तृणमूल एवं कांग्रेस ने वाममोर्चा के 34 सालों की दमन नीति के ख़िलाफ़ जनादेश मांगा है. चुनाव आयोग इस बार बिहार मॉडल लागू करने की सोच रहा है, पर सिर्फ़ इतने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उसे कुछ अभूतपूर्व क़दम उठाने होंगे. जहां तक बिहार मॉडल लागू करने की बात है तो पिछले दो-तीन चुनावों से वहां के राजनीतिक समाज में संयम, क़ानून का डर या उसके प्रति सम्मान दिखा है. इसमें चुनाव आयोग की चुस्ती से ज़्यादा अपराधियों के ख़िलाफ़ नीतीश सरकार की कार्रवाई और बदले माहौल का अहम हाथ रहा. लालू-राबड़ी के जमाने में भी आयोग कड़े क़दम उठाता रहा, पर चुनावी हिंसा और बूथ दखल रोकने में कामयाबी नहीं मिलती थी, पर बंगाल के हालात काफी अलग हैं. यहां वोटरों में दलीय आधार पर विभाजन इतना साफ और कट्टर है कि बड़ी से बड़ी संवैधानिक मशीनरी के फेल होने का ख़तरा पैदा हो गया है. इसका एक जाना-पहचाना कारण यहां स्थानीय निकाय चुनावों का दलीय आधार पर होना है और इसका रास्ता 34 सालों से काबिज वाममोर्चा ने ही दिखाया है. जो दल सत्ता में है, उसके कॉडरों को ही ठेका, राशनिंग व्यवस्था, नौकरी, सब्सिडी आदि के रूप में सत्ता की मलाई का ज़्यादा हिस्सा मिलता रहा है. इसीलिए राजनीतिक ध्रुवीकरण और गहरा होता गया. अन्यथा देश में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि एक राजनीतिक विचारधारा के लोग प्रतिद्वंद्वी दल के डर से महीनों तक गांव छोड़कर वहां रहें, जहां उनके दल का दबदबा है. शोषणविहीन समाज के माकपाई सपने के उलट यहां सत्ताधारियों द्वारा विरोधियों का शोषण होता रहा. हत्या, आतंक, सामाजिक बहिष्कार और अन्य तरीक़े हथियार बनाए गए. अब इन्हीं हथियारों को तृणमूलियों ने अपना लिया है और टकराव इतना घनघोर रूप ले चुका है. बंगाल में चल रही हिंसा की राजनीति में पक्ष और विपक्ष कमोबेश दोनों का हाथ है और दोनों पक्ष अगर संयम नहीं बरतेंगे तो अमन के माहौल में विधानसभा चुनाव कराना नामुमकिन हो जाएगा.

feedback@chauthiduniya.com

नई दिल्ली स्थित अपने फ्लैट की क़ीमत गोगोई ने चुनाव आयोग को 18 लाख रुपये बताई थी. वेबसाइट में उसी फ्लैट की क़ीमत 5.89 लाख रुपये बताई गई है.

बिहार

कुर्सी का रिश्ता दिखावे का टकराव

सरोज सिंह

बिहार में जदयू एवं भाजपा के रिश्तों में मौजूदा तल्ख़ी के भले ही लाख मायने निकाले जाएं, पर यहां की ज़मीनी राजनीतिक सच्चाई को समझने वाले इत्मीनान की लंबी-लंबी सांसें ले रहे हैं. भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर शरद यादव और नीतीश कुमार के बयानों पर भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप का गुस्सा यह ज़रूर एहसास कराता है कि पार्टी में कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा. लेकिन जब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ही हरेंद्र प्रताप को ग़लत ठहरा दिया तो लोगों को यह समझने में देर नहीं लगी कि पुरानी कहानी फिर दोहराई जा रही है.

दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों ने अगर इस सूबे के कुछ राजनीतिक किस्सों को सुलझा दिया तो इसी के साथ कुछ किस्सों को उलझा भी दिया है. जनता ने नीतीश कुमार को प्रचंड जनादेश देकर विकास की नई कहानी लिखने का टास्क दिया. जातीय दीवार टूटने की झलक मिली और यह साफ हुआ कि जो जनता की बात सुनेगा, वही राज करेगा. लेकिन इसके साथ ही जनता ने भाजपा को जदयू से बेहतर सफलता देकर उसे बहुत सारे अगर-मगर में भी डाल दिया. जिस राज्य में 123 विधायकों से सरकार बनती है, वहां भाजपा के 91 विधायक हो गए हैं. तीन निर्दलीय भी भाजपा समर्थक ही हैं. बिहार में भाजपा की इसी ताक़त के कारण सारे अगर-मगर की शुरुआत होती है. चुनाव परिणाम के बाद ऐसी समझ बनने लगी थी कि भाजपा का जदयू के साथ इस बार गठबंधन लगभग बराबर की हैसियत वाला होगा. पिछले पांच सालों में नीतीश कुमार ने जो एजेंडा तय किया, उसी पर भाजपा चलती रही. भले ही इस कवायद से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बढ़ी, पर गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर सब कुछ सहन किया जाता रहा, लेकिन विधानसभा में बढ़ी ताक़त से अनुमान लगाया जाने लगा कि भाजपा नीतीश कुमार की हर बात अब सिर हिलाकर नहीं मानेगी. मंत्री पदों का कोटा बढ़ाने की मांग रखकर उसने इसकी हल्की झलक भी दी, लेकिन वह अपना यह तेवर ज़्यादा दिनों तक बरक़रार नहीं रख पाई.

भाजपा की बहुप्रचारित तिरंगा यात्रा को ग़ैर ज़रूरी बताकर नीतीश कुमार ने अपने मंसूबे साफ कर दिए. एक तरफ़ जम्मू हवाई अड्डे पर सुषमा स्वराज एवं अरुण जेटली रोके जा रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे थे कि आज के संदर्भ में इस यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं थी. मतलब भाजपा अपने सबसे पुराने एवं सबसे मज़बूत सहयोगी जदयू को अपनी तिरंगा यात्रा का मक़सद ही नहीं समझा पाई. लालकृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए पसीना बहाने में मशगूल थे, पर उनके भरोसे के साथी उसे बेमतलब की कवायद बता रहे थे. स्वाभाविक था कि कुर्सी से बंधे लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, पर दूसरे भाजपाइयों को नीतीश कुमार का यह बयान नागवार गुजरा. वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्र प्रताप ने नीतीश के बयान पर दो टूक कहा कि गठबंधन निभाना केवल भाजपा की ज़िम्मेदारी नहीं है. जदयू में जब दागी तस्लीमुद्दीन को शामिल किया जा रहा था तो क्या भाजपा से पूछा गया था. गठबंधन को भाजपा की कमज़ोरी न समझा जाए. हरेंद्र प्रताप ने अपनी बात ख़त्म भी न की होगी कि जदयू से ज़्यादा भाजपा के नेता ही उन पर बरस पड़े. सी पी ठाकुर एवं सुशील मोदी ने कहा कि हरेंद्र प्रताप को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए थी.

इन दोनों नेताओं द्वारा ऐसा बोलते ही साफ हो गया कि भाजपा ने हमेशा की तरह गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चुप रहने का फ़ैसला किया है. ठीक उसी तरह, जैसे नरेंद्र मोदी प्रकरण पर नीतीश कुमार का रुख़ भाजपा ने आत्मसात कर लिया था. ठीक उसी तरह, जिस तरह खाने का निमंत्रण रद्द होने के बावजूद नितिन गडकरी कहते रहे कि हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए. नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए बिहार नहीं आएंगे और ऐसा ही हुआ. ऐसे कई उदाहरण हैं. किशनगंज की सीट लेने की बात हो या फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने का मामला, हर बार नीतीश कुमार की ही चली. महिला आरक्षण पर भी दोनों दल साथ नहीं दिखाई पड़े. इसके बावजूद दोनों दलों का गठबंधन बदस्तूर जारी है. बड़ी मुश्किल है, कुर्सी के लिए साथ रहना है और देश के लिए सब कुछ क़ुर्बान करने वाली पार्टी की छवि भी बनानी है. भाजपा को यह दोनों काम साथ-साथ करने हैं और कम से कम बिहार में तो वह इन्हें बख़ूबी अंजाम दे रही है. पार्टी की नीति और कार्यक्रम को लेकर जैसे ही जदयू के साथ कोई मतभेद होता है तो एक-दो नेता गरजने लगते हैं, पर अगले ही पल न जाने कितने नेता बेहतर बिहार बनाने एवं जनादेश की दुहाई देकर उन्हें ग़लत ठहरा देते हैं या फिर चुप्पी साध लेने की सलाह दे डालते हैं. बिहार को बचाने की दुहाई देकर अपने ही कार्यक्रम की धार भोथरी करने से भी भाजपाई नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं कि कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती.

ताजा मामले में जदयू सांसद शिवानंद तिवारी ने कहा कि हरेंद्र प्रताप जैसे नेताओं को भाजपा की लाइन तय करने का अधिकार नहीं है. इस तरह का काम अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज के ज़िम्मे है. उल्लेखनीय है कि चुनाव से पहले शिवानंद तिवारी बार-बार भाजपा को लताड़ने में लगे थे और उससे अलग होकर चुनाव लड़ने की बात भी करते रहे. देखा जाए तो नीतीश कुमार की दूसरी पारी में भी संकेत मिलने लगे हैं कि भाजपा हर क़ीमत पर कुर्सी के लिए गठबंधन धर्म निभाएगी, भले ही वह बिहार के विकास के नाम पर हो. दिखावे का विरोध होता रहेगा और यह जताने की कोशिश होगी कि चाल, चरित्र एवं चेहरे के मामले में वह सबसे अलग है और बिहार एवं देश के लिए वह सब कुछ क़ुर्बान करने को तैयार है.

feedback@chauthiduniya.com

असम

मंत्रियों की संपत्ति की घोषणा पर सवाल

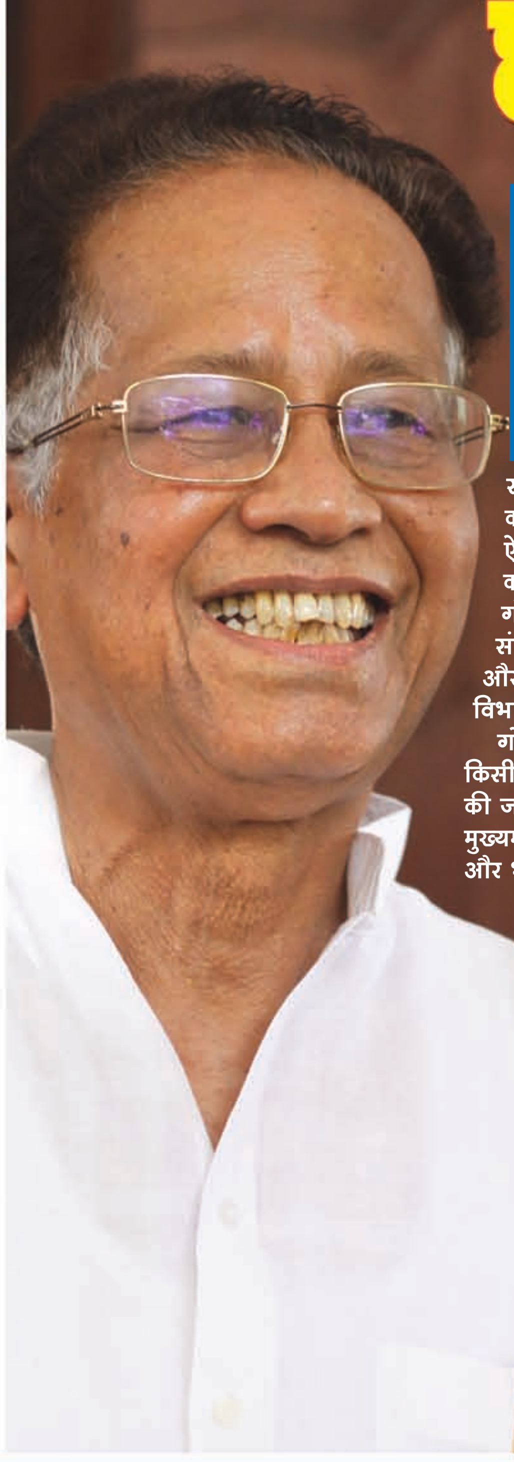

दिनकर कुमार

बीती 14 जनवरी को असम सरकार ने अपनी वेबसाइट पर राज्य के सभी मंत्रियों की संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक कर दिया. काफी समय पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने वादा किया था कि वह और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अपनी-अपनी संपत्ति की घोषणा करेंगे, लेकिन कई बार समय सीमा तय करने के बावजूद ऐसा नहीं हो सका. ऐसा लग रहा था, मानो गोगोई सरकार को संपत्ति की घोषणा करते हुए परेशानी महसूस हो रही है. बीच में एक बार मुख्यमंत्री गोगोई ने मीडिया से यह भी कहा कि राज्य के मंत्रियों को संपत्ति की घोषणा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और जो लोग उनकी संपत्ति का ब्योरा चाहते हैं, उन्हें आयकर विभाग में जाकर पता लगाना चाहिए.

गोगोई के इस कथन का भ्रामक अर्थ निकल रहा था, क्योंकि किसी भी आम नागरिक को आयकर विभाग मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी देने वाला नहीं था. इसका साफ मतलब था कि मुख्यमंत्री इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना चुके थे और भ्रामक बहानों का सहारा लेकर मीडिया को चुप करा देना चाहते थे. एक वकील होने के नाते ऐसी बयानबाज़ी करते समय गोगोई को भी अंदाज़ा रहा होगा कि वह ग़लत दलील पेश कर रहे हैं. लेकिन जब कांग्रेस हाईकमान ने देर से ही सही, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ सख़्त रवैया अपनाने की घोषणा की और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने असम का दौरा करके गोगोई सरकार पर संपत्ति की घोषणा करने का दबाव बनाया तो बेमन से ही सही, गोगोई को संपत्ति की घोषणा करने के लिए सहमत होना पड़ा. आनन-फानन में उन्होंने ऐलान कर दिया कि 15 जनवरी 2011 से पहले मंत्रीगण अपनी संपत्ति की घोषणा कर देंगे. उन्होंने सभी मंत्रियों से संपत्ति का ब्योरा देने के लिए कहा, लेकिन यह सारी प्रक्रिया एक मज़ाक बनकर रह गई. कई तरह के घपलों-घोटालों के आरोपों से घिरे गोगोई मंत्रिमंडल के सदस्यों ने संपत्ति की घोषणा करते समय जानबूझ कर खुद को ग़रीब दिखाने का हास्यास्पद प्रयास किया है.

वेबसाइट पर मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा देते समय जो चालाकी बरती गई है, उसकी वजह से गोगोई सरकार के इरादे और नीयत पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं. मंत्रियों की संपत्ति के ब्योरे ठीक से खुलते नहीं हैं. किसी मंत्री का ब्योरा वेबसाइट पर खुल जाता है तो किसी का बिल्कुल नहीं खुलता. इसके अलावा मंत्रियों ने अपनी पत्नी और बच्चों के नाम की संपत्ति का कोई ब्योरा नहीं दिया है. यह बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़्यादातर मंत्री, विधायक और नौकरशाह अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से संपत्तियां बनाते हैं. असम के मंत्रियों ने इस तरह की किसी भी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है. यही वजह है कि विपक्ष संपत्ति की घोषणा को जनता के साथ छल और गोगोई को झूठा बता रहा है. इतना ही नहीं, संपत्तियों के विवरण में भी कई तरह की विसंगतियां हैं. कहीं भूमि का आकार बताए बग़ैर उसके मूल्य का उल्लेख किया गया है तो कहीं मूल्य का उल्लेख किए बग़ैर भूमि के आकार का उल्लेख है. स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने एक आवास का उल्लेख करते हुए उसकी क़ीमत महज़ 1.05 लाख रुपये घोषित की है, जबकि इस समय गुवाहाटी में ज़मीन की क़ीमत आसमान छू रही है, ऐसे में गोगोई के घर की क़ीमत अविश्वसनीय लग रही है. ब्योरे के झूठ को आसानी से समझा जा सकता है. वर्ष 2006 में चुनाव आयोग को दिए गए संपत्ति के विवरण में मुख्यमंत्री ने अपने उसी घर की क़ीमत 7.5 लाख रुपये बताई थी. एक दूसरे घर की क़ीमत उन्होंने 2006 में चुनाव आयोग को 20.37 लाख रुपये बताई थी, उसी घर की क़ीमत सरकारी वेबसाइट में गोगोई ने 15.98 लाख रुपये बताई है. एक तरफ़ गुवाहाटी में ज़मीन की क़ीमत में कई गुना इज़ाफ़ा देखा जा रहा है, दूसरी तरफ़ गोगोई के घरों की क़ीमत लगातार घटती ही गई.

गोगोई के इस कथन का भ्रामक अर्थ निकल रहा था, क्योंकि किसी भी आम नागरिक को आयकर विभाग मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी देने वाला नहीं था. इसका साफ मतलब था कि मुख्यमंत्री इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना चुके थे और भ्रामक बहानों का सहारा लेकर मीडिया को चुप करा देना चाहते थे. एक वकील होने के नाते ऐसी बयानबाज़ी करते समय गोगोई को भी अंदाज़ा रहा होगा कि वह ग़लत दलील पेश कर रहे हैं.

नई दिल्ली स्थित अपने फ्लैट की कीमत गोगोई ने चुनाव आयोग को 18 लाख रुपये बताई थी. वेबसाइट में उसी फ्लैट की क़ीमत महज 5.89 लाख रुपये बताई गई है. ब्योरे के ज़रिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इस बात में कोई संदेह नहीं है. गोगोई मंत्रिमंडल के कई सदस्य टीवी चैनलों, होटलों और अन्य उद्योगों का संचालन कर रहे हैं, लेकिन संपत्ति की घोषणा करते समय किसी ने भी इस तरह का कोई उल्लेख नहीं किया है. एक भी मंत्री को करोड़पति की श्रेणी में नहीं दर्शाया गया है. आम जनता जिन मंत्रियों की अकूत दौलत, महंगे आवासों और व्यापार के बारे में अच्छी तरह जानती है, उन्हें भी वेबसाइट में दर्शाया नहीं गया. यही वजह है कि राज्य के विपक्षी दल और जन संगठन संपत्ति की घोषणा को तरुण गोगोई सरकार का प्रहसन बता रहे हैं.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

feedback@chauthiduniya.com

तस्करों ने कोसीकलां को भी अपना ठिकाना बना लिया है. यह खुलासा स्टेशन से पकड़ी गई उस महिला के ज़रिए हुआ, जो कछुओं की तस्करी में लिप्त थी.

उत्तर प्रदेश

तस्करों के निशाने पर कछुए

सुरेंद्र अग्निहोत्री

भगवान विष्णु ने भले ही कच्छप अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा की हो, लेकिन पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग अपने स्वार्थों के चलते कछुओं को बड़ी तेज़ी से ख़त्म करते जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कछुओं पर संकट के बादल मड़रा रहे हैं. अगर कछुओं का संरक्षण नहीं किया गया तो वे इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे. चीनी ज्योतिष फेंगशुई में धन का प्रतीक बना कछुआ सिर्फ़ धन की लालसा में ही नहीं, बल्कि ताक़त और स्वाद के कारण विलुप्ति की कगार पर है. जानकारों के अनुसार, कछुए के एक अंग से कामोत्तेजक दवाओं का निर्माण किया जाता है. एक कछुए की क़ीमत क़रीब 3-4 हज़ार रुपये है, जबकि दक्षिण-पूर्वी राज्यों में स्थित प्रयोगशालाओं में इसकी क़ीमत दस-बारह हज़ार रुपये हो जाती है. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में एक कछुए की क़ीमत क़रीब चालीस हज़ार रुपये है.

सूत्रों के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी राज्यों में बनी प्रयोगशालाओं में कछुए के अंग के एक हिस्से से कामोत्तेजक दवाओं का निर्माण होता है. यह दवा विदेशों में हज़ारों रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से बेची जाती है. कछुए को तस्कर सुंदरी के नाम से बुलाते हैं. उसके पीछे के हिस्से को सेला कहते हैं. यह भाग बेहद ताक़तवर और गर्म होता है. कछुआ खासकर आगरा, अलीगढ़ एवं बरेली में नहरों एवं तालाबों में पाया जाता है. ठंड से बचने के लिए ये एक-डेढ़ फीट तक ज़मीन में घुस जाते हैं. जहां कछुए छिपे होते हैं, वह जगह कुछ फूली होती है और शिकारी इसे भांप जाते हैं. वे एक विशेष सूजे से उन्हें दबोच लेते हैं. कछुओं का वास्तु और तंत्र विद्या में जमकर इस्तेमाल किया जाता है. कछुए को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. इस कारण लोगों को भ्रम है कि इसे घर में रखने से धन की वर्षा होगी. कछुए के पंजों एवं नाख़ूनों से दवाएं बनाई जाती हैं. कछुआ मांसाहारी जीव है. यह पानी में रहने वाले जीव-जंतुओं को अपना भोजन बनाता है. इससे जल साफ रहता है. जलचर प्राणियों में कछुए की उम्र सबसे अधिक होती है. यह सौ वर्ष से लेकर 200 वर्ष तक जीवित रहता है. कछुआ जल के किनारे मिट्टी में अपने अंडे देता है. प्राकृतिक आवास की कमी के कारण लगातार प्रजनन के संकट के चलते दुर्लभ श्रेणी में आ चुके कछुओं को यदि समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो नदियों एवं तालाबों का जल पीने लायक नहीं रह जाएगा.

उत्तर प्रदेश में कस्बों से लेकर बड़े नगरों तक तस्कर सक्रिय हैं. इस काम में महिलाओं एवं बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ने अंबेडकर नगर में बीती 15 जनवरी को एक टाटा सूमो पर लदे 17 बोरों से 927 कछुए बरामद किए, जिनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ढाई करोड़ रुपये आंकी गई. पकड़ा गया तस्कर पलाश कुमार दास पश्चिमी बंगाल का निवासी है. इसी तरह अमेठी रेलवे स्टेशन पर 335 कछुओं के साथ इक़बाल नामक तस्कर गिरफ्तार किया गया, जो पिछले 5 वर्षों से मुंबई में अपने ग्राहकों को कछुओं की आपूर्ति कर रहा था. हाथरस जनपद में हसायन थाना पुलिस ने एक युवक को जलेसर से गिरफ्तार किया. उससे बरामद 49 कछुए पुलिस ने वन विभाग को सौंप दिए. पुलिस ने यह बरामदगी जरैरा पुलिस चौकी पर चेकिंग के दौरान की. जलेसर से कछुए दक्षिण भारत के शहरों में सप्लाई किए जाते हैं. पूछताछ के बाद पुलिस ने दबिश देकर मैदान सिंह नामक एक और तस्कर को गिरफ्तार किया. हसायन थानाध्यक्ष ने बताया कि इन कछुओं को मैदान सिंह के पास ले जाया जा रहा था. इसी तरह बदायूं पुलिस ने वन्यजीवों की तस्करी में लिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से दुर्लभ प्रजाति के 12 कछुए बरामद किए गए. बगरैन चौकी प्रभारी विजय सिंह काजला ने बताया कि तस्करों के चार अन्य साथी करीब 90 कछुए लेकर फरार हो गए. गिरफ्तार लोगों ने स्वीकार किया कि वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से कछुओं को पकड़ कर उन्हें बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार में बेचते हैं. चारों बिसौली के रहने वाले हैं और पिछले पांच सालों से इस धंधे से जुड़े हैं. कछुओं के अलावा वे दूसरे दुर्लभ वन्यजीवों जैसे तेंदुआ एवं मोर आदि के मांस और खाल की भी तस्करी करते हैं.

उत्तर प्रदेश में क़स्बों से लेकर बड़े नगरों तक तस्कर सक्रिय हैं. इस काम में महिलाओं एवं बच्चों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. पुलिस ने अंबेडकर नगर में बीती 15 जनवरी को एक टाटा सूमो पर लदे 17 बोरों से 927 कछुए बरामद किए, जिनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में ढाई करोड़ रुपये आंकी गई.

मऊ जनपद में दक्षिण टोला पुलिस ने एक महिला को 30 कछुओं के साथ धर दबोचा. उसे मऊ-आजमगढ़ मार्ग स्थित मतलूपुर मोड़ से पकड़ा गया. बरामद कछुओं की क़ीमत दो लाख रुपये आंकी गई. बहराइच पुलिस ने एक लॉज से अंतरजनपदीय कछुआ तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करके उनके पास से ताबूत में रखे आठ जीवित कछुए बरामद किए. इलाहाबाद ज़िले की फूलपुर पुलिस ने सुरेंद्र, संतोष और संतू नामक तस्करों को 60 कछुओं के साथ धर दबोचा. थाना प्रभारी संतोष अवस्थी ने बताया कि तीनों तस्कर बिहार के सासाराम ज़िले के निवासी हैं. पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाक़ों से कछुए पकड़ कर उन्हें कोलकाता, बिहार एवं उड़ीसा में बेचते हैं. बरामद कछुए इलाहाबाद की विभिन्न झीलों से पकड़े गए थे.

तस्करों ने कोसीकलां को भी अपना ठिकाना बना लिया है. यह खुलासा स्टेशन से पकड़ी गई उस महिला के ज़रिए हुआ, जो कछुओं की तस्करी में लिप्त थी. जीआरपी पुलिस ने उसके पास से क़रीब तीन दर्जन कछुए बरामद किए. मथुरा में यमुना और रजबहों से कछुए पकड़ने वाला गैंग सक्रिय हैं. बीते दिनों हुलवाना में ग्रामीणों ने गैंग के चार सदस्यों को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया, जिनके पास से 40 कछुए बरामद हुए. उधर कानपुर देहात और कन्नौज पुलिस ने सात तस्करों को दबोच कर 1345 कछुए बरामद किए. पुलिस के मुताबिक़, इस गोरखधंधे के पीछे तस्करों का एक बड़ा नेटवर्क है. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जीआरपी ने जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से एक महिला तस्कर को गिरफ्तार करके 456 कछुए बरामद किए. कछुए वन विभाग को सौंप दिए गए. कैराना (मुजफ्फरनगर) पुलिस ने हरियाणा निवासी दो तस्करों को धर दबोचा. उनके पास से पुलिस ने 240 कछुए बरामद हुए. इटावा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने दो महिला तस्करों को 130 कछुओं के साथ गिरफ्तार किया. पश्चिम बंगाल की मूल निवासी इन महिलाओं ने बताया कि वे कई सालों से वन्य जीवों की तस्करी करने वाले कोलकाता के एक अंतर्राज्यीय गिरोह के लिए काम कर रही हैं. पुलिस ने इन महिलाओं के ख़िलाफ़ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. सुल्तानपुर ज़िले में पांच तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके क़ब्ज़े से 40 कछुए बरामद किए गए. पुलिस के अनुसार, ज़िले के धम्मौर इलाक़े में इन तस्करों को उस वक़्त गिरफ्तार किया गया, जब वे कछुओं के साथ कोलकाता जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने के मक़सद से सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे. धम्मौर थाना प्रभारी तेज बहादुर ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी तस्कर स्थानीय निवासी हैं.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंभर प्रसाद निषाद ने कहा कि प्राचीन समय में नदी एवं तालाबों के रखरखाव का कार्य मछुआ समुदाय करता रहा है, लेकिन सरकार ने इस समुदाय से नदी-नालों का अधिकार छीनकर प्राकृतिक असंतुलन पैदा कर दिया है. मछुआ समुदाय सिर्फ़ मछलियों का शिकार करता था, लेकिन अब इस कार्य में दूसरे लोगों द्वारा मछलियों के बहाने कछुओं का शिकार किया जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

इस्लाम में सूदख़ोरी हराम क्यों क़रार दी गई है? इसीलिए कि किसी व्यक्ति पर नाजायज़ आर्थिक बोझ न पड़े.

अब भारत में तालिबानी फ़रमान

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले के सलेमपुर गांव की मुस्लिम पंचायत ने एक ऐसे बुज़ुर्ग दंपत्ति के सामाजिक बहिष्कार का फ़ैसला सुना दिया, जो बेसहारा है और किसी तरह अपना जीवनयापन करता है तथा उसका कुसूर सिर्फ़ इतना है कि वह मदरसे के निर्माण के लिए चंदा दे सकने में असमर्थ है. इस तालिबानी फ़ैसले ने मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग को सकते में डाल दिया है.

ऐसा लगता है कि आजकल इस्लाम को बदनाम करने का ठेका सिर्फ़ मुसलमानों ने ले रखा है. न सिर्फ़ दुनिया के तमाम देशों, बल्कि भारत से भी अक्सर ऐसे समाचार मिलते रहते हैं, जिनसे इस्लाम बदनाम होता है और मुसलमानों का सिर नीचा होता है. कभी बेतुके फ़तवे इस्लामी तौहीन का कारण बनते हैं तो कभी तालिबानी पंचायती फ़रमान. पिछले दिनों ऐसी ही एक शर्मनाक ख़बर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले से मिली, जिसके अनुसार, वहां के सलेमपुर की एक मुस्लिम पंचायत ने गांव के एक बुज़ुर्ग दंपत्ति का सामाजिक बहिष्कार करने की घोषणा की है. बताया जाता है कि लगभग 1000 की मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में मोइनुद्दीन एवं मरियम नामक एक ग़रीब बुज़र्ग दंपत्ति अपने झोपड़ीनुमा कच्चे मकान में रहते हैं और टॉफी, नमक एवं बिस्कुट जैसी सस्ती चीज़ें बेचकर जीवनयापन करते हैं. इनकी ग़रीबी का आलम यह है कि ये अपने चंद मवेशियों के लिए घास-चारा और ईंधन के लिए लकड़ी आदि दूरदराज़ के खेतों से इकट्ठा करते हैं. इनके रहन-सहन से ही इनकी आर्थिक हैसियत का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

इसी गांव के मुसलमानों ने अपनी एक मुस्लिम पंचायत अर्थात अंजुमन बना रखी है. गांव में एक मदरसा निर्माणाधीन है, जिसके लिए स्थानीय एवं बाहरी लोगों से चंदा इकट्ठा किया जा रहा है. अंजुमन द्वारा मोइनुद्दीन एवं मरियम से भी मदरसे के चंदे के रूप में पांच सौ रुपये की मांग की गई. इस ग़रीब दंपत्ति ने अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के मद्देनज़र चंदा देने में असमर्थता व्यक्त कर दी. बस फिर क्या था, मोइनुद्दीन तो इस पंचायत की नज़र में इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया. अंजुमन ने मोइनुद्दीन के सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार की घोषणा कर दी. उसकी ख़स्ताहाल झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया कि गांव का कोई भी व्यक्ति मोइनुद्दीन की दुकान से कोई सामान नहीं ख़रीदेगा, कोई उससे किसी प्रकार का बर्ताव, व्यवहार एवं वास्ता नहीं रखेगा. यदि किसी ने अंजुमन के आदेश का उल्लंघन किया तो उसे 500 रुपये बतौर जुर्माना अदा करने होंगे. तालिबानी फ़रमान का अंत यहीं नहीं हुआ, बल्कि इन तथाकथित इस्लामी ठेकेदारों ने इस दंपत्ति को अपने खेतों में शौच के लिए जाने पर भी पाबंदी लगा दी. यह आदेश भी जारी कर दिया गया कि मरणोपरांत इस परिवार के किसी व्यक्ति को स्थानीय क़ब्रिस्तान में दफन भी नहीं किया जाएगा. पंचायत के फ़रमान के बाद इस परिवार को अपनी दो वक़्त की रोटी जुटा पाने में भी दिक्कत पेश आ रही है. गांव की मुस्लिम पंचायत इसकी बदहाली और भुखमरी पर स्वयं को गौरवांवित महसूस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ़ पड़ोस के एक गांव का सिख परिवार मानवता का प्रदर्शन करते हुए इसे दो वक़्त की रोटी मुहैया करा रहा है.

यह तो था इन तथाकथित इस्लामपरस्तों का तालिबानी फ़रमान, जो इन्होंने यह सोचकर जारी किया कि शायद ये तुगलकी सोच वाले मुसलमान इस्लाम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, परंतु आइए देखें कि इस्लाम दरअसल इन हालात में क्या सीख देता है. मैं अपने बचपन से कुछ इस्लामी शिक्षाएं वास्तविक इस्लामी दानिश्वरों से सुनता आया हूं. ऐसी ही एक इस्लामी तालीम थी कि पहले घर में चिराग़ जलाओ, फिर मस्जिद में. इस कहावत का अर्थ क्या है? यही न कि अपनी पारिवारिक ज़रूरतों से अगर पैसे बचें तो फिर अपने ख़ुदा की राह में ख़र्च करें. यह तो क़तई नहीं कि आप ख़ुद या आपके पड़ोसी भूखे रहें और आप मस्जिद या मदरसे के निर्माण कार्य के लिए चंदा देते फिरें. जो लोग इस्लाम में वाजिब कहे जाने वाले हज के नियम से वाक़िफ़ हैं, वह यह भलीभांति जानते हैं कि अगर आप क़र्ज़दार हैं और हज कर रहे हैं, तो वह भी जायज़ नहीं है. यहां तक कि अगर आप पर अपने बेटों एवं बेटियों की शादी का ज़िम्मा बाक़ी है तो पहले इन पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ही हज किया जा सकता है. अगर आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं तो फिर कभी भी हज कर सकते हैं. इसी तरह लगभग सभी इस्लामी कार्यकलापों के लिए यह बताया गया है कि हमेशा चादर के भीतर ही पैर फैलाना है. यहां तक कि फ़िज़ूलख़र्ची को भी इस्लाम में गुनाह क़रार दिया गया है. अपने को आर्थिक परेशानी में डालकर धर्म पर पैसे ख़र्च करना इस्लाम हरगिज़ नहीं सिखाता. मगर तालिबानी सोच रखने वाले कुछ मुसलमानों ने अपने गढ़े हुए इस्लाम के अंतर्गत फ़रमान जारी करके दो ग़रीब मुसलमानों को रोजी-रोटी से वंचित कर दिया. वहीं एक सिख परिवार वास्तविक मानवीय इस्लामी एवं सिख धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हुए इन्हें दो वक़्त की रोटी मुहैया कराता रहा. क्या यही है इन तालिबानों का इस्लाम? क्या ऐसे फ़रमान इस्लाम धर्म की वास्तविक शिक्षाओं के अंतर्गत जारी किए जाने वाले फ़रमान कहे जा सकते हैं?

यह ग़ैर इस्लामी फ़रमान जारी करने के बाद पंचायत के प्रमुख का कहना था कि यह परिवार नमाज़ नहीं पढ़ता, हमारे चंदे में, ख़ुशी और गम में, हमारे धार्मिक कामों में शरीक नहीं होता, लिहाज़ा गांव के लोग इससे अपना वास्ता क्यों रखें? सवाल यह है कि मान लिया जाए कि वह परिवार यदि किसी धार्मिक आयोजन या नमाज़-रोज़े में उनके साथ शरीक नहीं होता तो भी किसी को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उसके विरुद्ध कोई ऐसा फ़रमान जारी करे. किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों में शिरकत करना या न करना किसी भी व्यक्ति का अति व्यक्तिगत मामला है. यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्यकलापों में हिस्सा लेता है तो वह उसके पुण्य का भागीदार होगा. इसी प्रकार शरीक न होने अथवा नमाज़ आदि अदा न करने पर पाप का भागीदार भी सिर्फ़ वही होगा. धर्म प्रचारक या मुल्ला-मौलवी उसे अपनी बात प्यार-मोहब्बत से समझा सकते हैं, लेकिन उसका सामाजिक बहिष्कार करना, उसे आर्थिक संकट में डालना या उसके विरुद्ध कोई तालिबानी फ़रमान जारी करना पूरी तरह ग़ैर इस्लामी, ग़ैर इंसानी और अधार्मिक है.

दरअसल आज ऐसे तालिबानी सोच रखने वाले मुसलमानों एवं कठमुल्लाओं ने इस्लाम धर्म को बदनाम कर दिया है. चाहे वह अफ़ग़ानिस्तान के बामियान प्रांत में महात्मा बुद्ध जैसे विश्व शांति के दूत समझे जाने वाले महापुरुष की मूर्ति को तोप के गोलों से ध्वस्त करने जैसी कायरतापूर्ण कार्रवाई हो या पाकिस्तान में मस्जिदों, दरगाहों एवं धार्मिक जुलूसों में शिरकत करने वाले शांतिप्रिय लोगों की बड़ी संख्या में जान लेना या भारत में कभी बेतुके फ़तवे जारी करना, सलेमपुर गांव जैसा फ़रमान सुनाया जाना आदि कृत्य शर्मनाक, इस्लाम विरोधी और मानवता विरोधी ही नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने वाले भी हैं. यह कैसी विडंबना है कि उस गांव के तथाकथित मुसलमान एक मुस्लिम परिवार को भूखा-परेशान देखकर ख़ुश हो रहे हैं, जबकि एक सिख परिवार उस परेशानहाल मुस्लिम परिवार की भूख और परेशानियां सहन नहीं कर पा रहा और यथासंभव मदद कर रहा है. क्या संदेश देती हैं हमें ऐसी घटनाएं? क्या ऐसे फ़रमानों से इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है? यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जिस मदरसे की बुनियाद में ऐसे तालिबानी फ़रमान शामिल हों, उन मदरसों से भविष्य में निकलने वाले बच्चों की मज़हबी तालीम क्या हो सकती है और आगे चलकर वही तालीम क्या गुल खिलाएगी, इस बात का बड़ी सहजता से अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इन कट्टरपंथी तालिबानी सोच के मुसलमानों को उस सिख परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो उनके द्वारा भुखमरी की कगार पर पहुंचाए गए मुस्लिम परिवार को रोटी मुहैया करा रहा है. आज भी देश में हज़ारों ऐसी मिसालें मिलेंगी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम एवं सिख समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं. कहीं हिंदू नमाज़ पढ़ते हैं, कहीं रोज़ा रखते हैं, कहीं मोहर्रम में ताज़ियादारी करते हैं तो कहीं पीरों-फ़कीरों की दरगाहों की मुहाफ़िज़त करते हैं. इन ग़ैर मुस्लिमों का इस्लामी गतिविधियों की ओर झुकाव की वजह सिर्फ़ उदारवादी इस्लामी शिक्षाएं हैं, न कि कट्टरपंथी तालिबानी फ़रमान.

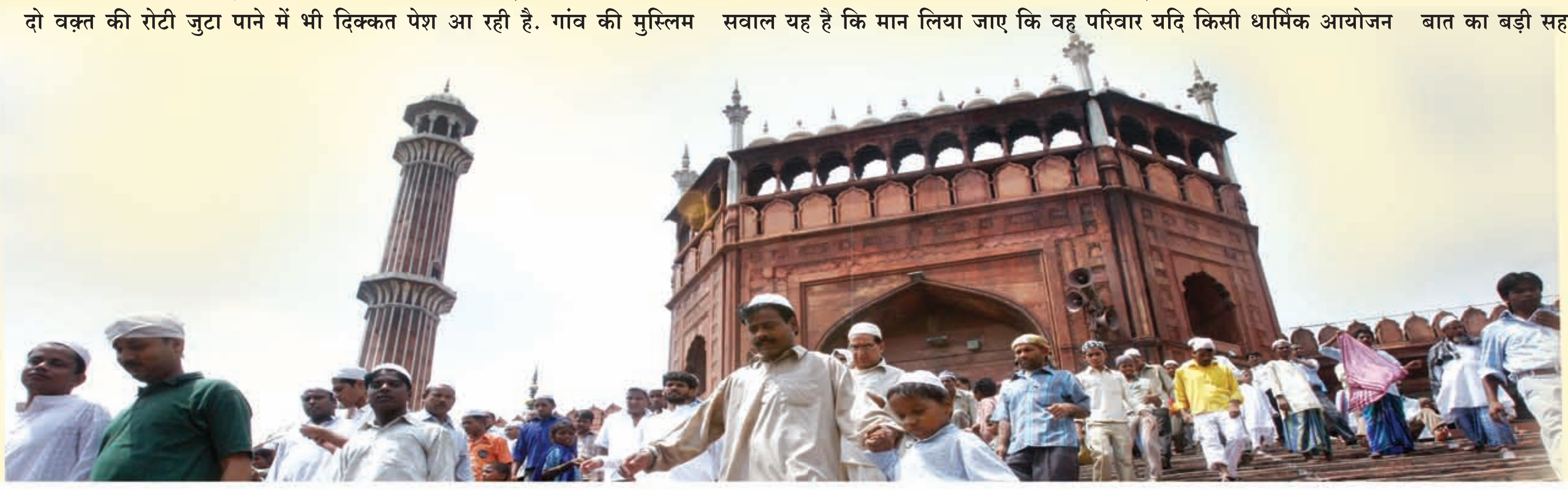

सलेमपुर की घटना से एक बात और ज़ाहिर होती है कि जब इन मुसलमानों का रवैया अपने ही समुदाय के एक परिवार के साथ ऐसा है तो फिर दूसरे समुदाय के प्रति इनसे प्रेम-सद्भाव से पेश आने की उम्मीद कैसी की जा सकती है. प्रभावित परिवार आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि बुज़ुर्ग महिला मरियम ने यहां तक कह दिया कि अब हम इनके आगे न झुक सकते हैं, न कुछ मांग सकते हैं, बल्कि हमें ग़ैर मुस्लिमों के आगे झुकने और उनसे मांगने में कोई हर्ज नहीं है. कितना बेहतर होता, यदि यही पंचायत अथवा अंजुमन ग़रीबों को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी रोज़ी-रोटी और शिक्षा आदि सुनिश्चित करने को तवज्जो देती. बजाय इसके वह लोगों से ज़ोर-ज़बरदस्ती करके चंदा वसूलने और न देने पर उनका सामाजिक-आर्थिक बहिष्कार करने जैसा अधार्मिक कृत्य अंजाम दे रही है. ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अज्ञानी कठमुल्लाओं से इस्लाम धर्म को कलंकित होने से बचाया जाए. क्या ऐसे तुगलकी और तालिबानी फरमान ग़ैर मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे, जिनसे मुस्लिम समुदाय का ही कोई परिवार रुसवा और बेज़ार हो जाए. जो इस्लाम सभी धर्मों एवं समुदायों, यहां तक कि पेड़-पौधों के साथ भी मानवता और सद्भाव से पेश आने की बात करता हो, वह किसी को भूखे रहने के लिए मजबूर करने की तालीम कैसे दे सकता है. इस्लाम में सूदख़ोरी हराम क्यों क़रार दी गई है? इसीलिए कि किसी व्यक्ति पर नाजायज़ आर्थिक बोझ न पड़े. इस्लाम में दिनोंदिन बढ़ती जा रही ऐसे लोगों की घुसपैठ रोकनी होगी. ऐसे फ़रमान जारी करने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है, जैसा सलेमपुर के उस ग़रीब दंपत्ति के साथ वहां की अंजुमन ने किया. यह ग़ैर इस्लामी और अमानवीय है, इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए, कम है.

तनवीर जाफरी
feedback@chauthiduniya.com

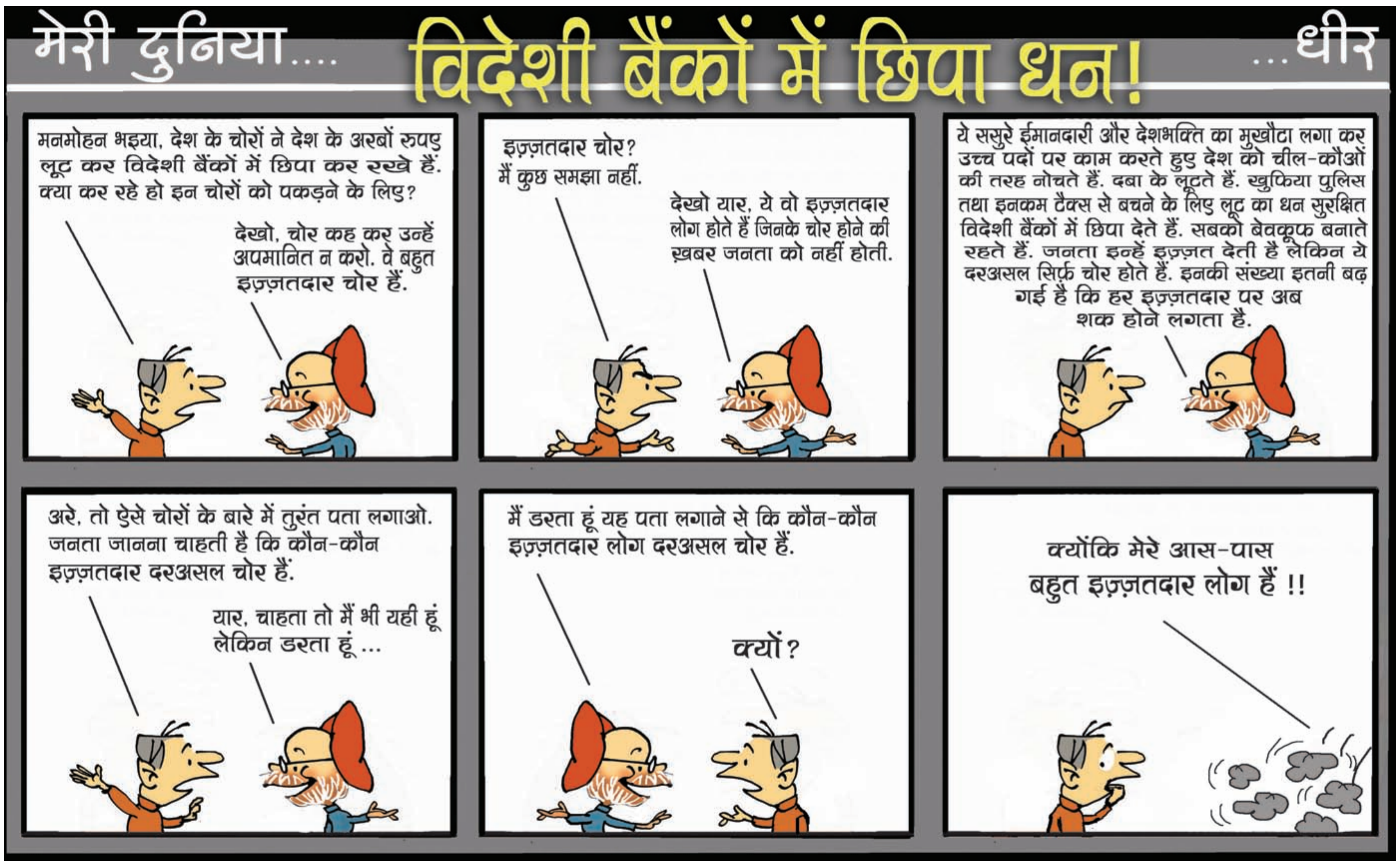

मुस्कराएं, आप बख़्तावरपुरा में हैं

- 10 साल पहले गांव हर वक़्त कीचड़ से भरा रहता था
- आज एक बूंद पानी सड़क-नाली में व्यर्थ नहीं बहता
- बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए कई कुएं बनाए गए
- गांव अब कीचड़मुक्त हो गया है, मच्छर भी नहीं हैं
- बस स्टैंड का मुद्दा-डिज़ाइन तक लोगों ने बैठक में तय किया

ग्रामसभा की नियमित बैठक से किसी गांव का विकास कितना संभव है? इस सवाल का जवाब जानना हो तो आप राजस्थान का बख़्तावरपुरा गांव देख आइए. इस गांव ने व्यवस्था में बैठे लोगों को बाध्य किया कि वह ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार चलना शुरू करें. निष्क्रिय ग्रामसभा को ज़िंदा कर गांव वालों ने तंत्र से जुड़े लोगों को भी इसमें शामिल किया. आज यह गांव पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया है.

शशि शेखर

ग्रामसभाओं की निष्क्रियता के कारण सरकारी पंचायतों में काफी भ्रष्टाचार है. ग्रामसभा के नाम पर कुछ लोगों के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं और खानापूर्ति हो जाती है. वास्तविक ग्रामसभा बैठती ही नहीं है. लेकिन देश के कुछ ऐसे गांव हैं, जो इस स्थिति को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं. वे पंचायत के प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामसभा को मज़बूत बनाया जा सके, ताकि सरकारी प्रस्तावों की ठीक-ठीक समीक्षा हो और अनुचित प्रस्ताव पारित न हो सकें. नतीजतन, इन प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे हैं. अब पंचायतों के जन प्रतिनिधि एवं कर्मचारी भ्रष्टाचार कर पाने में ख़ुद को असमर्थ पा रहे हैं. ज़ाहिर है, देश के अन्य हिस्सों में भी ग्रामसभा के सशक्तिकरण से पंचायत व्यवस्था आसानी से भ्रष्टाचार मुक्त बनाई जा सकती है.

दिल्ली-झुंझनू मार्ग पर, झुंझनू से क़रीब 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाला एक गांव. यहां की साफ-सफाई और चमचमाती सड़क बरबस ही इधर से गुजरने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचती है. रास्ते में एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, मुस्कराइए कि आप राजस्थान के गौरव बख्तावरपुरा गांव से गुज़र रहे हैं. ज़ाहिर है, ऐसा देख-पढ़कर सहज ही किसी का भी ध्यान इस ओर खिंच सकता है. इसलिए भी कि इस तरह के बोर्ड अमूमन बड़े-बड़े शहरों में तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक गांव में ऐसा बोर्ड देखकर आश्चर्य लाज़िमी है. गांव के अंदर जाकर देखने और गांव वालों से बात करने पर पता चलता है कि इस गांव में आज पानी की एक बूंद भी सड़क पर या नाली में व्यर्थ नहीं बहती. घरों से निकलने वाले पानी की एक-एक बूंद ज़मीन में रिचार्ज कर दी जाती है. इसके लिए लगभग हर दो-तीन घरों के सामने सड़क के नीचे पानी को ज़मीन में रिचार्ज करने वाली सोख्ता कुइंया बना दी गई हैं. गांव में कई बड़े कुएं भी बने हैं, जहां बारिश के पानी की एक-एक बूंद इकट्ठा की जाती है. सरपंच महेंद्र कटेवा बताते हैं कि गांव की ज़रूरतों के लिए हर रोज़ साढ़े चार लाख लीटर पानी ज़मीन से निकाला जाता है, लेकिन इसमें से क़रीब 95 फ़ीसदी वापस उसी दिन रिचार्ज कर दिया जाता है. पानी की कमी से जूझ रहे राजस्थान के गांवों के लिए यह एक बड़ी बात है. दरअसल, यह गांव जल संरक्षण की दिशा में जिस तरह काम कर रहा है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. राजस्थान जैसी जगह के लिए तो इस गांव का सफल प्रयोग और भी प्रेरक है.

क़रीब 10 साल पहले तक यहां गांव के अंदर ही नहीं, मुख्य सड़क पर भी घरों से निकलने वाला पानी भरा रहता था और हर वक़्त कीचड़ बना रहता था. सरपंच महेंद्र कटेवा और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर अपने घरों का पानी ज़मीन में रिचार्ज करना शुरू किया. इसके लिए उन्होंने घर के सामने सड़क के नीचे 30 फीट गहरी और तीन फीट चौड़ी कुइंया बनाकर उसे ऊपर से बंद कर दिया. इसमें उन्हें तो सफलता मिली, लेकिन गांव के बाकी लोगों ने इसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और चार-पांच घरों का पानी रुकने से कीचड़ की स्थिति पर कोई फ़र्क़ पड़ने वाला नहीं था. तब सरपंच ने ग्रामसभा की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की. इसके फ़ायदे सुनकर गांव के कुछ और लोगों ने भी अपने घरों के सामने ऐसे ही सोख्ता पिट बनवा लिए. इससे सरपंच को लगा कि जो बात गांव वालों को अलग-अलग नहीं समझाई जा सकती, वह एक साथ बैठक में समझाई जा सकती है. इसके बाद तो गांव में हर महीने क़रीब-क़रीब दो ग्रामसभाएं होने लगीं. क़ानूनन राजस्थान में हर महीने की 5 व 20 तारीख़ को ग्राम पंचायत की बैठक होनी ज़रूरी है, जो अगर कहीं होती भी है तो सिर्फ़ पंचायत सदस्यों के लिए ही. लेकिन बख्तावरपुरा में इस बैठक में गांव के लोगों को बुलाया जाने लगा और धीरे-धीरे गांव में हर महीने दो बैठकें होने लगीं, जहां गांव वाले एक निश्चित तारीख़ को अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं.

इन बैठकों से गांव के विकास का रास्ता निकला. धीरे-धीरे पूरा गांव न सिर्फ़ कीचड़मुक्त हो गया, बल्कि लोग साफ-सफाई भी रखने लगे. इसका फ़ायदा यह हुआ है कि गांव में अब मच्छर नहीं हैं. मच्छर न होने से बीमारियां कम हो गई हैं. कटेवा बताते हैं कि इन बैठकों में लिए गए फ़ैसलों को लोग अपने धर्म की तरह मानते हैं. अगर निर्णय सामूहिक न होते तो यह काम होता ही नहीं. अगर होता, कोई कर भी लेता तो फेल हो जाता. अगर वाटर रिचार्ज सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी आती है तो गांव का हर व्यक्ति उसे सुधारने के प्रति तत्पर रहता है और वह आकर मुझे बताता है कि आज फलां नाली में गड़बड़ी हो गई थी, कचरा आ गया था तो हमने दो आदमियों को भेज दिया और नाली ठीक चल रही है. साफ-सफाई के रूप में मिली सफलता ने गांव वालों को अपने गांव से जोड़ दिया. वे गांव में होने वाले हर छोटे-बड़े काम में अपनी राय रखते हैं और उनकी बात मानी भी जाती है. इसका एक उदाहरण गांव में मुख्य सड़क पर बना बस स्टैंड है. इसमें पंखे लगे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है. इस बस स्टैंड का डिज़ाइन तक गांव के लोगों की बैठक में तय हुआ. सरकार की ओर से इसके रंग-रोगन के लिए चूना-पुताई के पैसे आते हैं, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि वे इस पर पेंट कराएंगे. इस पर अधिकारियों ने आपत्ति की, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक न चलने दी और आज इस बस स्टैंड की सुंदरता भी यहां से गुजरने वाले लोगों को एहसास कराती है कि वे किसी खास गांव से गुजर रहे हैं.

इसी सड़क पर रात को रोशनी के लिए सोलर लाइट लगाई गई हैं. महेंद्र सिंह कटेवा बताते हैं, इन्हें गांव वालों ने ही स्थान तय करके लगवाया है और आज इनकी बैटरियों-बल्बों की रक्षा के लिए ख़ुद गांव वाले आते-जाते सतर्क रहते हैं. अगर इन्हें बिना ग्रामसभा में बातचीत किए लगाया गया होता तो इनका नामोनिशान भी यहां नहीं होता. और इसका एक मंत्र है, सरपंच का यह मानना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता. ग्रामसभा की बैठकों में लोगों की बातें सुनी जाती हैं और उन पर अमल होता है. इसका फ़ायदा यह हुआ है कि गांव के विकास के लिए होने वाले हर काम को लोग अपना काम मानते हैं. ग्रामसभा यदि नियमित रूप से हो और पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में गांव के लोगों को शामिल किया जाए तो किसी पंचायत या गांव का संपूर्ण विकास होने से कोई नहीं रोक सकता. यहां तक कि एक भ्रष्ट व्यवस्था या भ्रष्ट अधिकारी भी नहीं. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ग्रामसभा में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, ग़रीब-अमीर या किसान-मजदूर जैसा कोई भेदभाव न किया जाए. आदर्श स्थिति यह है कि पंचायतें ग्रामसभा द्वारा दिए गए अधिकारों के सहारे ही काम करें. प्रधान के लिए वे निर्णय बाध्यकारी हों, जो ग्रामसभा द्वारा लिए गए हों, साथ ही ग्रामसभा को एक परिवार के रूप में विकसित किया जाए.

वर्तमान परिस्थितियों में समाज सशक्तिकरण के लिए लोक स्वराज और उसके लिए ग्रामसभा सशक्तिकरण ही एक मार्ग दिखता है. ऐसे में देश की बाकी पंचायतों के लिए बख्तावरपुरा एक मिसाल है. ऐसा नहीं है कि देश की बाक़ी पंचायतों का विकास इस गांव जैसा न हो. रास्ता भी सिर्फ़ यही है. राजनीतिक दलों और नेताओं के भरोसे बैठकर आख़िर कब तक इंतज़ार किया जा सकता है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

दिल्ली-झुंझनू मार्ग पर, झुंझनू से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाला एक गांव. यहां की साफ-सफाई और चमचमाती सड़क बरबस ही इधर से गुज़रने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचती है. रास्ते में एक बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है, मुस्कराइए कि आप राजस्थान के गौरव बख़्तावरपुरा गांव से गुज़र रहे हैं. ज़ाहिर है, ऐसा देख-पढ़कर सहज ही किसी का भी ध्यान इस ओर खिंच सकता है.

भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव विहारों में दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत के हिमालय की तराई में आबाद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं.

करकरे के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आतंकी हमलों की जांच सही दिशा में होने लगी. इंद्रेश कुमार जैसे आरएसएस नेता एवं विहिप के स्वामी असीमानंद जांच के घेरे में आ गए.

मेघनाद देसाई

ब्रिटिश संसद से कुछ सीखें

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अध्यक्ष हेलेन हेयमैन से मिलने पहुंचीं. मीरा कुमार यह आशा कर रही थीं कि हेयमैन से मिलने के दौरान एक भोज का आयोजन होगा और लॉर्ड्स अध्यक्ष उनके साथ ख़ूब सारा समय बिताएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जैसे ही लंच के लिए भोजन परोसा जाने लगा, हेयमैन ने अपना औपचारिक वस्त्र पहना और क्षमा मांगते हुए कहा कि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंतिम सत्र के लिए जाना है. यह सत्र सोमवार के दिन दोपहर दो बजकर तीस मिनट पर शुरू हुआ था, लगातार सारी रात चलता रहा और आज वह सत्र ख़त्म हो रहा था. हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कैलेंडर के मुताबिक़, यह दिन अभी भी सोमवार ही था. सत्र के अंत में हेयमैन को उपस्थित रहना ही था, क्योंकि वह सत्र के प्रारंभ में भी उपस्थित थीं. उन्होंने पहले सत्र में भाग लिया, फिर लंच के लिए गईं. लंच ख़त्म करने के बाद हेयमैन को तुरंत वापस होना था, क्योंकि उन्हें मंगलवार को होने वाले सत्र में शामिल होना था, जो दो बजकर तीस मिनट पर शुरू होने वाला था.

हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ताधारी दल के ख़िलाफ़ विपक्ष समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. भारत में तो विपक्षी दल इस तरह हताश हैं कि वे संसद की कार्यवाही तक ठप्प कर देते हैं. लंदन में हम किसी विषय को थोड़ा इसलिए खींचते हैं, ताकि सरकार के धैर्य की परीक्षा ली जा सके.

मीरा कुमार के लिए यह एक अजीब अनुभव था. जहां भारत में विपक्ष अपनी सारी ताक़त संसद की कार्यवाही ठप्प करने में लगा देता है, वहीं ब्रिटेन में विपक्ष सारी-सारी रात काम करके सरकार के लिए मुसीबत खड़ा कर देता है. हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक ऐसा सदन है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स की ओर से भेजे गए किसी भी विधेयक की बहुत ही सावधानीपूर्वक जांच करता है. हर विधेयक को दोबारा पढ़ा जाता है, कमेटी उसकी जांच करती है. एक बार फिर यानी तीसरी बार उस बिल को पढ़ा जाता है. अंत में दोनों सदनों को उस विधेयक के लिए सुझाए गए संशोधनों पर सहमत होना पड़ता है. ब्रिटिश संसद का सबसे खास गुण है समय सीमा का पालन. जिस विधेयक की हम बात कर रहे हैं, उसे दोनों सदनों से 15 फरवरी तक पारित हो जाना है. हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष को अनुशासन में रखने का काम अध्यक्ष करते हैं, जो यह तय करते हैं कि किन संशोधनों पर बहस की जा सकती है और इसका फ़ायदा यह होता है कि बहस बेवजह लंबी खिंचने से बच जाती है. हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक स्व-नियंत्रित, स्व-शासित संस्था है, जहां अध्यक्ष के पास किसी बहस को काटने-छांटने का अधिकार नहीं है. सदस्य किसी भी संशोधन पर बहस के लिए कह सकते हैं और उस पर मतदान के लिए भी कह सकते हैं.

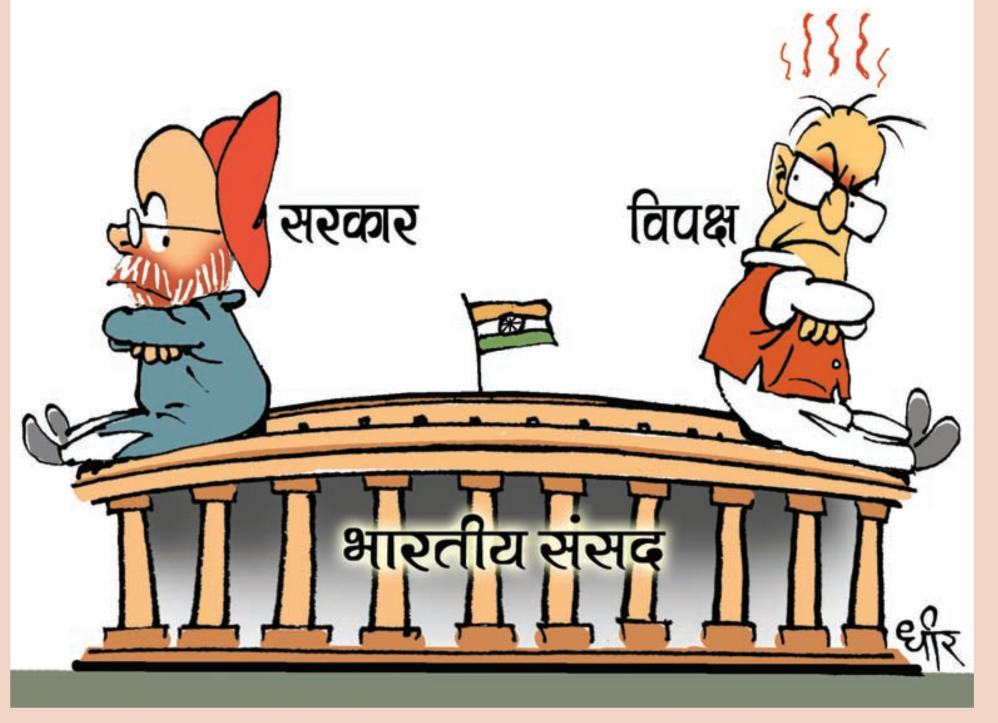

अभी जिस विधेयक पर बहस हो रही है, वह असल में मतदान प्रक्रिया पर जनता का मत जानने को लेकर है. लिबरल डेमोक्रेट्स लंबे समय से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर जोर देते रहे हैं. जनमत के लिए 5 मई का दिन तय किया गया है. लेकिन इस विधेयक का एक और पहलू भी है. इसमें टोरी प्लान की बात शामिल है, जिसके मुताबिक़ हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यों की वर्तमान संख्या 650 को घटाकर 600 करने की योजना है. ऐसा इसलिए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भिन्नता है. लेबर पार्टी छोटे निर्वाचन क्षेत्रों से चुनकर आ जाती है, जबकि टोरीज को जीतने के लिए ज़्यादा वोटों की ज़रूरत पड़ती है. यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक मुद्दा है. विपक्षी लेबर पार्टी ने इस पर कई सारे संशोधन सुझाए हैं और उन पर बड़े आराम से बहस चल रही है. यही वजह है कि यह सत्र रात में भी चल रहा है. सदस्यगण बारी-बारी से सोते हैं और अलग-अलग समय पर बहस में भाग लेते हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे सदन में भी थोड़ी कटुता देखने को मिल रही है. फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नियम के मुताबिक़ विघ्न पैदा करने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाता.

हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ताधारी दल के ख़िलाफ़ विपक्ष समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. भारत में तो विपक्षी दल इस तरह हताश हैं कि वे संसद की कार्यवाही तक ठप्प कर देते हैं. लंदन में हम किसी विषय को थोड़ा इसलिए खींचते हैं, ताकि सरकार के धैर्य की परीक्षा ली जा सके. दोनों ही हालत में सत्ताधारी गठबंधन विपक्ष के ग़लत व्यवहार को दोष देता है. यदि हम सब एक सभ्य तरीक़े से व्यवहार करें और बहुमत ध्यान से अल्पमत की बात सुने तो राजनीति अपने आप एक सभ्य रूप अख्तियार कर लेगी. वेस्टमिंस्टर शैली की राजनीति विरोधात्मक होती है. थोड़ी-बहुत लड़ाई लोकतंत्र के लिए अच्छी भी मानी जाती है. तानाशाही में निर्णय बिना किसी परेशानी के ले लिए जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र हमें यह समझने का मौक़ा देता है कि जो भी निर्णय लिए गए, उन सब में हमारी भी सहभागिता थी.

feedback@chauthiduniya.com

भारत की वन नीति में बदलाव आवश्यक

आज़ादी के बाद बनी भारतीय वन नीति की समीक्षा 1988 में की गई थी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसमें हेरफेर किए बिना यथावत उसे लागू कर दिया गया, जबकि 1975 में नेपाल द्वारा अपनाई गई वन नीति का भारतीय वनों पर प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों का विपरीत प्रभाव पड़ा है. बावजूद इसके पैंतीस साल व्यतीत हो जाने के बाद भी भारतीय वनों पर पड़ रहे कुप्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए भारत सरकार द्वारा अभी तक कोई ठोस वन नीति नहीं तैयार की गई है. जबकि भारत-नेपाल सीमावर्ती भारतीय वनों पर नेपालियों के बढ़ रहे दबाव को रोकने, वन संपदा एवं जैव विविधता की सुरक्षा के लिए वर्तमान वन नीति में बदलाव किया जाना अति आवश्यक हो गया है.

भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव विहारों में दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत के हिमालय की तराई में आबाद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं. देश के वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी के बाद 1952 में पहली वन नीति बनी थी. इसके बाद बदलते परिवेश और समय की मांग के अनुरूप 1978 में दूसरी वन नीति बनी, जो आज तक लागू है. विडंबना यह है कि इस वन नीति में नेपाल की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण जैव विविधता के संरक्षण एवं वनों की सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि मित्र राष्ट्र नेपाल से भारत की लगभग 1400 किमी लंबी सीमा सटी हुई है. 1975 से पूर्व भारत-नेपाल सीमा के दोनों ओर घने वनक्षेत्र स्थित थे, जिनमें दोनों ओर से वन्यजीवों का आवागमन निर्बाध रूप से होता था. उत्तर भारत में हिमालय की तराई में फैले अधिकांश वनक्षेत्रों की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग ज़िले से लेकर पश्चिम में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ तक स्थित है. पिथौरागढ़ में काली नदी के दोनों तरफ़ नेपाल का इलाक़ा एवं भारत का धारचूला क़स्बा आबाद है. आवागमन की दृष्टि से दुर्गम होने के बावजूद यह क्षेत्र तिब्बत में पाए जाने वाले चीरू नामक हिरन के बालों से बने शाहतूस शालों की तस्करी के लिए विख्यात है. अपनी अति विशेष खासियत के कारण उच्च वर्ग में इन शाहतूस शालों की खासी मांग बनी रहती है. यही कारण है कि अधिकांश वन्यजीव तस्कर बाघ, तेंदुआ आदि के अंगों के बदले शाहतूस शाल हासिल करके उसका व्यापार करते हैं.

ग़ौरतलब है कि 1975 में नेपाल द्वारा अपनाई गई सरपट वन कटान नीति के कारण हिमालय की तराई के वनाच्छादित भू-भाग से सटे नेपाल के इलाक़ों से वनों का सफाया हो गया. नेपाल सरकार ने एक सुनियोजित नीति के तहत इन क्षेत्रों में सेवानिवृत्त नेपाली सैनिकों को बसा दिया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय सीमा पर मज़बूत नेपाली नागरिकों की सामाजिक फौज की स्थापना था. खाली हुई वनभूमि पर आबाद हुए नेपाली फौजियों को नेपाल सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर असलहों के लाइसेंस भी प्रदान किए गए. हालांकि कालांतर में नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारों की स्थिति आयाराम-गयाराम की रही, जिससे इन क्षेत्रों में आबाद हुए गांव माओवादियों के गढ़ बन गए, जो अब भी नेपाल सरकार के लिए समस्या का कारण बने हुए हैं. यद्यपि यह मामला नेपाल सरकार का है कि वह माओवादियों से कैसे निपटती है, लेकिन उसकी सरपट वन कटान नीति का भारतीय वनों पर अच्छा-खासा भारी विपरीत प्रभाव पड़ा है. नेपाल की ओर से वन के कट जाने के कारण भारतीय क्षेत्र में स्थित प्रमुख जैवविविध क्षेत्र में जल प्लावन एवं गाद (सिल्टिंग) जमा होने की समस्या बढ़ने लगी और सीमावर्ती वनक्षेत्र सूख गए. जंगल के घास मैदानों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा, मानवजनित कारणों से वनों की सुरक्षा भी प्रभावित हुई. इसके अतिरिक्त पिछले तीन-चार सालों से नेपाल से सटे भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ का कहर भी बढ़ने लगा है. यह भी सर्वविदित है कि नेपाल, चीन, कोरिया एवं ताईवान आदि कई देश वन्यजीव-जंतु उत्पाद के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र हैं, जहां बड़ी मात्रा में ऊंचे दामों पर वन्यजीव उत्पादों की ख़रीद-फरोख्त होती है. उनके लिए कच्चा माल हिमालय एवं उसकी तराई में बसे जैव विविधता क्षेत्रों में उपलब्ध है. उक्त देश वन्यजीव एवं उनसे निर्मित सामग्री का आयात-निर्यात करने वालों की भूमिका अदा करते हैं. वहीं से सारा सामान विश्व बाज़ार में प्रवेश करता है, जहां प्रतिवर्ष 2-5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है. वन्यजीवों के अंगों का यह अवैध कारोबार नारकोटिक्स के बाद दूसरे नंबर पर आता है. इस स्थिति की गंभीरता का अनुमान नेपाल को पहले ही हो गया था, शायद इसी का परिणाम है कि नेपाल सरकार ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व सेना को

भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव विहारों में दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत के हिमालय की तराई में आबाद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव विहार सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हैं. देश के वनों की सुरक्षा के लिए आज़ादी के बाद 1952 में पहली वन नीति बनी थी. इसके बाद बदलते परिवेश और समय की मांग के अनुरूप 1978 में दूसरी वन नीति बनी, जो आज तक लागू है.

सौंप दिया था. परिणाम यह निकला कि नेपाली सैनिकों के दबाव के कारण वन्यजीव तस्कर भारत, श्रीलंका, म्यांमार एवं मलेशिया जैसे देशों में सक्रिय हो गए. हाल में यहां पकड़े गए वन्यजीव अंगों के तस्कर भी अपने बयानों में स्वीकार कर चुके हैं कि नेपाल के प्रमुख बाज़ारों में निर्बाध रूप से वन्यजीवों के उत्पादों की तस्करी जारी है और नेपाल में एकत्र होने के बाद वन्यजीवों के अंग तिब्बत, चीन एवं कोरिया पहुंच कर ऊंचे दामों पर बिकते हैं. इससे यह स्पष्ट हो जाता है अपनी वन संपदा एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नेपाल ने यथोचित प्रबंध कर रखा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तस्करी पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है.

नेपाल द्वारा सरपट वन कटान नीति के अंतर्गत वृहद पैमाने पर किए गए वन कटान का भारतीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या प्रभाव पड़ा, अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है. इतना ही नहीं, उपरोक्त नीति के कारण भारतीय वन क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए भी कोई विशेष नीति भारत सरकार द्वारा नहीं अपनाई गई है. ऐसा प्रतीत होता है कि इस गंभीर स्थिति का मूल्यांकन किए बग़ैर इसे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है. यदि पूर्व में पश्चिम बंगाल से पश्चिम में उत्तराखंड तक फैले महानंदा वन्यजीव विहार, मानस वन्यजीव विहार, बुक्सा टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सोहागीबरवा वन्यजीव प्रभाग, सुहेलदेव वन्यजीव प्रभाग, कतर्निया घाट वन्यजीव प्रभाग, दुधवा टाइगर रिजर्व, किशनपुर वन्यजीव विहार एवं पीलीभीत के लग्गा-भग्गा वनक्षेत्र की स्थिति को देखा जाए तो ज्ञात होता है कि भारतीय सीमा की ओर नियंत्रण एवं संरक्षण की यथोचित व्यवस्था है, परंतु नेपाल की तरफ़ इन क्षेत्रों में पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को न्यूनतम स्तर पर ले जाने के लिए वनकर्मी खुद को असहज महसूस करते हैं. भारतीय वनों पर नेपाली नागरिकों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. वन्यजीवों का अवैध शिकार हो अथवा पेड़ों को काटना हो, नेपाली नागरिक इसमें जरा भी कोताही नहीं बरतते. स्थानीय स्तर के प्रबंध को यदि नज़रअंदाज कर दिया जाए तो पैंतीस वर्ष के बाद भी हमारे देश की वन नीति में उपरोक्त कुप्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए कोई उपाय किया गया है और न नई वन नीति तैयार की गई तथा भविष्य में भी ऐसी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती. लेकिन बदलते परिवेश में अब यह आवश्यक हो गया है कि हिमालय एवं उसकी तराई में नेपाल की सीमा पर भारतीय जैव विविधता क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु एक व्यवहारिक एवं ठोस वन नीति बनाई जाए, अन्यथा भारतीय वनों पर नेपाल की तरफ़ से पड़ रहे दुष्प्रभावों के भविष्य में और भी घातक परिणाम सामने आ सकते हैं.

देवेंद्र प्रकाश मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस मीठा ज़हर

24-30 जनवरी के अंक की आवरण कथा-कांग्रेस मीठा ज़हर है, रोचक है. राम विलास पासवान ने अपनी किताब के बहाने कांग्रेस पर जमकर हमले किए. पूरा सच क्या है, यह तो वही बेहतर जानते होंगे. लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-बहुत सच्चाई तो है उनकी बातों में.

-सरोज कुमार, दरभंगा, बिहार.

सरकार की नीयत

आलेख-लोकपाल विधेयक: भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कमज़ोर सरकारी हथियार (24-30 जनवरी) पढ़ा. अहम जानकारी प्राप्त हुई. लेखक ने बहुत बारीकी से विषय पर प्रकाश डाला है. अव्वल तो सरकार की मंशा ही नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, वह सिर्फ़ दिखावा करती है कि उसे देश की चिंता है, जबकि उसकी कोशिश हमेशा यह रहती है कि उससे जुड़े लोग अपनी मनमानी करते रहें और फंसने भी न पाएं.

-मनोज कुमार, इटावा, उत्तर प्रदेश.

पशु बलि प्रथा एक कलंक

गढ़वाल के पशु बलि मेले के बारे में पढ़ा. आलेख ज्ञानवर्द्धक है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हमारा समाज आज भी आदिम युग में है. पशुओं के वध से देवी-देवता ख़ुश होते हैं, यह सोच ही ग़लत है. हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है.

-दिव्या रानी, मधुबनी, बिहार.

शिक्षा का अधिकार

आधी आबादी और शिक्षा का अधिकार शीर्षक से प्रकाशित लेख में सही कहा गया है कि आज भी लड़कियों की पढ़ाई के बारे में रोक-टोक बरती जाती है और उन्हें घर के कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं.

-राजू शर्मा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

नव उदारवाद

तोप मुक़ाबिल-महंगाई नव उदारवाद की देन (24-30 जनवरी) पढ़ा. वाकई निजी कंपनियों के एकाधिकार की वजह से ही महंगाई और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है. सरकार ही बाज़ार को उनके लिए छोड़ देती है, जिससे महंगाई आसमान छू रही है और खामियाजा निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ता है. सरकार के सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं.

-निर्मला चोपड़ा, हुगली, बंगाल.

बोफोर्स का सच

17-23 जनवरी के अंक की आवरण कथा-बोफोर्स का पूरा सच पढ़ी, बढ़िया लगी. विषय को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है. बोफोर्स से जुड़े इतने फैक्ट एक साथ आज तक कहीं पढ़ने को नहीं मिले. साधुवाद.

-आशू, ई-मेल से.

-बोफोर्स मुद्दे को आपने बहुत सुंदर ढंग से उठाया. आज सरकार ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है. क्रांति होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं.

-डी पी मिश्रा, ई-मेल से.

युवकों को बेवकूफ बनाने का नाटक

चौथी दुनिया के तीन जनवरी के अंक में सरोज सिंह जी का लेख बहाली पर बवाल वास्तव में बिहार सरकार के द्वारा युवाओं को रोज़गार का सब्ज़बाग दिखाने का खुलासा है. चाहे वह शिक्षक बहाली हो या सिपाही भर्ती. सभी तरह के बहाली में बिहार सरकार की नीयत पर शक की सुई घूमती नज़र आती है सभी तरह की बहाली में पारदर्शिता का पूरी तरह का अभाव है. सारे बहाली की प्रक्रिया भ्रष्टाचार के रास्ते पूरी की जाती है. इसके विरुद्ध आंदोलन करने वाले अभ्यार्थी पर लाठी चार्ज करना भी इसी की कड़ी है. क्योंकि सारी बहाली पैसों के बल पर पूरी कर ली जाती है. इंटरव्यू तो एक दिखावा है. सरकार सारी बातों से अवगत हैं. लेकिन पता नहीं इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है. हमारे मुख्यमंत्री इसमें कुछ न कुछ बोलते प्रतिदिन हैं लेकिन उसे रोकने को वह कोई उपाय नहीं कर पाए हैं. एक और प्रक्रिया की शुरुआत की गई है जिसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रोज़गार देने के लिए कैंप करते हैं. उसमें कितने बेरोज़गारों को काम मिलेगा कहना मुश्किल है. उसमें मिलने वाली मज़दूरी नरेगा के मज़दूरों से भी कम है. जब ऐसी स्थिति बरक़रार है, तब फिर बेरोज़गारों के साथ यह खेल क्यों खेला जा रहा है. सरकार को बहाली के सारे प्रारुप को सीधा अंजाम देने की व्यवस्था करनी चाहिए.

शंकर शर्मा, बेगूसराय, बिहार

**आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com**

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सोनावणे की हत्या से उपजे सवाल

क्या इस देश से ईमानदारी और वफ़ादारी का जनाज़ा ही उठ जाएगा? क्या भारत में ईमानदार अधिकारी पैदा होने ही बंद हो जाएंगे? स्थिति देखकर तो ऐसा ही महसूस होता है. चारों ओर बेईमानी, रिश्वतख़ोरी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और लूट-खसोट का बोलबाला है. ईमानदारी तो जैसे इस देश को रास आना ही बंद हो गई है और बेईमानी इसकी नियति बन गई है. नासिक के अतिरिक्त ज़िलाधिकारी यशवंत सोनावणे का केवल यही दोष था कि वह ईमानदार थे. इसी दोष ने उन्हें स्वर्गीय, बच्चों को अनाथ और पत्नी को विधवा बना दिया. वाक़ई हमारे देश में कितना मीठा फ़ल है ईमानदारी का! यह बात भी बड़ी अजीब है कि एक तो हमारे देश में ईमानदार अधिकारियों का पहले से ही अभाव है और जो ईमानदार हैं भी, तो उन्हें या तो बेईमान बनने पर मजबूर कर दिया जाता है या फिर मौत के हवाले. सोनावणे देश के उन्हीं ईमानदार अधिकारियों में से एक थे, जो अपना फ़र्ज़ निभाते-निभाते मौत की आग़ोश में चले गए. उन्हें मिलावटख़ोरों के ख़िलाफ़ मुहिम छेड़ने की सज़ा के तौर पर अपनी जान गंवानी पड़ी.

दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक में एक भयानक घटना को अंजाम देते हुए मिलावटख़ोरों ने अतिरिक्त ज़िलाधिकारी यशवंत सोनावणे को ज़िंदा जला दिया. यह दर्दनाक घटना नासिक से 75 किलोमीटर दूर एक तेल डिपो पर दिन के उजाले में अंजाम दी गई. याद रहे कि यह पूरा इलाक़ा पेट्रोल, डीज़ल और केरोसिन में मिलावट के लिए बदनाम है. सोनावणे ने इस इलाक़े से गुज़रते हुए देखा कि कुछ ट्रक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, इसलिए उन्होंने अपना फर्ज़ निभाते हुए कार से उतर कर लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, तभी पोपट शिंदे नामक एक आदमी ने अपने साथियों समेत हमला कर दिया और उन पर तेल डालकर आग लगा दी, जिससे मौक़े पर ही उनकी मौत हो गई. सोनावणे तो चले गए, लेकिन सरकार और जनता के सामने कई सवाल खड़े कर गए. उनकी मौत से यह स्पष्ट हो गया कि देश में अपराधी कितने आज़ाद हैं. वे क़ानून से कैसे खिलवाड़ करते हैं? पुलिसकर्मियों को वे इस तरह मौत के घाट उतार देते हैं, जैसे वे क़ानून के रखवाले न होकर आम आदमी हों. वे जिस चीज़ में चाहें, मिलावटख़ोरी कर सकते हैं और अगर क़ानून के रखवाले भी उनके इस काम में रोड़ा बनेंगे तो वे उन्हें मौत के घाट उतार देंगे. यह हमारी सरकार के लिए सोचने का समय है.

ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र के मनमाड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तेल के डिपो हैं, जहां से प्रतिदिन 3000 टैंकरों में तेल की आपूर्ति होती है. यहां के तेल माफ़िया ट्रांसपोर्टरों से मिलीभगत करके प्रतिदिन 5 हज़ार लीटर पेट्रोल की चोरी करते हैं. फिर इन ट्रैंकरों में केरोसिन मिला दिया जाता है और यह तेल अन्य भागों में सप्लाई कर दिया जाता है. यह हमारी आदत बन चुकी है या फिर परंपरा रही है कि हम किसी भी अवैध काम को रोकने के लिए उस वक़्त तक कार्यवाही नहीं करते, जब तक कोई बड़ा नुक़सान न हो जाए. यानी बड़े पैमाने पर जान और माल का नुक़सान न हो जाए. सोनावणे की मौत के फ़ौरन बाद ही सरकार हरकत में आ गई और मिलावटख़ोरों के ठिकानों पर छापामारी शुरू कर दी गई, सैकड़ों मिलावटख़ोरों की गिरफ़्तारी भी हुई. सवाल यह उठता है कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया? क्यों देश को एक ईमानदार अधिकारी की सेवा से वंचित कर दिया गया? क्या सरकार और प्रशासन को मिलावटख़ोरों के इस काले धंधे की पहले से जानकारी नहीं थी? निश्चित रूप से थी, बल्कि उनके ठिकानों की भी जानकारी थी. उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही सिर्फ़ इसलिए नहीं की गई, क्योंकि वे सरकार में बैठे लोगों और अधिकारियों को मोटी रिश्वत देते हैं. मिलावटख़ोरी का यह काम सरकार और प्रशासन के संरक्षण में होता है. यह तो केवल डीज़ल और पेट्रोल की कहानी सामने आई है, खाद्य पदार्थों में भी बड़े पैमाने पर ज़हर मिलाया जा रहा है. ऐसा ज़हर, जो कितने ही मासूम लोगों की ज़िंदगियां लील चुका है और उससे प्रशासन भी पूरी तरह वाक़िफ़ है, लेकिन कार्यवाही उस समय तक नहीं होगी, जब तक कोई बहुत बड़ा नुक़सान न हो जाए और मीडिया उसे प्राथमिकता देकर प्रकाशित-प्रसारित न करे.

सोनावणे की मौत का मुद्दा ताज़ा है, इसलिए सरकार और प्रशासन हरकत में हैं. दो-चार महीने गुज़र जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे और सरकार भी कि कौन था सोनावणे और कहां है उसकी विधवा और बच्चे? यही हमारा क़ानून और प्रथा है और यही हमारी परंपरा है.

सोनावणे के हत्यारों की गिरफ़्तारी भी मीडिया और जनता के दबाव में आकर की गई. जब महाराष्ट्र सरकार को एहसास हुआ कि सोनावणे की हत्या राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकी है तो उसने आनन-फ़ानन में सैकड़ों मिलावटख़ोरों को गिरफ़्तार कर लिया. यह गिरफ़्तारियां तब की गईं, जब लाखों सरकारी कर्मचारी उत्तेजित होकर विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए. राज्य के 80,000 राजपत्रित अधिकारियों समेत 17 लाख सरकारी कर्मचारियों ने अपना काम बंद करके विरोध प्रदर्शन किया. इससे सरकार को अपनी कुर्सी पर ख़तरा मंडराता नज़र आया तो उसने मिलावटख़ोरों को गिरफ़्तार ही नहीं किया, बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने की घोषणा भी की. अब देखना यह है कि सोनावणे के हत्यारों को कितनी जल्दी फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा और उनकी विधवा को कब शांति मिलेगी. संभव है, सोनावणे के मामले की फ़ाइल भी उन लाखों-करोड़ों फ़ाइलों में दबकर रह जाए, जिन्हें नंबर आने से पहले ही दीमक चाट चुके हैं, जिनके पन्ने पीले और बेजान होकर झड़ चुके हैं और न्याय की उम्मीद लगाए बैठे लोग इस दुनिया से चले गए.

मुंबई पर हमला हुआ यानी देश की प्रतिष्ठा पर हमला हुआ. क़साब पकड़ा गया और उसे अदालत ने मौत की सज़ा भी सुना दी, लेकिन वह आज भी ज़िंदा है और जेल में मज़े से ज़िंदगी गुज़ार रहा है. मुंबई हमले के पीड़ित आज भी क़साब की फांसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें हमले में अपनों को खोने का दु:ख आज भी सता रहा है, उनके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं? सिर्फ़ अपनों को याद करके आंसू बहा सकते हैं और क़ानून का रोना रो सकते हैं. सोनावणे की मौत का मुद्दा ताज़ा है, इसलिए सरकार और प्रशासन हरकत में हैं. दो-चार महीने गुज़र जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे और सरकार भी कि कौन था सोनावणे और कहां है उसकी विधवा और बच्चे? यही हमारा क़ानून और प्रथा है और यही हमारी परंपरा है. मिलावटख़ोरी का बाज़ार फिर गर्म हो जाएगा और फिर कोई सोनावणे बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया जाएगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

बिन लादेन और असीमानंद एक ही थैली के चट्टे-बट्टे

साधारण अपराधों की तुलना में आतंकी अपराधों की जांच कहीं अधिक कठिन होती है. इनमें बम फेंकने या गोली चलाने वालों के असली नियंत्रक रहस्य के आवरण में लिपटे रहते हैं और उन तक पहुंचना आसान नहीं होता. समस्या को और बढ़ाती है जांचकर्ताओं की मानसिकता, सोच एवं पूर्वाग्रह. हमारे देश में हुए अधिकांश आतंकी हमलों के लिए जेहादी आतंकवाद को दोषी ठहराया जाता रहा है और पुलिस एवं जांच एजेंसियां यह मानकर चलती रही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जेहादी मुसलमान ही आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार हैं. हर आतंकी हमले का दोष सीमा पार के किसी न किसी मुस्लिम संगठन पर मढ़ दिया जाता था. सीमा पार आतंकवाद जांचकर्ताओं का प्रिय शब्द बन गया था. कथित सीमा पार आतंकियों के स्थानीय संपर्क सूत्र होने के आरोप में मुसलमान युवकों को पकड़ा जाता, उन्हें शारीरिक यंत्रणा देकर उनसे जबरन इक़बालिया बयान दिलवाए जाते और हर मामला सुलझा लिया जाता. पिछले कई वर्षों से यह एक सिलसिला सा बन गया था.

जब हमला मुस्लिम बहुल इलाक़ों में ऐसे समय-मौक़े पर होता था, जबकि वहां बड़ी संख्या में मुसलमान इकट्ठा हों, तब भी हमले के लिए मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार बताया जाता. पुलिस तुरंत कुछ मुस्लिम युवकों को धर लेती और उनके ख़िलाफ़ सुबूत भी जुटा लेती थी. ग़ैर भाजपा शासित प्रदेशों एवं केंद्र की सरकारें भी इस तमाशे को चुपचाप देखती रहीं. जांच प्रक्रिया पर आरोपियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब भी आपत्ति उठाई, उन्हें दरकिनार कर दिया गया. जांच प्रक्रिया का पाखंड पहली बार तब उजागर हुआ, जब महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं हिंदुत्व शिविर के कई सिपहसालारों का हाथ होने के पुख्ता सुबूत पेश किए. सभी आरोपी आरएसएस के किसी न किसी अनुसांगिक संगठन

संघ को प्रतिबंधित करने की मांग बेमानी है. पहले भी संघ पर तीन बार प्रतिबंध लग चुका है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, आपातकाल के दौरान और बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद. संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता. असली इलाज है विचारधारात्मक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तरों पर संघ से मुक़ाबला.

से जुड़े हुए थे, सांप्रदायिक विचारधारा से प्रेरित थे और हर चीज को धर्म के चश्मे से देखते थे. करकरे द्वारा किए गए खुलासों यह हुआ कि पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व अपनी जिद छोड़कर हिंदूवादी संगठनों को भी जांच के घेरे में लेने लगे. करकरे को धमकियां मिलने लगीं, उनकी जान ख़तरे में पड़ गई. अंतत: 26 नवंबर, 2008 को उनकी हत्या हो गई.

करकरे के प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि आतंकी हमलों की जांच सही दिशा में होने लगी. इंद्रेश कुमार जैसे आरएसएस नेता एवं विहिप के स्वामी असीमानंद जांच के घेरे में आ गए. असीमानंद ने गुजरात के डांग ज़िले में ईसाई विरोधी जनोन्माद भड़काया, जिससे वहां ईसाइयों के ख़िलाफ़ व्यापक हिंसा हुई. असीमानंद ने डांग में शबरी कुंभ का आयोजन किया. आदिवासियों को डरा-धमका कर उसमें भाग लेने पर मजबूर किया गया. इस कुंभ में आरएसएस एवं उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रही. यह कुंभ संघ के अल्पसंख्यक विरोधी अभियान का हिस्सा था. असीमानंद एक बार फिर चर्चा में हैं. कारण है उनका इक़बालिया बयान, जिसमें उन्होंने आतंकी हमलों में अपनी एवं अपने साथियों की भागीदारी स्वीकार की. यह बयान उन्होंने 18 दिसंबर, 2010 को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया. स्वामी के दिमाग़ में बदला लेने का विचार सबसे पहले 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए आतंकी हमले के बाद आया. 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर हमले के बाद इस विचार ने जोर पकड़ लिया. स्वामी ने कहा, हमने भरत भाई (भरत रीतेश्वर) के वलसाड स्थित निवास पर जून 2006 में बैठक की. इसमें हमने निश्चय किया कि मुसलमानों के पूजास्थलों पर विस्फोट किए जाएं. संदीप डांगे, भरत भाई, साध्वी प्रज्ञा, सुनील जोशी, लोकेश शर्मा, राम जी कालसांगरा एवं अमित बैठक में मौजूद थे. हमने तय किया कि मालेगांव, अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस में विस्फोट किए जाएं. जोशी ने इन सभी ठिकानों का सर्वेक्षण करने की ज़िम्मेदारी ली. स्वामी ने कहा कि हमलों की तैयारी के लिए बैठक की पहल उसने की थी. ज्ञातव्य है कि लोकेश शर्मा को पहले ही अजमेर दरगाह विस्फोट के सिलसिले में हिरासत में लिया जा चुका है.

पुलिस जांच से यह साबित हुआ कि कई हिंदुत्ववादी जैसे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (पूर्व अभाविप कार्यकर्ता), ले. कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, पूर्व मेजर उपाध्याय (भाजपा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ मुंबई का प्रमुख), स्वामी दयानंद पांडे (आरएसएस से जुड़ाव, अभिनव भारत की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका), इंद्रेश कुमार (आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य), सुनील जोशी (आरएसएस प्रचारक, बाद में अज्ञात हत्यारों के हाथों मारा गया), देवेंद्र गुप्ता (आरएसएस प्रचारक, अभिनव भारत से संबंध), रामचंद्र कालसांगरा एवं संदीप पांडे आदि कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे. स्वामी असीमानंद की स्वीकारोक्तियों से कई बातें साफ हो गई हैं. पहली बात तो यह है कि नांदेड में संघ कार्यकर्ता राजकोंडवार के घर में हुए विस्फोट, जिसमें बजरंग दल के दो कार्यकर्ता मारे गए थे, के समय से ही सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हिंदुत्ववादियों का आतंकी घटनाओं में हाथ है. नांदेड मामले की जांच एक जनसमिति ने की थी और पुलिस की जांच एवं निष्कर्षों में कई कमियां पाई गई थीं. इसके बाद महाराष्ट्र के परभणी, जालना, बीड एवं अन्य स्थानों पर ऐसी ही घटनाएं हुईं. सामाजिक कार्यकर्ता लगातार अपने संदेहों की ओर सरकार और मीडिया का ध्यान आकर्षित करते रहे, परंतु उनकी किसी ने नहीं सुनी. पुलिस की सोच तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी ही, ग़ैर भाजपाई राज्य सरकारें एवं केंद्र सरकार भी इन विस्फोटों के बीच की समानताओं और पुलिस जांच की कमियों को अनदेखा करती रहीं.

मीडिया का बड़ा हिस्सा भी चुप्पी साधे रहा और आतंकी घटनाओं में हिंदुत्ववादियों की भूमिका को न के बराबर महत्व देता रहा. आतंकी घटनाओं में तथाकथित जेहादियों की भूमिका की ख़बरें तो मुखपृष्ठ पर बैनर शीर्षकों से छपती थीं. इसके विपरीत पुलिस के निष्कर्षों को चुनौती देने वाली ख़बरें, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा की गईं जांचों के नतीजे आदि या तो छपते ही नहीं थे और यदि छपते भी थे तो अंदर के पृष्ठों पर छोटे-छोटे शीर्षकों से. इसी मानसिकता के चलते दर्जनों मुस्लिम नौजवानों को पुलिस के हाथों घोर शारीरिक यंत्रणा झेलनी पड़ी. कई की पढ़ाई छूट गई और कई के फलते-फूलते करियर बर्बाद हो गए. सामूहिक सामाजिक सोच यह बना दी गई कि सभी आतंकी मुसलमान होते हैं. आज भी बड़ी संख्या में मुस्लिम युवक ऐसे आतंकी हमलों के सिलसिले में सलाखों के पीछे हैं, जिन हमलों की ज़िम्मेदारी असीमानंद एंड कंपनी ने ले ली है. क्या सरकार पुलिस की ग़लत जांच प्रक्रिया के कारण इन युवकों के साथ हुए अन्याय और अत्याचार की भरपाई करेगी? यह मांग की जा रही है कि वे तुरंत रिहा हों और उन्हें मुआवज़ा भी मिले. सरकार को इन मांगों के संबंध में जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए.

एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आरएसएस के साथ क्या किया जाना चाहिए. संघ नफरत की राजनीति का मुख्य स्रोत है. आतंकी घटनाओं में लिप्त पाए गए अधिकांश हिंदुत्ववादियों का संघ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था. संघ आसानी से इन लोगों से अपना कोई भी नाता होने से इंकार कर सकता है और वह ऐसा करेगा भी. संघ अपने अनुसांगिक संगठनों की गतिविधियों के लिए क़ानूनन ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि काग़ज़ पर वे सभी स्वायत्त हैं. जो आरोपी संघ से सीधे संबद्ध थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और संघ ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया है. संघ प्रमुख ने कहा है कि उनके संगठन में हिंसक गतिविधियां करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है. क़ानूनन संघ पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती. संघ का संगठनात्मक ढांचा इतना लचीला है कि वह सैकड़ों क़त्ल करा दे, तब भी उसके दामन पर ख़ून का एक धब्बा भी नज़र नहीं आएगा.

संघ को प्रतिबंधित करने की मांग बेमानी है. पहले भी संघ पर तीन बार प्रतिबंध लग चुका है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद, आपातकाल के दौरान और बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद. संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता. असली इलाज है विचारधारात्मक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तरों पर संघ से मुक़ाबला. यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य है. संघ अपनी विचारधारा का सतत प्रचार-प्रसार करता रहा है. मीडिया से लेकर स्कूली पाठ्य पुस्तकों तक, सभी का उपयोग संघ अपनी विचारधारा के प्रसार के लिए करता रहा है. स्वामी असीमानंद, लक्ष्मणानंद एवं अन्य कथित संतों ने संघ की विचारधारा को धर्म का लबादा पहना दिया है. हर भारतीय नागरिक, जो प्रजातांत्रिक समाज और मानवाधिकारों का हामी है, उसे अपने समान विचार वाले अन्य लोगों के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर धर्म आधारित राष्ट्रवाद का मुक़ाबला करना चाहिए. चाहे स्वामी असीमानंद हों या ओसामा बिन लादेन, दोनों धर्म की चाशनी में लिपटे आतंकवाद के पोषक हैं.

राम पुनियानी
feedback@chauthiduniya.com

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

डिस्कवर पत्रिका के अनुसार, आज से 20,000 वर्ष पहले के मानव के दिमाग़ के कद की अपेक्षा आज के मानव के दिमाग़ का घनत्व 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर कम हो गया है.

आपके पत्र, हमारे सुझाव

मूल प्रति नहीं मिल रही

एक फ़र्ज़ी फोटोकॉपी आवेदन का सहारा लेकर मुझे अपने मूल पद से नीचे के पद पर पहुंचा दिया गया. मैंने सूचना अधिकार क़ानून के तहत उक्त फोटोकॉपी आवेदन की मूल प्रति उपलब्ध कराने को कहा (जो था ही नहीं). असल में मेरे मामले में साजिश रची गई और उक्त फ़र्ज़ी फोटोकॉपी बनाई गई. मुझे तभी न्याय मिल सकता है, जब उक्त आवेदन की मूल प्रति मिल जाए. मैं इस मामले को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग तक गया. सूचना आयुक्त ने उक्त आवेदन की मूल प्रति उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन को आदेश भी दिया, लेकिन मूल प्रति नहीं दी गई. मैं दोबारा आयोग में गया, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. कृपया यह बताएं कि न्याय पाने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए?

–एस आर के मिश्रा, *धनबाद, झारखंड.*

आप केंद्रीय सूचना आयोग में भी जा चुके हैं. वहां से मूल प्रति दिए जाने का आदेश भी दिया जा चुका है. ऐसे में आप सूचना आयोग में यह शिक़ायत कर सकते हैं कि उसके आदेश का पालन नहीं हुआ. यदि इससे भी काम नहीं बनता है, तब आप सारे सबूतों एवं आयोग के आदेश की प्रति के साथ हाईकोर्ट में इस मामले को ले जा सकते हैं.

आरटीआई सदस्य बनना चाहता हूं

मैं एक स्वयंसेवक हूं. मैंने सूचना क़ानून के माध्यम से कई सारे विभागों में आवेदन दिए हैं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता रहता हूं. मैं आरटीआई का सदस्य बनना चाहता हूं. इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?

–रमेश गुप्ता, *नरकटियागंज, प. चंपारण, बिहार.*

आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आरटीआई सदस्य बनने के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी संगठन से जुड़ सकते हैं या ख़ुद का एक संगठन बना सकते हैं. आप चौथी दुनिया में प्रकाशित होने वाले आरटीआई कॉलम के ज़रिए भी अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं.

कम अंक मिले

मैं पटना कॉलेज में बीए पार्ट–2 का छात्र हूं. बीए पार्ट–1 की परीक्षा में मुझे अपेक्षा से कम अंक मिले. मैं इस मामले में आरटीआई का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं?

–गणेश शंकर विद्यार्थी, *पटना, बिहार.*

आप इस मामले में सूचना क़ानून का सहारा ले सकते हैं. आप सूचना आवेदन के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाने की मांग कर सकते हैं. कई सूचना आयोगों द्वारा उत्तर पुस्तिका दिखाने का आदेश दिया जा चुका है.

ग्राम स्तर पर भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो?

सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसे समाप्त करने के लिए योगदान करना चाहता हूं. इसके लिए मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए. ग्राम स्तर पर जो सरकारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, यह जानकारी चाहता हूं. मनरेगा, सरकारी राशन, वृद्धावस्था पेंशन एवं सरकारी अस्पतालों आदि में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है?

–विपिन कुमार, *फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड.*

चौथी दुनिया के लगभग सभी अंकों में हम इन समस्याओं से संबंधित आवेदन का प्रारूप प्रकाशित करते हैं, साथ ही यह भी बताते हैं कि कैसे हम और आप मिलकर इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं. आप चौथी दुनिया के इस अभियान से जुड़ सकते हैं. हम सदैव आपके साथ हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश,
पिन –201301
ई–मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(हैंडपंपों का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
.........................के हैंडपंपों के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. आपके रिकॉर्ड के मुताबिक उपरोक्त गांव में कुल कितने हैंडपंप लगवाए गए हैं? उनकी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:
क. स्थान का नाम, जहां हैंडपंप लगा है
ख. हैंडपंप लगाए जाने की तारीख़
ग. हैंडपंप लगाने के लिए खर्च की गई राशि
घ. इस राशि का भुगतान किस मद से किया गया
ड. हैंडपंप की वर्तमान स्थिति बताएं (चालू व ठीक/चालू लेकिन खराब/बंद)
च. लगाए जाने के बाद से अब तक कितनी बार मरम्मत की गई, तिथिवार विवरण दें.
छ. प्रत्येक मरम्मत पर व्यय की गई राशि का विवरण दें.

2. क्या सरकार द्वारा इन हैंडपंपों की नियमित जांच कराई जाती है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद और जिम्मेदारियां बताएं.

3. आखिरी बार इन हैंडपंपों की जांच कब की गई? जांच अधिकारी का नाम एवं पद बताएं, साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.

4. किसी गांव में हैंडपंपों की संख्या का निर्धारण किस आधार (जनसंख्या/क्षेत्रफल/विस्तार/अन्य) पर किया जाता है? इससे संबंधित नियमों, दिशानिर्देशों एवं शासनादेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

5. क्या हैंडपंपों के जल की शुद्धता की जांच की गई है? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम एवं पद बताएं, साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं.

6. क्या हैंडपंप लगवाने/मरम्मत में आने वाली लागत का कुछ भाग गांव वाले वहन करते हैं? यदि हां, तो इससे संबंधित सभी शासनादेशों एवं दिशानिर्देशों की प्रमाणित प्रति दें. उपरोक्त हैंडपंपों को लगवाने में किन–किन ग्रामीणों से और कितना धन वसूल किया गया, प्रत्येक का नाम एवं पता बताएं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.......रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर..........है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम...................
पता...................
फोन नंबर.............

संलग्नक..........
(यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष — 21 मार्च से 20 अप्रैल
परिश्रम की आवश्यकता है, ताकि आप आगे की तैयारी कर सकें. आपके विरोधी परास्त होंगे. व्यय भार बढ़ेगा. निर्माण कार्य की आवश्यकता महसूस होगी. रचनात्मक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

वृष — 21 अप्रैल से 20 मई
पुराने दोस्त के आगमन से परिवार में व्यस्तता बढ़ेगी. नियोजित कार्यक्रम भी सफल होंगे और आर्थिक लाभ का सुअवसर भी हाथ आएगा. किसी फिल्मी हस्ती से मुलाक़ात होगी. सौदे में कठिनाई होगी. हो सकता है कि यात्रा रोकनी पड़े.

मिथुन — 21 मई से 20 जून
चल–अचल संपत्ति का पारिवारिक विवाद निपटाना आवश्यक होगा. आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और मनोवांछित की प्राप्ति होगी. सप्ताह के मध्य में पारिवारिक व्यवस्था बनाने में व्यस्त रहेंगे. सोचे कार्य सफल होंगे. मित्रों द्वारा किए जा रहे विरोध में कमी आएगी.

कर्क — 21 जून से 20 जुलाई
दांपत्य संबंधों में पूर्ण सहयोग एवं विश्वास अनुभव करेंगे. स्वजनों का भी सहयोग मिलेगा. पर्याप्त धन–संपदा हाथ में होने के बावजूद पारिवारिक अशांति रहेगी, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सबसे पहले न लें. मित्रों का सहयोग बना रहेगा.

सिंह — 21 जुलाई से 20 अगस्त
मानसिक उलझनों के कारण सिरदर्द की आशंका या फिर संतान पक्ष की चिंता रहेगी. पड़ोसियों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है. बेहतर होगा कि उनसे बनाकर रखें, तभी सहायता मिलेगी. वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें.

कन्या — 21 अगस्त से 20 सितंबर
धर्म–कर्म के प्रति श्रद्धा पैदा होगी और किसी महान हस्ती के दर्शन लाभ भी होंगे. आंख के कष्ट के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में अस्थिरता रहेगी. समय के अनुसार चलने से आप उन्नति करेंगे, वरना समय आपको पीछे छोड़ देगा.

तुला — 21 सितंबर से 20 अक्टूबर
मित्रों एवं बंधुजनों के कारण तनाव होने से घर में भी क्लेश की स्थिति पैदा हो सकती है. शुभ समाचार का आना लगातार जारी रहेगा, इसलिए वही कार्य करें, जिसके बनने की उम्मीद हो. संतान के प्रति थोड़ा चिंतित होंगे, पर समझदारी से काम लें.

वृश्चिक — 21 अक्टूबर से 20 नवंबर
ख़र्च पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है. व्यापार से संबंधित कई अनुभव होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों की विभिन्न क्षेत्रों में साख बढ़ेगी. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन अपने सामान के प्रति सचेत रहें.

धनु — 21 नवंबर से 20 दिसंबर
कुछ अधूरे कार्य आपको निपटाने होंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. व्यय की पूर्ति होगी. सुख–दु:ख को समान समझ कर सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें. सब अपने आप ठीक होगा. समाज के कार्यों में व्यस्त रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें.

मकर — 21 दिसंबर से 20 जनवरी
किसी से अनबन के कारण व्यवहार एवं विचारों में परिवर्तन करना होगा. आपके द्वारा किए गए कार्यों का विरोध होगा. परिवार की समस्याओं के संबंध में कोई ग़लत निर्णय लेना कठिन होगा. पेट संबंधी कोई शिक़ायत हो सकती है.

कुंभ — 21 जनवरी से 20 फरवरी
अधिक उत्साह और तत्परता से कार्य बिगड़ सकता है. असफलता के कारण दु:ख होगा. शुभ संदेश भी आएगा और पुराने मित्रों से मुलाक़ात होगी. अनावश्यक शंकाओं से बचें. ग़लत तरीक़े से धन अर्जित न करें. यात्रा आवश्यक होगी.

मीन — 21 फरवरी से 20 मार्च
जटिलताएं ख़त्म होंगी और विरोधी परास्त होंगे. कनिष्ठ सदस्यों अथवा संतान पक्ष के कारण परेशानी होगी. जीवनसाथी से आर्थिक कारणों से दूरी रहेगी, लेकिन प्रेम यथावत बना रहेगा. काफी समय से अधूरा पड़ा कार्य पूरा हो जाएगा.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

रोबोट से इश्क

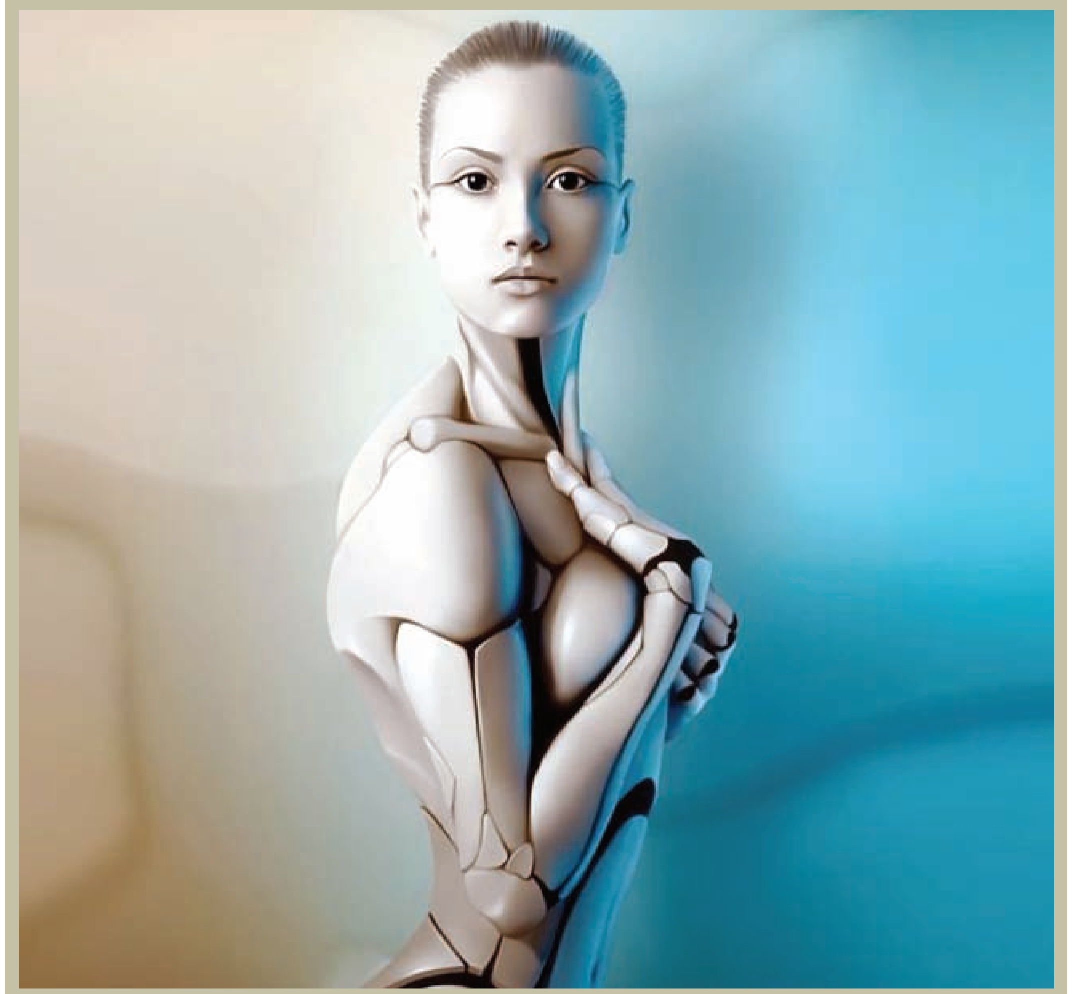

आजकल चाहे कामकाजी हो या फिर बेरोज़गार, सभी पर इश्क का भूत सवार रहता है. इस मामले में कुछ लोग भाग्यशाली रहते हैं, जबकि कुछ लोगों की लुटिया ही डूब जाती है. जिन लोगों को यह दु:ख सताता रहता है कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता या उन्हें अभी तक अपना जीवनसाथी नहीं मिला, उनके लिए एक अच्छी ख़बर है, यानी प्रेमी रोबोट. एक जर्मन डिज़ाइनर स्टीफन ने एक ऐसा रोबोट बनाया है, जो इंसान के स्पर्श को महसूस कर उस हिसाब से प्रतिक्रिया देता है. हालांकि अभी यह रोबोट अपनी प्रारंभिक विकास प्रक्रिया में है, इसलिए यह उम्मीद न रखें कि यह देखने में बहुत सुंदर होगा. वस्तुत: यह देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं है. इसका आकार एक बड़े तकिए की तरह है, परंतु इसे विकसित करने वाले डिज़ाइनर का दावा है कि जब यह तकनीक पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तो उसके बाद रोबोट के शारीरिक ढांचे को सुधारने का काम किया जाएगा.

डिज़ाइनर स्टीफन का कहना है कि आज के दौर का इंसान तकनीकी चीजों के अधिक क़रीब जा रहा है. उसे गैजेटों से प्रेम होने लगा है और इसलिए यह रोबोट उसके काम आ सकता है. यह इंसान के अकेलेपन को दूर करके उसे एहसास कराएगा कि उसके पास कोई अपना है. यह रोबोट इंसान के शरीर की गर्मी, स्पर्श और चमड़ी के रंग को भांपकर उस हिसाब से प्रतिक्रिया देता है. सबसे ज़रूरी बात कि यह रोबोट आपकी प्रेमिका की तरह बात–बात पर नाराज़ भी तो नहीं होगा. तो फिर अब लड़ाइए रोबोट से इश्क!

दिमाग़ छोटा हो रहा है

पहले की अपेक्षा आज के इंसान का दिमाग़ धीरे–धीरे छोटा होता जा रहा है. इसकी वजह क्या है और क्या इससे हमारी विचार शक्ति पर असर पड़ रहा है? इस विषय पर दुनिया के वैज्ञानिकों की राय अलग–अलग है. डिस्कवर पत्रिका के अनुसार, आज से 20,000 वर्ष पहले के मानव के दिमाग़ के कद की अपेक्षा आज के मानव के दिमाग़ का घनत्व 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर कम हो गया है. यह बदलाव क़रीब एक टेनिस की गेंद के जितना है. यह बदलाव दोनों लिंगों यानी नर और मादा के दिमाग़ में हुआ है. क्या इसका असर हमारी सोचने–समझने की शक्ति पर पड़ा है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाइसकोंसिन के जॉन हॉक्स के अनुसार, ऐसा नहीं है. इंसान का दिमाग़ छोटा हुआ है, परंतु साथ–साथ परिष्कृत भी. आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल हुआ है. हॉक्स के अनुसार, दिमाग़ का कद घटना मंदबुद्धि होने का लक्षण नहीं है.

लेकिन एक अन्य शोधकर्ता कैथेलिन मैकऑलिफ उनसे सहमत नहीं हैं. कैथेलिन के अनुसार, दिमाग़ के छोटे होने का असर विचार शक्ति पर पड़ा है. कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, आज के मानव का जीवन अपेक्षाकृत काफी सरल हो गया है. पहले के मानव को अपना जीवन बचाने और गुजारा करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. ठंड से बचने से लेकर खाने का जुगाड़ करने तक हर पल उसे सजग रहना पड़ता था और इसलिए उसका दिमाग़ भी बड़ा था. आज भोजन और अन्य कई ज़रूरी चीजें सर्वसुलभ हैं और इस वजह से हमारे दिमाग़ के बढ़ने का क्रम भी रुका है, बल्कि उल्टे गियर पर जा रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के डेविड गियरी और बैली के अनुसार, दिमाग़ के छोटे होने का क्रम तब शुरू हुआ होगा, जब इंसान ने समूह बनाकर रहना शुरू किया और परिवारवाद पनपा. परिवार में रहने की कला सीखने की वजह से इंसान के लिए कठिनाइयों का सामना करना थोड़ा सरल हो गया और उसने दिमाग़ का इस्तेमाल करना धीरे–धीरे कम कर दिया. फलस्वरूप दिमाग़ का कद बढ़ना रुक गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ईश निंदा क़ानून

कितना धर्म, कितनी राजनीति

पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या साबित करती है कि पाकिस्तान में क़ानून व्यवस्था नामक कोई चीज नहीं रह गई है. आश्चर्य की बात तो यह है कि मलिक मुमताज़ हुसैन क़ादरी जैसे कट्टरपंथी को तासीर जैसे उदारवादी नेता की सुरक्षा में तैनात किया गया. उससे भी ज़्यादा दु:खद यह है कि कुछ मुल्ला-मौलवियों का कहना है कि जो लोग तासीर की हत्या का शोक मनाएंगे, उनका हाल भी तासीर जैसा होगा.

डॉ. असगर अली इंजीनियर

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या से पाकिस्तान के ईश निंदा क़ानून के औचित्य के बारे में परंपरावादियों एवं उदारवादियों के बीच कटु बहस छिड़ गई है. यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी तत्व तासीर के हत्यारे के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं. यही नहीं, वे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हत्या की निंदा करने वालों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है. इन कट्टरपंथियों को यह समझना चाहिए कि अगर कोई क़ानून औचित्यपूर्ण हो, तब भी उसे तोड़ने वालों की जान लेने का हक़ किसी को नहीं है. यदि कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से किसी क़ानून को तोड़ने वालों को सज़ा देने लगेगा तो वह क़ानून, क़ानून नहीं रह जाएगा. क़ानून तोड़ने वालों को भी न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप मुक़दमा चलाकर और अपने बचाव का पूरा मौक़ा देकर ही सज़ा दी जा सकती है.

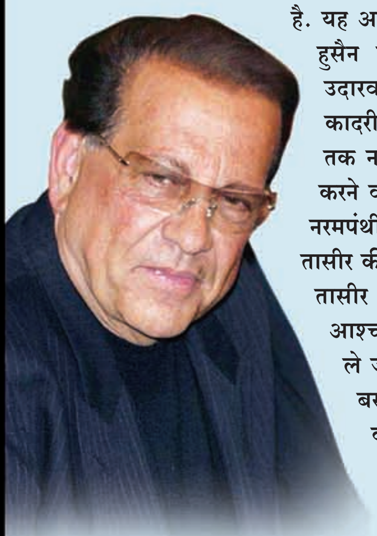

तासीर की हत्या से साफ है कि पाकिस्तान में क़ानून और व्यवस्था चौपट हो चुकी है. यह अचंभे की बात है कि हत्यारे मलिक मुमतज़ हुसैन कादरी जैसे कट्टरपंथी को तासीर जैसे उदारवादी गवर्नर के सुरक्षा दस्ते में रखा गया. कादरी को तो तासीर के नज़दीक आने का मौक़ा तक नहीं मिलना चाहिए था. उतनी ही अचंभित करने वाली बात यह है कि 500 (कथित रूप से नरमपंथी) मुल्ला-मौलवियों ने घोषणा की है कि तासीर की हत्या का शोक मनाने वालों का हाल भी तासीर जैसा ही होगा. इस पृष्ठभूमि में यह आश्चर्यजनक नहीं कि जब कादरी को अदालत ले जाया गया तो कुछ वकीलों ने उन पर फूल बरसाए. और तो और, हत्या की धमकी देने वाले मौलवियों और हत्यारे का सार्वजनिक अभिनंदन करने वाले वकीलों के ख़िलाफ़ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की. कई इस्लामिक विद्वानों ने टेलीविज़न कार्यक्रमों में तासीर की हत्या को उचित ठहराया और हत्या की निंदा करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा. ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सरकार है ही नहीं. वहां केवल कठमुल्लाओं का राज चल रहा है.

कुरआन, जो कि इस्लामिक क़ानून का मूल एवं सबसे प्रमाणिक स्रोत है, में ईश निंदा के लिए सज़ा की कहीं कोई चर्चा नहीं है. कुरआन अपने मानने वालों से यह कहती है कि वे अल्लाह से पैगंबर के लिए दया और कृपा मांगें. इसी कारण मुसलमान पैगंबर के नाम के आगे सल-लल-लाहु-अलैहि वसल्लम (उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो) लिखते हैं. कुरआन में पैगंबर मोहम्मद को सारी दुनिया के प्रति दया रखने वाला भी कहा गया है. जो सारी दुनिया के प्रति दया रखता हो, उसके नाम पर किसी को मारना कैसे जायज़ हो सकता है? हम कुरआन की सुनेंगे या सहज मानवीय कमज़ोरियों की? अगर यह मान भी लिया जाए कि किसी ने पैगंबर साहब का अपमान किया है तो भी क्या बिना क़ानूनी प्रक्रिया अपनाए, बिना उसके अपराध को सिद्ध किए उसकी जान ली जा सकती है? ईसाई महिला आसिया बीबी को एक निचली अदालत ने पैगंबर साहब का अपमान करने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी. अगर कोई व्यक्ति यह मानता है कि आसिया बीबी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या मात्र इसलिए वह भी पैगंबर के अपमान का दोषी हो जाएगा? ऐसा निष्कर्ष न्याय और क़ानून के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा. केवल कट्टरपंथी, उन्मादी तत्व ही ऐसा सोच सकते हैं. इस तरह की सोच की कोई क़ानूनी मान्यता नहीं है और कोई सभ्य समाज इसे स्वीकार नहीं कर सकता. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कुरआन में पैगंबर का अपमान करने वालों के लिए किसी प्रकार की सज़ा का प्रावधान नहीं है. और यहां तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ़ इसलिए मार डाला, क्योंकि पहला व्यक्ति यह मानता था कि एक तीसरे व्यक्ति को इस अपराध के लिए दी गई सज़ा उचित नहीं है. ऐसी राय रखने से भला कैसे पैगंबर साहब का अपमान होता है?

ईश निंदा क़ानून के समर्थक इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए सुन्नते पैगंबरी में दी गई एक कहानी का हवाला देते हैं. इस कहानी के अनुसार, एक यहूदी महिला पैगंबर व इस्लाम के बारे में उत्तेजना फैलाने वाली कविताएं लिखा करती थी. कहानी में कहा गया है कि पैगंबर ने अपने साथियों से पूछा कि उन्हें इस महिला से कौन छुटकारा दिला सकता है. इसके बाद उनके एक साथी ने उस महिला को मार डाला. जब उसने यह बात पैगंबर को बताई तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की. पहला सवाल तो यही है कि यह कहानी कितनी सही है. अगर इसे सही मान भी लिया जाए तो यह साफ है कि उस महिला को सज़ा पैगंबर का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि देशद्रोह के अपराध के लिए मिली थी. मदीना में रहने वाले सभी यहूदियों ने पैगंबर के साथ एक संधि की थी, जिसके अनुसार, यहूदियों की जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त और उनके मजहब को निभाने की इजाज़त के बदले उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि बाहरी लोगों के मदीना पर हमला करने की स्थिति में वे मदीना की रक्षा करेंगे. इस यहूदी औरत की कविताओं का इस्तेमाल इस्लाम विरोधी तत्व पूरे अरब प्रायद्वीप में इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे थे. इस प्रकार वह महिला संधि का उल्लंघन और देशद्रोह कर रही थी. आज भी दुनिया के अधिकांश देशों में देशद्रोह की सज़ा मौत है.

इसके विपरीत, जब एक अन्य यहूदी महिला ने पैगंबर पर कचरा फेंककर उनका अपमान किया, तब पैगंबर ने उस महिला को कोई सज़ा नहीं दी. जब भी पैगंबर उस महिला के घर के सामने से निकलते, वह उन पर कचरा फेंकती. एक दिन जब उस महिला ने पैगंबर पर कचरा नहीं फेंका तो उन्होंने उसके बारे में पूछताछ की. जब उन्हें पता लगा कि महिला बीमार है तो वह तुरंत उसकी मिजाज़पुर्सी के लिए पहुंचे. इस पर महिला बहुत शर्मिंदा हुई कि वह कितने महान व्यक्ति पर कचरा फेंकती थी और उसने इस्लाम अंगीकार कर लिया. इस तरह पैगंबर ने न केवल अपना व्यक्तिगत अपमान करने वाली महिला को माफ किया, वरन् उसका हालचाल जानने भी पहुंचे. किसी भी सच्चे धार्मिक व्यक्ति को यही करना चाहिए. अपने अपमान का बदला लेना कोई धार्मिक कृत्य नहीं है, वह तो मानव स्वभाव का एक गंदला, अंधेरा पक्ष है. पैगंबर साहब तो इतने आध्यात्मिक थे कि वह अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे. उन्हें अल्लाह ने एक ऐसे आदर्श मानव के रूप में धरती पर भेजा था, जिससे सभी मनुष्य प्रेरणा ग्रहण कर सकें और उनका व्यवहार सचमुच मानव जाति के लिए आदर्श था. कुरआन बार-बार मुसलमानों को सलाह देती है कि वे प्रतिशोध और क्रोध जैसी भावनाओं को दबाएं. जब कुरआन ऐसा कहती है तो पैगंबर, जिनके द्वारा कुरआन धरती पर उतरी थी, भला कुछ और कैसे कह सकते हैं?

पाकिस्तान में जिया-उल-हक ने ईश निंदा क़ानून लागू किया था और उसके पीछे शुद्ध राजनीतिक उद्देश्य थे. वैसे भी जिया-उल-हक एक सैन्य अधिकारी थे, जिनकी इस्लाम के प्रति समझ सीमित थी. यह भी महत्वपूर्ण है कि एक सैन्य अधिकारी को अपने शत्रु को नीचा दिखाने, उससे बदला लेने और उसका अपमान करने में असीम आनंद आता है. जिया ने यह क़ानून बनाकर ठीक यही किया. दु:ख की बात यह है कि इसके लिए उन्होंने इस्लाम के नाम का घोर दुरुपयोग किया. उनका उद्देश्य अपनी तानाशाही सत्ता के लिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी उलेमा का समर्थन हासिल करना था. जिया ने पाकिस्तान को इस्लामिक राज्य घोषित किया और उन्होंने ही कट्टरपंथी धार्मिक तत्वों को राजनीति में प्रवेश दिया. मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान के निर्माण में जो भी भूमिका रही हो, परंतु इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जिन्ना ने कठमुल्लाओं या इस्लाम का अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया. जिन्ना आधुनिक, उदारवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान का निर्माण करना चाहते थे, परंतु अनेक कारणों से, जिनकी चर्चा करना यहां प्रासंगिक न होगा, पाकिस्तान में प्रजातंत्र की जड़ें कभी मज़बूत नहीं हो सकीं. सभी राजनेताओं ने इस्लाम के नाम का ज़बरदस्त दुरुपयोग किया. सौभाग्यवश पाकिस्तान के पहले सैनिक तानाशाह अय्यूब ख़ान उदारवादी एवं धर्मनिरपेक्ष सोच के थे. उनकी अन्य कमियां चाहे जो रही हों, परंतु उन्होंने इस्लाम का राजनीतिक इस्तेमाल कभी नहीं किया. उल्टे उन्होंने कुछ सुधार ही किए, जिनमें 1961 का परिवार अध्यादेश भी था. इस नए क़ानून ने महिलाओं को बहुत राहत दी.

याह्या ख़ान, जो एक सैनिक क्रांति के ज़रिए अय्यूब ख़ान को अपदस्थ करके सत्ता पर काबिज हुए थे, को शासन व्यवस्था सहित किसी चीज की कोई फ़िक्र नहीं थी. याह्या ख़ान के बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सत्ता संभाली. भुट्टो, जो 1970 के दशक के प्रारंभ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, ने इस्लामिक समाजवाद के नाम पर जमकर राजनीति की. उन्होंने धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना दिया. कठमुल्लाओं को ख़ुश करने के लिए उन्होंने अहमदिया संप्रदाय को ग़ैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित कर दिया. मुल्लाओं के इस तुष्टिकरण की पाकिस्तान को बड़ी भारी क़ीमत चुकानी पड़ी. यद्यपि जिन्ना की मृत्यु के बाद ही लियाकत अली ख़ान ने इस्लाम को पाकिस्तान का राष्ट्रधर्म घोषित कर दिया था, तथापि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्लाम के इस्तेमाल का असली सिलसिला भुट्टो के शासनकाल में शुरू हुआ. जिया, जिन्होंने भुट्टो को सत्ता से खदेड़ कर गद्दी हासिल की, ने तो पाकिस्तान को बाकायदा इस्लामिक राज्य ही घोषित कर दिया. जिया ही उस ईश निंदा क़ानून के जनक हैं, जिसका व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालने के लिए जमकर दुरुपयोग होता आ रहा है. इस क़ानून के शिकार अल्पसंख्यक ईसाई तो हैं ही, मुसलमान भी हैं. इस क़ानून के अंतर्गत आरोपी ठहराए गए व्यक्तियों में आधे से अधिक मुसलमान हैं. इस्लामिक कट्टरपंथी एवं कठमुल्ले पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं. वे चुनाव के रास्ते तो सत्ता में आ नहीं सकते, इसलिए सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की चाहत में वे सत्ताधारियों से सौदेबाज़ी में लगे रहते हैं.

पाकिस्तान में असहिष्णुता का वातावरण है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि सलमान तासीर की हत्या के पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या यह एक अकेले सिपाही के पागलपन का नतीजा है. जो भी हो, यह साफ है कि तासीर की हत्या दूसरों के विचारों के प्रति असहिष्णुता का परिचायक और नतीजा दोनों है. भारत की तरह पाकिस्तान में भी स्कूली पाठ्य पुस्तकें कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं. वे छोटी उम्र से ही बच्चों में असहिष्णुता एवं संकीर्णता की भावना भर रही हैं. भविष्य के नागरिकों को कट्टरपंथी और दकियानूसी बनाया जा रहा है. यह काम इस हद तक हो चुका है कि पाकिस्तान के समाज को एक बार फिर उदारवादी एवं आधुनिक बनाने में कई वर्ष नहीं, बल्कि कई दशक लगेंगे. पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना अपने देश को उदार एवं धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र बनाना चाहते थे, परंतु आज तंग दिमाग़ मुल्ला पाकिस्तान के भाग्य विधाता बन बैठे हैं. इक़बाल ने ठीक ही लिखा है कि मुल्लाओं का काम फसाद कराना रह गया है. धर्म के नाम पर की जा रही राजनीति से पाकिस्तान की स्थिति इतनी विकट हो गई है कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अत्यंत दूरदर्शी एवं साहसी नेता की ज़रूरत होगी. तभी पाकिस्तान इस्लाम की मूल शिक्षाओं-सत्य, न्याय, दया एवं ज्ञान पर आधारित देश बन सकेगा. धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को मारने से अधिक अधार्मिक कुछ नहीं हो सकता.

(लेखक मुंबई स्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्युलरिज्म के संयोजक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

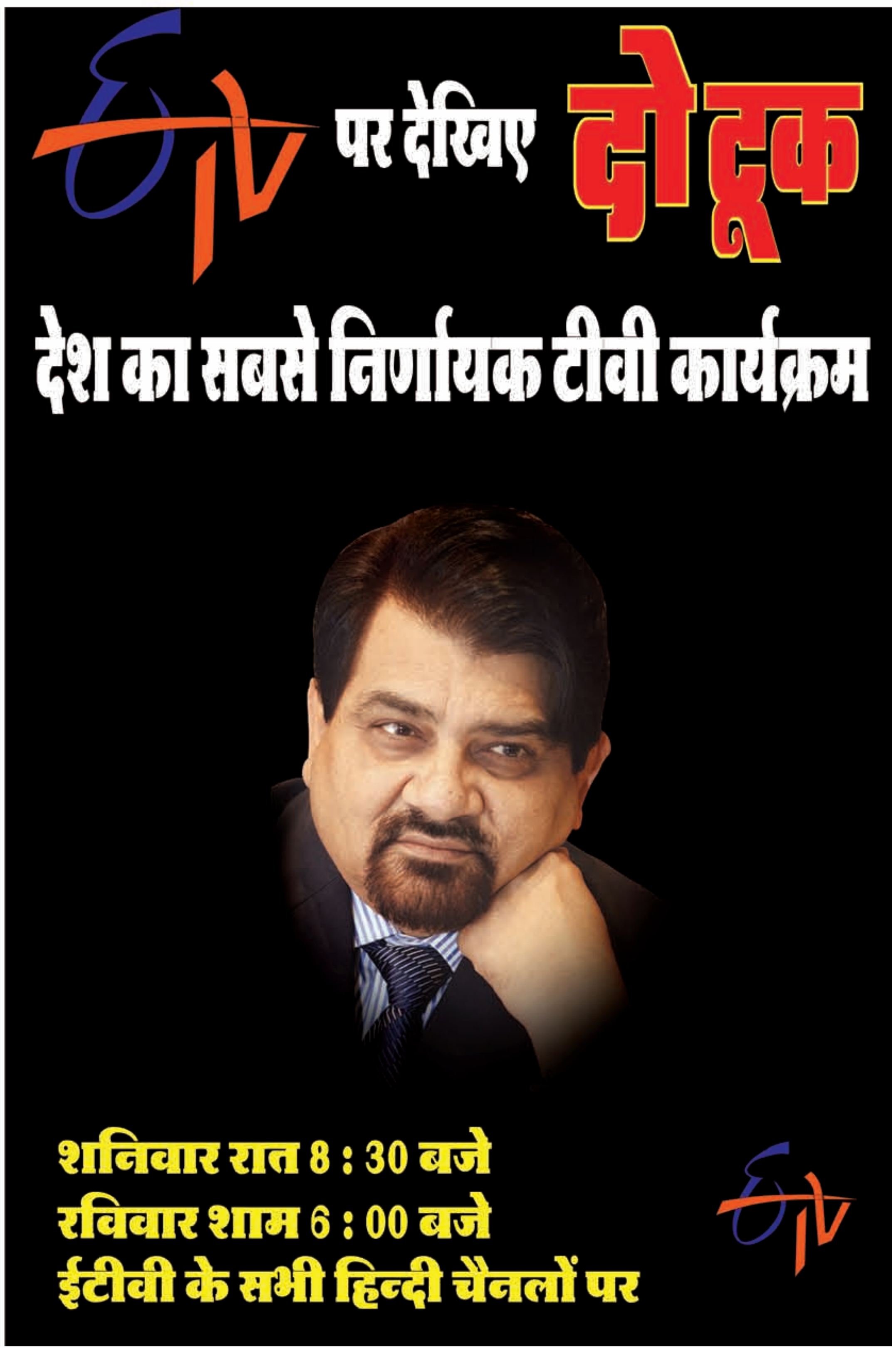

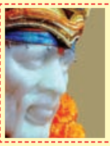

साई बाबा के करिश्मे के कारण काशीराम की जान बच गई. असल में काशीराम मात्र साधन था, असली शक्ति तो साई बाबा थे.

साकार से निराकार

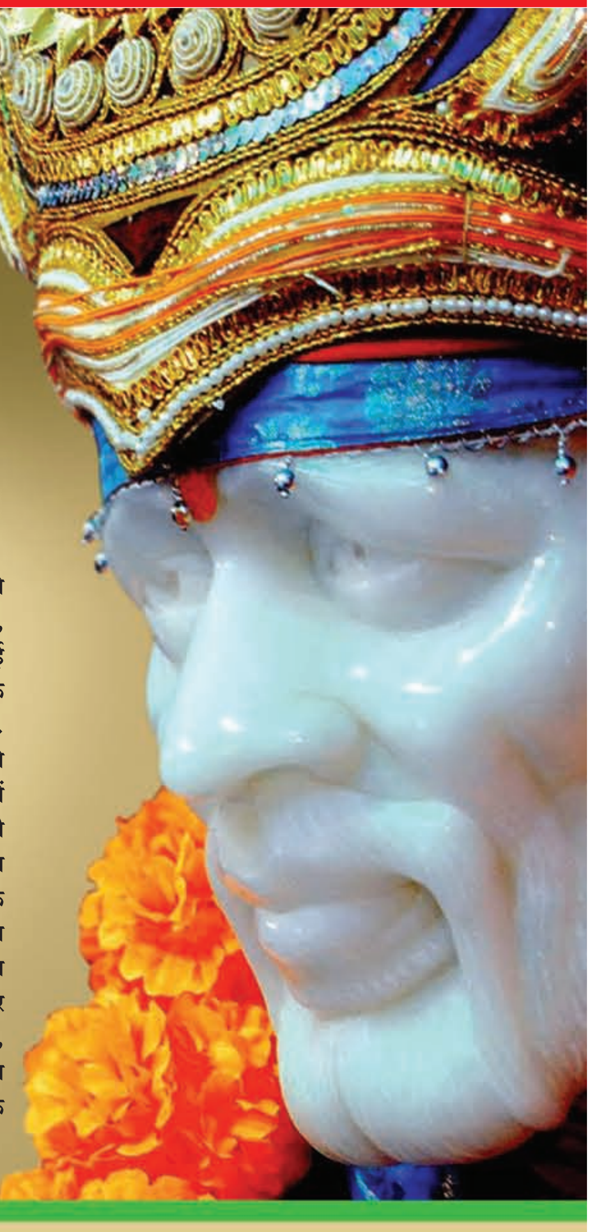

ऑसिम खेत्रपाल

साई बाबा द्वारका माई में रहते हुए भी हर जगह भक्तों की पुकार सुनते ही तत्काल घटनास्थल पर निराकार रूप से प्रकट होते थे और आज भी होते हैं. काशी राम हथकरघे से कपड़े बुनकर उन्हें किसी पड़ोस के साप्ताहिक बाज़ार में बेचता था. एक दिन देर शाम वह कपड़े बेचकर बाज़ार से लौट रहा था. रास्ते में भील लुटेरों ने उसे घेर लिया. काशी इतना डर गया कि उसके पास जो कुछ भी था, उसने लुटेरों को सौंप दिया, लेकिन एक छोटा सा बंडल जिसमें चीटियों के लिए शक्कर थी, उन्हें नहीं दिया. लुटेरों ने समझा कि उस बंडल में नोट या सोना-चांदी है. एक लुटेरा काशीराम से बोला, बंडल दे दो, अन्यथा तुम्हारी जान चली जाएगी. फिर वह लुटेरा अपनी तलवार ज़मीन पर रखकर काशी राम से बंडल छीनने लगा. सहसा काशीराम के मुंह से निकला, मदद करो साई बाबा. आश्चर्य की बात कि यकायक न जाने कहां से दुर्बल काशीराम में शक्ति आ गई. उसने एक झटके में लुटेरे की तलवार ज़मीन से उठाई और उसे

एक लुटेरा काशीराम से बोला, बंडल दे दो, अन्यथा तुम्हारी जान चली जाएगी. फिर वह लुटेरा अपनी तलवार ज़मीन पर रखकर काशी राम से बंडल छीनने लगा. सहसा काशीराम के मुंह से निकला, मदद करो साई बाबा. आश्चर्य की बात कि यकायक न जाने कहां से दुर्बल काशीराम में शक्ति आ गई.

आगे-पीछे जोर से घुमाने लगा. दो लुटेरे तुरंत मर गए, परंतु तभी एक लुटेरे ने पीछे से काशीराम पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. काशीराम अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़ा. उसके शरीर से ख़ून की फुहार बहने लगी.

काशीराम को मरा हुआ समझ कर शेष लुटेरे भाग गए. जब उसे होश आया तो लोगों ने गांव के वैद्य के पास जाने की सलाह दी, पर काशी को साई बाबा पर विश्वास था. वह सीधा द्वारकामाई पहुंचे. उदी और बाबा के आशीर्वाद से वह सात दिनों में ही ठीक हो गए. काशीराम की बहादुरी पर सरकार ने उसे तलवार भेंट की. जबकि हक़ीक़त यह है कि जब काशीराम लुटेरों से जूझ रहा था तो द्वारकामाई में साई बाबा जोर जोर से गाली निकाल कर हाथ में सटका उठाकर बार-बार ज़मीन पर पटकते और चिल्लाते हुए कभी अपने हाथों से अपना मुख भी पीटते थे. द्वारकामाई में बैठे हुए भक्त समझ गए कि किसी भक्त पर भारी विपदा आई है. उसे बचाने के लिए साई बाबा ऐसा कर रहे हैं. द्वारकामाई में भक्तों को जब काशीराम ने अपनी लुटेरों से मुठभेड़ का विवरण सुनाया तो भक्तगण समझ गए कि यह सब साई बाबा के करिश्मे के कारण हुआ और काशीराम की जान बच गई. असल में काशीराम मात्र साधन था, असली शक्ति तो साई बाबा थे. इस प्रकार साकार से निराकार रूप में आकर बाबा ने काशीराम की मदद की. बाबा अपने भक्तों के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

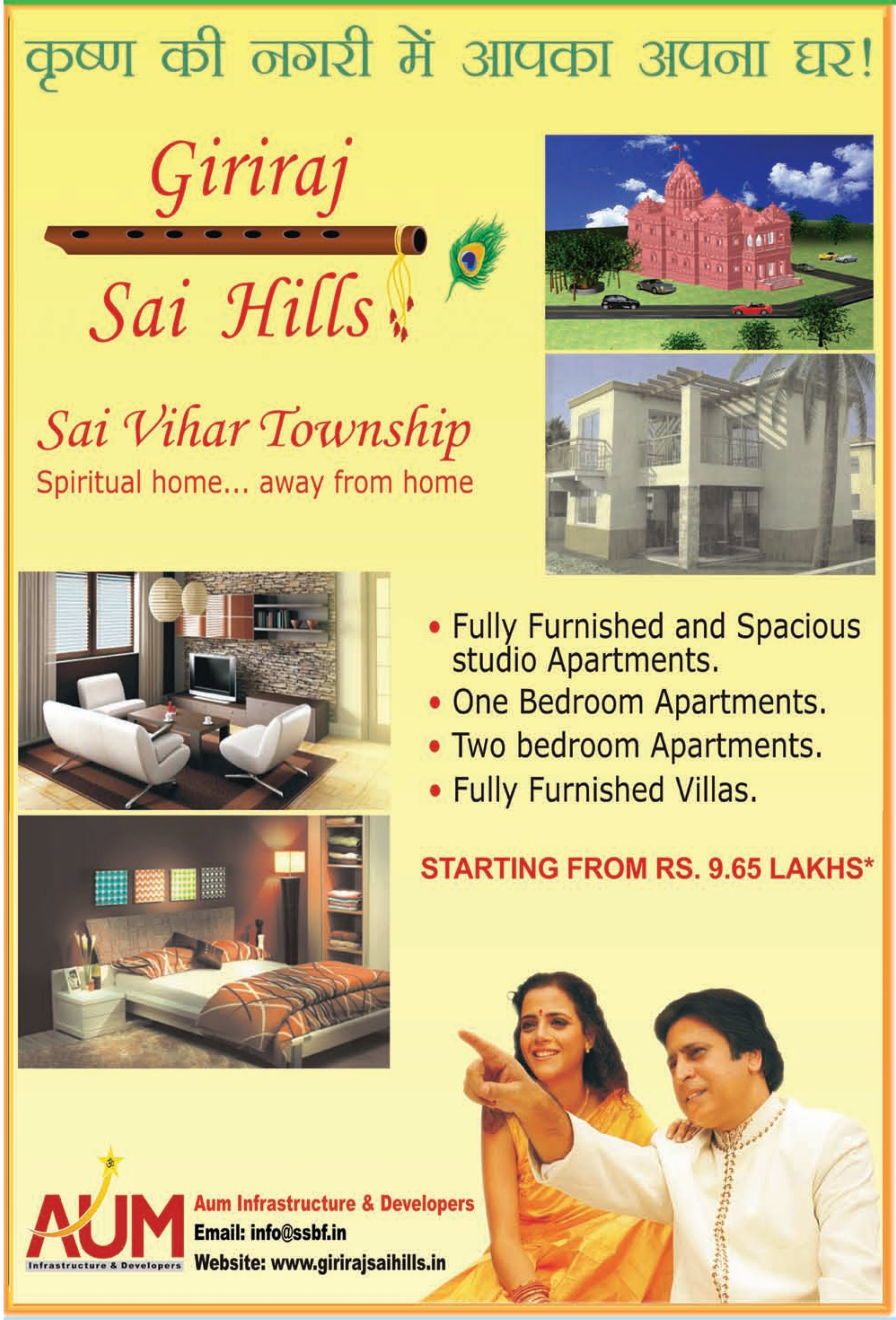

SSBF

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ् कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई की महिमा के इस अंक में हम आपके लिए एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं. इसमें हम आपसे बाबा के जीवन से जुड़ी पहेली पूछेंगे.

इस बार की पहेली साई सच्चरित्र से जुड़ी है. आपको हमें उस भक्त का नाम बताना है, जिसको साई बाबा ने सांप के काटने से बचाया था?

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

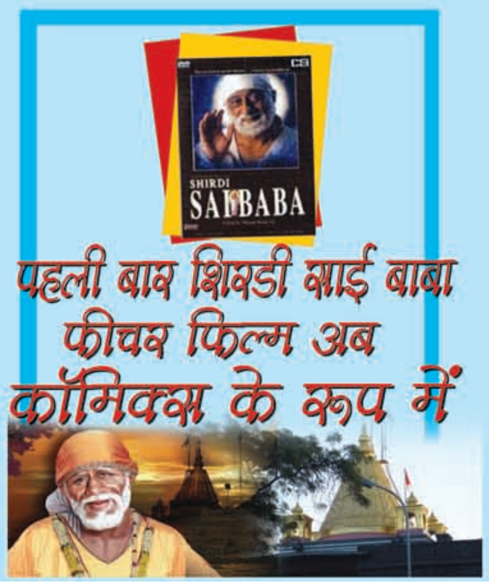

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

अगर चोट लगे, तभी शायरी होती है. यह एक बेबुनियाद बात है. असल बात यह है कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं. इसका संबंध शायरी के क्राफ्ट से है.

मां-बेटे के रिश्ते की नई इबारत

अनंत विजय

चंद साल पहले की बात है, आस्ट्रिया से एक ऐसी ख़बर आई थी, जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था. एक ऐसी क्राइम स्टोरी, जो दुनिया भर के अख़बारों में कई दिनों तक सुर्ख़ियां बनी. आस्ट्रिया निवासी एक पापी पिता जोश फ्रिट्ज ने अपनी बेटी को चौबीस साल तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान उसके साथ बलात्कार करता रहा. उसके अपनी बेटी से सात बच्चे भी पैदा हुए. जब पुलिस ने जोश फ्रिट्ज को गिरफ़्तार करके उसकी बेटी और बच्चों को आज़ाद कराया तो पूरा विश्व सन्न रह गया था. यह एक साधारण अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसे जुर्म की दास्तां थी, जिसने दुनिया भर के लोगों में पापी पिता के ख़िलाफ घृणा भर दी. जब एमा डोनोग का उपन्यास रूम बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ तो पश्चिमी देशों के अख़बारों ने एमा डोनोग पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने उपन्यास का प्लॉट जोश फ्रिट्ज के जुर्म की कहानी से उठाया है. यह भी आरोप लगा कि उस कहानी में थोड़ा-बहुत बदलाव करते हुए लेखिका ने उसे अपनी शैली में पेश कर दिया है, लेकिन एमा समीक्षकों और साथी लेखकों के इन आरोपों से ज़रा भी विचलित नहीं हुईं. ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उपन्यास लिखते वक़्त इस बात का अंदाज़ा था कि उन पर इस तरह के आरोप लग सकते हैं, लिहाज़ा उन्होंने उपन्यास के अंत में उसके पात्र से इसका जवाब दिलवा दिया. एक जगह जब एक वकील जैक की मां को सलाह देता है कि वह अपनी कहानी लिख दे तो वह जवाब देती है कि आप क्या चाहते हैं, कोई हमें बेचे, उसके पहले हम ख़ुद ही अपने आप को बेच दें?

एमा डोनोग पर चाहे जो भी आरोप लगे हों, लेकिन उनका उपन्यास रूम कई हफ्तों तक बेस्ट सेलर की सूची में बना रहा और बुकर के लिए नामांकित होने के पहले और बाद में भी उसकी जमकर चर्चा हुई, बल्कि ज़बरदस्त बिक्री भी हुई. दरअसल यह कहानी एक पांच साल के बच्चे जैक की है, जिसकी मां को उन्नीस साल की उम्र में ओल्ड निक नामक एक शख्स अगवा कर लेता है. इसके बाद वह उसे ग्यारह वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे में बंधक बना लेता है. लेखिका जिसे रूम कहती हैं, दरअसल वह एक कैदखाना है, जहां न तो बाहरी दुनिया से संपर्क का कोई साधन है और न कोई रास्ता, जिससे बाहर की दुनिया को देखा जा सके. ओल्ड निक रोज रात को उस महिला के साथ

वह अपने बेटे की परवरिश इस तरह करती है कि जैक यह समझता है कि दुनिया तो सिर्फ़ रूम के अंदर ही है. जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है कि सारी कहानी जैक के इर्द-गिर्द चलती है और लेखिका ने भाषा भी पांच साल के बच्चे जैसी चुनी है. एमा डोनोग पर आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि इस पूरे उपन्यास में मां का नाम तक किसी को पता नहीं चलता. अगर लेखिका जोश फ्रिट्ज की कहानी को भुनाना चाहती तो केंद्रीय पात्र वह महिला होती, न कि उसका पांच साल का बेटा जैक. अगर उपन्यास उस युवा महिला, जिसे सात साल तक कमरे में बंद कर हर रोज बलात्कार किया जाता है, को केंद्र में रखकर लिखा जाता तो बिक्री ज़्यादा हो सकती थी.

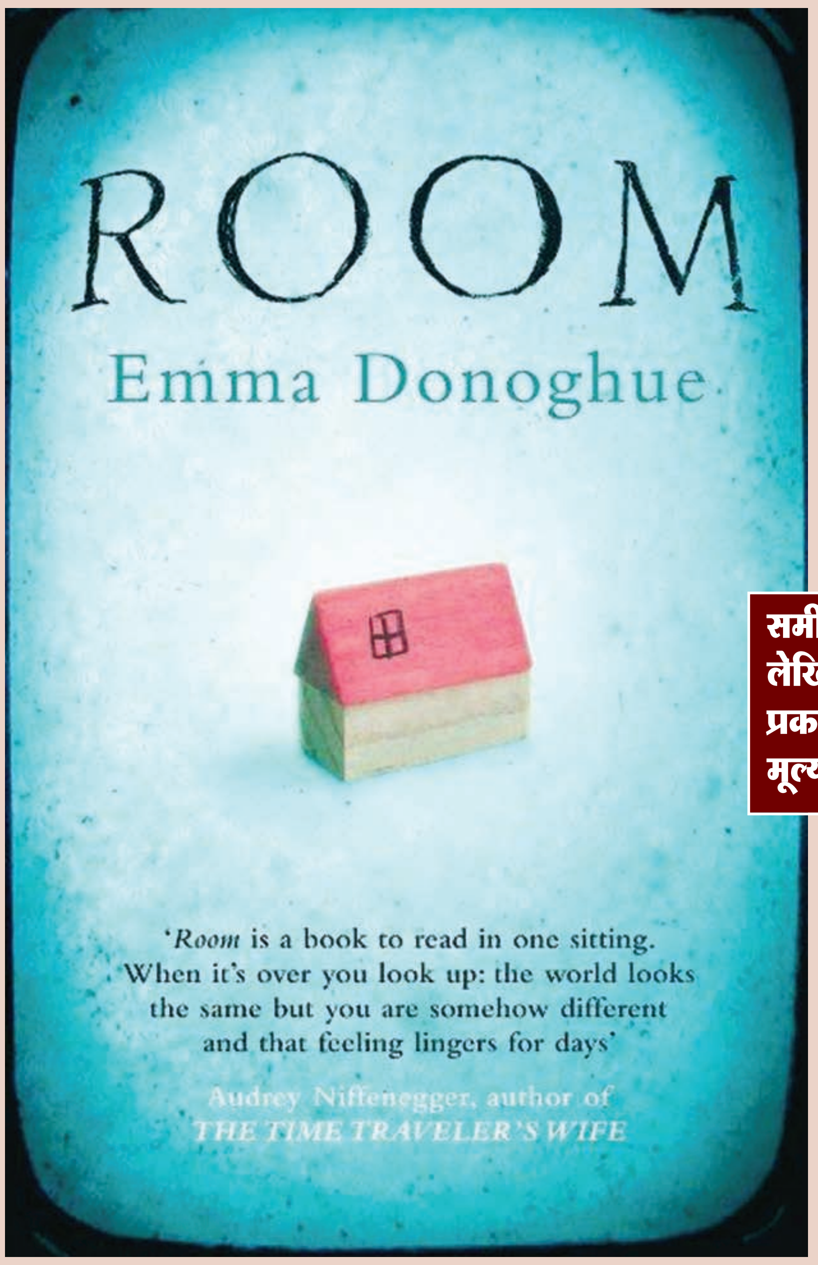

बलात्कार करता है और वह चुपचाप उसे सहन करती है. लेकिन तक़रीबन दो साल बाद जब जैक पैदा होता है तो उसकी दुनिया थोड़ी बदल जाती है. यह पूरा उपन्यास जैक के इर्द-गिर्द ही घूमता है. जैक को हर रोज अपनी मां के साथ होने वाले बलात्कार की जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ओल्ड निक जब रात को कमरे में आता है तो मां अपने बेटे को अलमारी में सुलाकर बंद कर देती है. उसे इस बात का एहसास नहीं होने देती कि उस पर हर रोज क्या गुजरती है.

मां-बेटे जिस छोटे से कमरे में रहते हैं, वहां दरी, बेड, वॉर्डरोब, टीवी एवं लैंप सब कुछ मौजूद है. टीवी पर जब मां-बेटे बाहर की दुनिया को देखते हैं तो जैक की मां उसे यह समझा देती है कि वह सब कुछ नकली और काल्पनिक है. टीवी पर दिखने वाली कहानियां दूसरी दुनिया की कहानी है. वह अपने बेटे की परवरिश इस तरह करती है कि जैक यह समझता है कि दुनिया तो सिर्फ़ रूम के अंदर ही है. जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है कि सारी कहानी जैक के इर्द-गिर्द चलती है और लेखिका ने भाषा भी पांच साल के बच्चे जैसी चुनी है. एमा डोनोग पर आरोप लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि इस पूरे उपन्यास में मां का नाम तक किसी को पता नहीं चलता. अगर लेखिका जोश फ्रिट्ज की कहानी को भुनाना चाहती तो केंद्रीय पात्र वह महिला होती, न कि उसका पांच साल का बेटा जैक. अगर उपन्यास उस युवा महिला, जिसे सात साल तक कमरे में बंद कर हर रोज बलात्कार किया जाता है, को केंद्र में रखकर लिखा जाता तो बिक्री ज़्यादा हो सकती थी. वजह यह कि उसमें जहालत और दर्द के अलावा सेक्स प्रसंग भी बहुतायत में होते. यहां तो पूरे उपन्यास में महिला का नाम तक नहीं पता चलता. वह तो सिर्फ़ मां है, जिसकी दुनिया उसका बेटा जैक है. लेकिन एमा बंद कमरे में एक मां के दर्द को बग़ैर लिखे इस तरह पेश करती है और पाठकों को चुनौती देती है कि वे जो नहीं लिखा गया है, उसे महसूस करें. यह शैली ही इस उपन्यास की ख़ूबसूरती है.

अचानक एक दिन जैक की मां को एहसास होता है कि ओल्ड निक उसके बेटे में भी रुचि लेने लगा है. यह एहसास होते ही उसके दिमाग़ में ख़तरे की घंटी बजती है. आसन्न ख़तरे को भांपते हुए वह कैदखाने से निकल भागने की योजना बनाती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है. जब वह और उसका बेटा जैक कैद से आज़ाद होकर बाहर की दुनिया में आते हैं तो उपन्यास की कहानी में एक ज़बरदस्त और नाटकीय मोड़ आता है. कहानी अचानक एक बंद कमरे से निकल कर दुनियादारी की आगोश में समा जाती है. बचपन से जैक की कंडीशनिंग इस तरह हुई कि उसके लिए तो सिर्फ उसकी मां हक़ीक़त है, बाक़ी सब कुछ काल्पनिक. लेकिन जब वह बाहर की दुनिया को देखता है तो उसे ज़बरदस्त झटका लगता है. वह यह समझ ही नहीं पाता है कि दूसरी दुनिया में कैसे रह पाएगा. जब उसकी मां उसके अलावा अन्य लोगों से प्यार भरी बातें करती है या उन्हें समय देती है तो जैक खिन्न हो जाता है. जैक के द्वंद्व का चित्रण करते हुए भी एमा डोनोग ने पाठकों को निराश नहीं किया. लेखिका यहां भी जैक की आज़ाद और मासूम नज़र से दुनिया को देखना और महसूस करना शुरू कर देती हैं. जैक और उसकी मां बाहर की दुनिया को देखते-समझते हुए उसमें ख़ुद को ढालने की भी कोशिश करते हैं. हर पल कहानी में उतार-चढ़ाव आता रहता है. इन पलों को चित्रित करते हुए एमा इमोशंस का इस्तेमाल इस तरह करती हैं कि कहानी पाठकों को बांधे रखती है. कहानी में मां-बेटे के बीच का एक ऐसा प्यार और अटूट रिश्ता सामने आता है, जो इस रिश्ते को एक नया आयाम तो देता ही है, संभावनाओं के नए द्वार भी खोलता है. उपन्यास के अंत में जैक एक बार फिर वापस उस रूम में जाता है और अपने सामान को गुडबॉय कहता है-गुडबॉय फ्लोर, गुडबॉय वॉर्डरोब आदि. यहां भी लेखिका ने जैक के हवाले से बाल मन की संवेदना को एक नई ऊंचाई दी है.

समीक्ष्य कृति-रूम
लेखिका-एमा डोनोग
प्रकाशक-पिकाडोर
मूल्य-499 रुपये

अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कहानी नहीं, बल्कि उसके कहने की शैली और मां-बेटे के प्यार का जो एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया है, वही इसकी ताक़त है और भरपूर बिक्री का आधार भी. लोग ग़लतफहमी में इसे क्राइम स्टोरी समझ रहे हैं. दरअसल यह क्राइम स्टोरी न होकर मां-बेटे के रिश्ते की मज़बूती की एक नई इबारत है. कहीं-कहीं इसे पढ़ते हुए पाठकों को तकलीफ होती है, लेकिन अंततः यह कहानी संतोष देती है.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है

पाकिस्तान के मशहूर शायर एवं नाटककार अमजद इस्लाम अमजद पिछले दिनों भारत में थे. वह यहां एक सेमिनार में हिस्सा लेने आए थे. इस दौरान चौथी दुनिया (उर्दू) की संपादक वसीम राशिद ने उनसे एक लंबी बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:

अमजद साहब, भारत की धरती पर आपका स्वागत है. हमें अपने बारे में कुछ बताएं...

मैं 4 अगस्त, 1944 को लाहौर में पैदा हुआ. मेरे माता-पिता सियालकोट के थे. मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुस्लिम मॉडल हाईस्कूल लाहौर में हुई. इस्लामिया कॉलेज से मैंने बीए किया और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए. मैंने कॉलेज से ही लिखना शुरू कर दिया था. एमए तक पहुंचते-पहुंचते मैं पंजाब विश्वविद्यालय में लिट्रेरी सोसाइटी का चेयरमैन बन गया. अगले साल उसकी पत्रिका महविर का संपादक बन गया. साहित्य के साथ मेरा संबंध विद्यार्थी जीवन से हो गया था. मेरी पहली कविता 1966 में फ़न्नून में प्रकाशित हुई, जिसे अहमद नदीम क़ासमी निकालते थे.

ऐसा क्या हुआ कि आप शायरी करने लगे?

अदब में कुछ बातें बहुत प्रचलित हैं. मसलन यह कहा जाता है कि अगर चोट लगे, तभी शायरी होती है. यह एक बेबुनियाद बात है. असल बात यह है कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं. इसका संबंध शायरी के क्राफ्ट से है. शायरी की कला यह है कि आपके अंदर और बाहर जो दुनिया है, उसके अनुभव एवं एहसास क्या हैं, क्या वे आपके अंदर रचनात्मक उत्साह पैदा करते हैं, क्या उन्हें आप एक नई शक्ल देने की कोशिश करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं और उसमें कामयाब हैं तो वही शायरी है.

आपने बचपन में किसके शेर सुने, जिनसे प्रभावित होकर आपने शायरी की, क्या शायरी स्वाभाविक अमल है?

जैसा कि मैंने कहा कि मुझे शुरू में ही एक पत्रिका का संपादक बना दिया गया. यह उम्र सीखने की होती है. जैसे कोई बच्चा गाना गाता है, जिसे आगे चलकर गायक बनना होता है, तो वह शुरू में ही मशहूर गायकों-गानों की नक़ल करने लगता है. इससे पता चलता है कि वह सुर में है. फिर वह अपने सुर की रचना करने लगता है. शायरों की भी शुरुआत इसी तरह होती है. वे जिन शायरों से प्रभावित होते हैं या जो शायरी उन्होंने पढ़ी होती है या जो शायरी उस उम्र में उनकी समझ में आती है, वे उसे नक़ल करने की कोशिश करते हैं. उसे हम मश्क़-ए-सुख़न कहते हैं. टी एस एलिट का एक अहम नज़रिया है कि 25 साल तक की उम्र तक हर बंदा शायर होता है. बच्चे के अंदर अगर यह स्वाभाविक रुझान हुआ और क्षमता हो तो इसका नमूना या इज़हार बचपन से ही किसी न किसी हवाले से होना शुरू हो जाता है. जब मैं ग्यारहवीं या बारहवीं कक्षा में आया तो उस ज़माने में मुझे रोमांटिक शायरों में जिगर साहब बहुत अच्छे लगते थे. इंक़लाबी शायरों में साहिर लुधियानवी बहुत पसंद थे. आगे चलकर यह नहीं कि शायर छोटे हो गए, बल्कि मैं उनसे आगे बढ़ गया और फिर वह बात जो साहिर के यहां सीधे तौर पर होती थी, जिसमें कशिश तो होती थी, लेकिन गहराई नहीं होती थी, वह अशद और फैज़ साहब के यहां ज़्यादा बेहतर और गहराई में नज़र आई. मुझे जो शोहरत मिली है, वह रोमांटिक शायर के तौर पर मिली है, लेकिन मैंने सिर्फ़ रोमांटिक शायरी नहीं की, बल्कि ज़माने की शायरी भी की. हमारे यहां एक ग़लत रिवाज चलन में है कि किसी आदमी को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं देखा जाता, एक शायर को पूरे व्यक्तित्व में पढ़ना चाहिए.

पिछले दिनों मैं बंगलौर के एक मुशायरे में गया तो देखा कि वहां 70 शायर मंच पर बैठे हुए थे. ऐसे में एक आम आदमी, जिसे सुबह अपने ऑफ़िस भी जाना है, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा. नतीजे में मुशायरे में ऐसे सुनने वाले आएंगे, जो बहुत लंबा वक़्त दे सकते हैं.

अपनी शुरुआती शायरी के कुछ नमूने सुनाएं?

मेरी एक कविता मोहब्बत शीर्षक से है, जो शुरुआती दिनों की है और तबसे आज तक मशहूर है. मेरी एक ग़ज़ल स्वर्गीय इक़बाल बानो ने गाई है, जो बहुत मशहूर हुई, उसका पहला शेर सुनाता हूं:

दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है.
इतना बे सिम्त न चल, लौट के घर जाना है.

अब तक आपकी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं?

एक हम्द व नात और सलाम का असबाब और बाक़ी मेरी कविताओं और ग़ज़लों के संग्रह हैं. इनमें से मेरी पहली किताब बरज़ख़ केवल कविताओं की है. इसके अलावा मेरी ग़ज़लों का संग्रह अलग छपा है. मेरी कुल 57 किताबें आ चुकी हैं, एक किताब और पूरी होने वाली है-तो पानी कम नहीं होता.

लाहौर में ज़्यादातर लोग पंजाबी में बातचीत करते हैं, ऐसे में उर्दू की तरक़्क़ी की वजह?

पाकिस्तान के लगभग 90 प्रतिशत घरों में लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उर्दू में भी बात करते हैं और बारहवीं कक्षा तक उर्दू एक अनिवार्य विषय है. इससे यह बात साबित होती है कि पाकिस्तान में, ख़ासकर लाहौर में उर्दू का भविष्य रोशन है.

भारत और बाहर के मुशायरों में क्या फ़र्क़ पाते हैं?

हमने मुशायरे को बुनियादी तौर पर फेस्टिवल बना लिया है. पिछले दिनों मैं बंगलौर के एक मुशायरे में गया तो देखा कि वहां 70 शायर मंच पर बैठे हुए थे. ऐसे में एक आम आदमी, जिसे सुबह अपने ऑफ़िस भी जाना है, कैसे बर्दाश्त कर पाएगा. नतीजे में मुशायरे में ऐसे सुनने वाले आएंगे, जो बहुत लंबा वक़्त दे सकते हैं. इंसानी ज़हन की जो तहक़ीक़ की गई है, इस नतीजे पर पहुंची है कि वह मुश्किल से किसी चीज़ पर दो-ढाई घंटे तक अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है.

जब आप ऐसे शहरों में जाकर मुशायरा पढ़ते हैं, जहां उर्दू नहीं बोली जाती तो आपको कैसा महसूस होता है?

उर्दू दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन जहां तक इसकी स्क्रिप्ट का सवाल है, यह दुनिया की पहली 30 भाषाओं में भी नहीं आती. इतना अंतर किसी और भाषा में नहीं है. अगर आने वाली नस्लें अपनी स्क्रिप्ट से परिचित नहीं होंगी तो यह बोली से पहले भाषा बनी थी और फिर भाषा से बोली बन जाएगी. इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए. भारत में मुशायरा उर्दू की सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है. कमोबेश पाकिस्तान में भी यही स्थिति है, लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी मुशायरे हो रहे हैं, वे दरअसल वहां के खाते-पीते लोगों की तफ़रीह का हिस्सा हैं.

वे कौन से गीत हैं, जो आपने भारतीय फिल्मों के लिए लिखे?

असल में फिल्मों के लिए लिखे नहीं, वे फिल्मों में आ गए. मैंने एक गीत नुसरत फ़तेह अली ख़ां के लिए लिखना शुरू किया था, लेकिन उनका देहांत हो गया. राहत मेरे पास आए और कहा कि गीत यह मुझे दे दीजिए. इसके बाद उन्होंने यह गीत गाया और हिंदुस्तानी फिल्म पाप में भी यह शामिल हो गया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ. इसके बोल हैं, लगन लागी मन की लगन. फिर एक और फ़िल्म सदियां में अदनान सामी और सुनिधि चौहान ने गाया. इसी तरह जगजीत जी ने मेरी गई ग़ज़लें गाई हैं. मुझे और भी ऑफर आ रहे हैं. पाकिस्तान में मैंने 6 फिल्में लिखी हैं. वहां पिछले 30 सालों में कोई भी गायक ऐसा नहीं है, जिसने मेरी चीज़ें न गाई हों.

editorurdu@chauthiduniya.com

दिल्ली, 07 फरवरी-13 फरवरी 2011 चौथी दुनिया

ख़ास कंप्यूटर

आधुनिक पढ़ाई में कंप्यूटर अहम हो गया है. इसकी पहुंच शहर ही नहीं, गांवों में भी हो रही है. स्कूल छोटा हो बड़ा, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देना अनिवार्य सा बन गया है. इस वजह से देश में कंप्यूटर का बाज़ार बढ़ता जा रहा है. कंप्यूटर सस्ते भी हो रहे हैं, पर इतने नहीं कि हर कोई उन्हें ख़रीद सके. लेकिन अब शायद यह संभव हो जाए. हैदराबाद की एक कंपनी ने आम लोगों तक कंप्यूटर पहुंचाने का ज़िम्मा उठाया है. कंपनी ने करिश्मा जैसा कर दिखाया है. हैदराबाद की कंपनी एलोका टेक्नोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने यह सस्ता ईको फ्रेंडली कंप्यूटर पेश किया है. इसमें वातावरण को नुक़सान न पहुंचाने वाली ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. यानी यह कंप्यूटर ऐसी तकनीक से लैस है, जिससे पर्यावरण को नुक़सान नहीं होगा. इसकी ख़ासियत है कि यह आकार में छोटा है और इसके इस्तेमाल में महज़ 5 वाट बिजली की खपत होती है. उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर बिजली न हो तो यह सौर ऊर्जा से चलता है. इसका वजन बहुत कम है, सिर्फ़ 100 ग्राम और इसमें एक जीबी स्पेस है. इसमें यूट्यूब, फेसबुक, गूगल डॉक्स और ऑडियो-वीडियो प्लेयर भी है. इसे किसी भी तरह के एलसीडी मॉनीटर से जोड़ा जा सकता है और यह छोटे से डिब्बे में समा सकता है. इसे मोबाइल फोन से जोड़कर इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. यह खास कंप्यूटर सिर्फ़ 5,000 रुपये का है. यह कंप्यूटर सिर्फ़ क़ीमत के लिहाज़ से नहीं, बल्कि तकनीक के कारण भी खास है. यह गांवों और छोटे शहरों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसके मेंटेनेंस में कोई समस्या नहीं है.

एलोका टेक्नोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने यह सस्ता ईको फ्रेंडली कंप्यूटर पेश किया है. इसमें वातावरण को नुक़सान न पहुंचाने वाली ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. यानी यह कंप्यूटर ऐसी तकनीक से लैस है, जिससे पर्यावरण को नुक़सान नहीं होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ड्राइंगरूम में सजेगा थ्री डी टीवी

थ्री डी टीवी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे देखने के लिए एक खास चश्मा लगाना पड़ता है और आप सपरिवार एक साथ बैठकर इसका आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि हर किसी को वह चश्मा चाहिए. लेकिन अब यह समस्या दूर होने वाली है. जापान की कंपनी तोशिबा ने एक ऐसा टेलीविज़न तैयार किया है, जिसकी ख़ासियत यह है कि थ्री डी होने के बावजूद उसे देखने के लिए किसी भी तरह का चश्मा नहीं लगाना पड़ता. इस टीवी का नाम है रेग्जा जीएल-1 सीरीज. तीस सेंटीमीटर के इस टीवी सेट में लिथवीड क्रिस्टल लगे हैं. कंपनी आगे इसे 50 सेंटीमीटर में भी बनाकर बाज़ार में उतारने की तैयारी में है. तोशिबा ने इसके लिए खास प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. रेग्जा जीएल-1 में आप 2 डी और थ्री डी दोनों फॉर्मेट बदल-बदल कर देख सकते हैं. कंपनी ने जापान में इसका दाम रखा है 1440 डॉलर यानी लगभग 66,000 रुपये. लेकिन भारतीय दर्शकों को इस टीवी से अपना ड्राइंगरूम सजाने में अभी थोड़ा वक़्त लगेगा.

आ गया सुपर फोन

मोबाइल फोन में लगातार नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं. नित नए फीचर्स और स्टाइल वाले मोबाइल फोन बाज़ार में आ रहे हैं. इस तर्ज पर आगे बढ़ते हुए कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी ने मोबाइल फोन की दुनिया में सनसनी मचा दी है. कंपनी ने एक ऐसा फोन पेश किया है, जिसे सुपर फोन का नाम दिया गया है. लास वेगास में कंपनी ने एलजी ओपटिमस-2 एक्स को एनविडिया कंपनी के साथ मिलकर पेश किया. इस फोन में नेक्स्ट जेनरेशन चिप (प्रोसेसर) टेगरा-2 लगा हुआ है. दरअसल इस चिप का इस्तेमाल टेबलेट पीसी में किया जाता है. इस चिप के कारण इस स्मार्ट फोन की क्षमता कहीं ज़्यादा हो गई है.

एनविडिया के सीईओ जेन सुन हुआंग का कहना है कि यह सुपर चिप लगाते ही फोन की स्पीड और कंटेंट में वृद्धि हो जाती है, साथ ही इससे वीडियो को स्टोर करके रखने की क्षमता भी कई गुनी बढ़ जाएगी. मोबाइल गेमिंग के शौकीनों के लिए यह बेहतरीन फोन साबित होगा. हालांकि कंपनी की तरफ़ से इस फोन की क़ीमत के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है. बहुत शीघ्र यह बाज़ार में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा.

ख़ूबसूरत कार

कार सिर्फ़ एक वाहन नहीं, बल्कि लोगों के स्टेटस, शौक और लाइफ स्टाइल की प्रतीक भी है. इसलिए अब कार के स्टाइल और सौंदर्य पर भी खासा ध्यान दिया जाने लगा है. यूं तो आज बाज़ार में रॉल्स रॉयल्स, लैंबोर्गिनी, फरारी और बेंटली जैसी एक से बढ़कर एक कारें मौजूद हैं, जो टेक्नोलॉजी और आराम के मामले में तो बेहतरीन हैं ही, लुक के मामले में भी इनके जादू से बचना मुश्किल है.

लेकिन हम आपको उस कार के बारे में बता रहे हैं, जिसे दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत कार के तौर पर जाना जाता है. यह कार है अल्फा रोमियो 8-सी कंपेटीजियोन. इसे दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत कार के तौर पर पहचान मिली है. इसमें टियरड्रॉप विंडो, आल्मंड हेडलैंप जैसे बेहतरीन लुक वाले फीचर्स मौजूद हैं. इतना ही नहीं, इसके पहियों को भी दुनिया के दस सबसे बेहतरीन पहियों की सूची में जगह मिली है. इस कार में खास तौर पर बनाए गए 20 इंच के टायरों का इस्तेमाल किया गया है. इसके रिम काफी बेहतरीन हैं. यह कार टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है. इसके ब्रेक्स लाजवाब हैं. 97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने के बावजूद सिर्फ़ 32 मीटर की दूरी पर इसे रोका जा सकता है. इस कार की ऑफिशियल टॉप स्पीड है 292 किलोमीटर प्रति घंटा. रोड एंड ट्रैक मैग्ज़ीन के मुताबिक़, इसकी अधिकतम रफ्तार 306 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस शानदार कार की क़ीमत क़रीब 1.20 करोड़ रुपये है.

अल्फा रोमियो 8-सी कंपेटीजियोन दुनिया की सबसे ख़ूबसूरत कार के तौर पर पहचान मिली है. इसमें टियरड्रॉप विंडो, आल्मंड हेडलैंप जैसे बेहतरीन लुक वाले फीचर्स मौजूद हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

मुंबई में जब निरूपम यह बयान दे रहे थे, तब ख़ुद सचिन भी वहां मौजूद थे. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि सचिन भारत के रत्न ही नहीं, बल्कि अनमोल रत्न हैं.

भारत रत्न और सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट अगर हिंदुस्तान का धर्म है तो सचिन क्रिकेट की दुनिया के भगवान. ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है इस देश में. ज़ाहिर है, एक देश के करोड़ों निराश लोगों को ख़ुशी के जितने पल सचिन रमेश तेंदुलकर ने दिए हैं, उतने शायद किसी ने नहीं. भ्रष्टाचार और घोटालों की ख़बरें सुन-सुनकर ऊब चुकी जनता के लिए यह ख़बर सावन की रिमझिम फुहार से कम नहीं थी. पद्म पुरस्कारों की घोषणा होनी थी, इसी बीच 25 जनवरी को एक ख़बर मीडिया में आई कि देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न सचिन को मिल सकता है. सचिन को चाहने वालों के लिए यह एक बड़ी ख़बर थी. लता मंगेशकर भी चाहती हैं कि क्रिकेट के इस भगवान को भारत रत्न मिले. ख़ुद सचिन भी गाहे-बगाहे मीडिया से यह कहते रहे हैं कि यदि यह सम्मान मिला तो उन्हें ख़ुशी होगी. अफवाहों को अगर पुष्ट ख़बर न भी मानें तो ऐसे ख़बरें आईं कि कई नेताओं और जाने-माने लोगों ने सचिन को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया और ख़ुद भी यह मांग रखी. गणतंत्र दिवस समारोह से सिर्फ़ 48 घंटे पहले कांग्रेस सांसद संजय निरूपम ने कहा कि इस सम्मान के लिए उनकी पार्टी ने सचिन के नाम की भरपूर वकालत की है. मुंबई में जब निरूपम यह बयान दे रहे थे, तब ख़ुद सचिन भी वहां मौजूद थे. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि सचिन भारत के रत्न ही नहीं, बल्कि अनमोल रत्न हैं.

सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, इस पर मीडिया में भी बहस हुई. आमतौर पर राष्ट्रीय मीडिया ने जनता की नब्ज़ को भांपते हुए सचिन के समर्थन में उतरने में ही अपनी भलाई समझी. लेकिन इस सबके बीच इस तथ्य की ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया कि अब तक यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया गया. अब तक भारत रत्न से सिर्फ़ उन्हीं महापुरुषों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कला, साहित्य, वैज्ञानिक उपलब्धि और जनसेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो अथवा जिनके कार्यों से देश की सेवा हुई हो. इस लिहाज़ से अब तक किसी भी खिलाड़ी को भारत रत्न सम्मान नहीं मिल सका है. ऐसे में सवाल उठता है कि तब सचिन को यह सम्मान क्यों दिया जाना चाहिए. अगर खेल के क्षेत्र से ही किसी को इस सम्मान के लिए चुनना हो तो पहले मेजर ध्यानचंद क्यों नहीं? हॉकी तो फिर भी हमारा राष्ट्रीय खेल है. और फिर उनके योगदान को कौन भूल सकता है, उनकी प्रतिभा को कौन चुनौती दे सकता है, जिनकी हॉकी तोड़कर देखी गई कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगा है, क्योंकि विपक्षी खिलाड़ी उनसे गेंद छीन ही नहीं पाते थे.

सवाल कुछ और भी हैं, जो सचिन के विरोध में नहीं, बल्कि भारत रत्न जैसे सम्मान को बचाए रखने से जुड़े हैं. मसलन, सचिन के पास अभी इतना वक़्त है कि वह भारत रत्न जैसे सम्मान के लिए थोड़ा और इंतज़ार कर सकते हैं. उम्र के लिहाज़ से अभी भी कई लोग हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया जा सकता है. यही वजह है कि सरकार भी सचिन को यह सम्मान देने से हिचक रही है. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सचिन खेल के अलावा उन तमाम ब्रांडों का विज्ञापन भी करते हैं, जो यदा-कदा विवादों में आते रहे हैं. अमूमन इस तरह के सम्मान से सम्मानित होने वाली हस्तियों से यह अपेक्षा होती है कि वह न तो ख़ुद विवादित रहे हों और न किसी विवाद से उनका कोई नाता हो. एक और सवाल, क्या हमारे देश के लिए क्रिकेट वाकई इतना महत्वपूर्ण हो चुका है? ऐसा क्रिकेट, जिसे टीम इंडिया भले ही कहा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह टीम बीसीसीआई की है. वह बीसीसीआई, जिसके दामन पर आईपीएल घोटाले से लेकर अपारदर्शी संस्था होने तक का आरोप लगा है.

ख़ैर, यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एक संवेदनशील इंसान और बेहतरीन खिलाड़ी होने के नाते सचिन ख़ुद आगे बढ़कर इस तरह की चर्चाओं को क्लीन बोल्ड कर देंगे. अगर सचिन ऐसा करते हैं तो बिना भारत रत्न मिले भी वह हम सबके लिए किसी भारत रत्न विभूति से कम नहीं होंगे.

सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं, इस पर मीडिया में भी बहस हुई. आमतौर पर राष्ट्रीय मीडिया ने जनता की नब्ज़ को भांपते हुए सचिन के समर्थन में उतरने में ही अपनी भलाई समझी. लेकिन इस सबके बीच इस तथ्य की ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं गया कि अब तक यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को नहीं दिया गया. अब तक भारत रत्न से सिर्फ़ उन्हीं महापुरुषों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने कला, साहित्य, वैज्ञानिक उपलब्धि और जनसेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किया है या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो अथवा जिनके कार्यों से देश की सेवा हुई हो.

शशि शेखर
shashishekhar@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

बॉलीवुड की कुछ ही फिल्में ऐसी हैं, जो उन्हें पसंद हैं. बॉलीवुड फिल्मों के कुछ रोमांटिक दृश्य उन्हें भुलाए नहीं भूलते.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

तक़दीर और तदबीर

सोनाक्षी सिन्हा अब सिल्वर स्क्रीन का जाना-माना चेहरा हैं. वह कहती हैं, सिनेमा में आने से मेरे निजी जीवन पर कोई खास फ़र्क़ नहीं पड़ा. मैं जैसी पहले थी, वैसी ही आज भी हूं. लाइफ स्टाइल में भी ज़्यादा फ़र्क़ नहीं आया है. लाइफ स्टाइल वही है, जिसमें अपने आप को सहज महसूस कर सकूं. चूंकि अब मैं ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ चुकी हूं, इसलिए मेरा अपने लुक को लेकर खास ध्यान है. मैं ख़ुद पर नए-नए स्टाइल्स अपनाने की कोशिश करती रहती हूं और फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूं. अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूं. इसके लिए योगा एवं डाइटिंग कर रही हूं. मैं जिम भी जाती हूं. दरअसल मुझे स्लिम-ट्रिम होने के लिए सबसे ज़्यादा सलमान ख़ान ने प्रोत्साहित किया. उन्होंने कहा कि तुम पतली हो जाओ, फिल्मों में तुम्हारा अच्छा स्कोप है. तब मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, उसके बाद मैंने लैक्मे की मॉडलिंग भी की. कपड़ों के प्रति कोई खास पसंद नहीं है मेरी, मैं बस वह पहनना पसंद करती हूं, जो मुझ पर सूट करता है. मुझे रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा एवं नीता लुल्ला द्वारा डिज़ाइन की गई ड्रेसेज पसंद हैं. कई बार मैं उनके डिज़ाइन किए कपड़े बहुत शौक से ख़रीदती हूं. मैं म्यूज़िक सुनती हूं, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है. इसके अलावा फैशन से संबंधित क्रिएटिव काम करना पसंद करती हूं. मुझे डांस का शौक है, तेज म्यूज़िक लगाकर डांस भी करती हूं. खाली वक़्त में पसंदीदा लेखकों की किताबें पढ़ती हूं. जीवन से मैंने सीखा है कि तकदीर अगर हमारा साथ न दे तो तदबीर भी कुछ नहीं कर पाती.

छोटी-छोटी बातों में ख़ुश

कमल हसन की बेटी श्रुति अब किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. अपनी पहली फिल्म लक से ही श्रुति ने एक अलग पहचान बना ली है. एक बार फिर वह अपनी क़िस्मत आजमाने आ रही हैं मधुर भंडारकर की फिल्म *दिल तो बच्चा है जी में*. इसे लक ही कहा जाएगा कि उन्हें मधुर भंडारकर के साथ काम करने का अवसर दोबारा मिला. वह कहती हैं, मैं अपने डेस्टिनी स्टार्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिनकी वजह से मैं मधुर के इस प्रोजेक्ट में एक अहम रोल की हकदार बनी. इस फिल्म में उन्होंने निक्की नामक एक ऐसी लड़की का रोल किया है, जो अमेरिका से लौटी है और काफी यंग है. वह समाजसेवा में यक़ीन रखती है. आज के वक़्त के हिसाब से वह काफी पढ़ी-लिखी, मॉडर्न, स्मार्ट और अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर है. श्रुति कहती हैं कि मुझे निक्की का रोल अदा करते समय वाकई काफी मज़ा आया. निक्की का किरदार उनकी असल ज़िंदगी से मिलता-जुलता है. निजी जीवन में भी वह एक यंग, एनर्जेटिक और बबली गर्ल हैं. उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसे हासिल करने के लिए क्या करना है. श्रुति बताती हैं, मुझे इस कैरेक्टर की एक और बात सबसे अच्छी लगी, वह यह कि निक्की का दिमाग़ काफी तेज है. जब मधुर ने मुझे निक्की का रोल ऑफर किया तो मैंने दोबारा नहीं सोचा. यह कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन यह फिल्म में काफी अलग, रोचक और अहम है. मेरे लिए इसे छोड़ना असंभव था, एक तो पसंद की वजह से, दूसरा फिल्म की स्टारकास्ट, डायरेक्टर और स्क्रिप्ट की वजह से. इस फिल्म की शूटिंग करते वक़्त मुझे काफी मज़ा आया. दिल तो बच्चा है जी के पहले फ्रेम से लेकर आख़िरी शूट, जब डायरेक्टर ने कहा चलो ख़त्म, तक सब कुछ काफी ताजातरीन था. मधुर इंडस्ट्री के सबसे काबिल निर्देशकों में से एक हैं और उनके साथ काम करना कुछ भाग्यशाली मौक़ों में से एक होता है. मैं बहुत ख़ुश हूं कि मुझे यह मौक़ा मिला, मैं छोटी-छोटी बातों में ख़ुश रहने वाली हूं.

शजान की पसंद

यशराज फिल्म्स के बैनर तले अपना करियर शुरू करने वाली शजान पद्मसी फिल्म *दिल तो बच्चा है जी में* नज़र आईं. इन दिनों उनकी क़िस्मत के सितारे ख़ूब चमक रहे हैं. एक तो पहली ही फिल्म यशराज बैनर तले इंडस्ट्री के मोस्ट हैपनिंग बैचलर स्टार के साथ और दूसरी भी इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टर के साथ, वह भी इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर के अपोजिट. अब उन्होंने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बना ली है. लेकिन इस हॉट बेब के क्या-क्या शौक हैं, आइए जानिए. शजान के आईपॉड में किसी बॉलीवुड फिल्म या गायक का गाना नहीं रहता, बल्कि उनका ऑल टाइम फेवरिट है हेड कांडी का संगीत और फिल्में भी उन्हें विदेशी ही पसंद हैं. बॉलीवुड की कुछ ही फिल्में ऐसी हैं, जो उन्हें पसंद हैं. बॉलीवुड फिल्मों के कुछ रोमांटिक दृश्य उन्हें भुलाए नहीं भूलते. वह कहती हैं कि उन्हें दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे का वह सीन बेहद पसंद है, जिसमें पैशनेट लवर राज सिमरन का करवा चौथ का व्रत खुलवाने के लिए उससे टेरेस पर मिलता है और अपने हाथों से खाना खिलाता है. अपनी इस पसंद से शजान काफी रोमांटिक मिजाज़ की लगती हैं. वह कहती हैं कि यही वह फिल्म है, जिसका वह हिस्सा बनना चाहती हैं. किस अभिनेता के साथ वह डेट पर जाना पसंद करेंगी? इस सवाल के जवाब में वह किसी बॉलीवुड हीरो का नहीं, बल्कि टॉम क्रूज का नाम लेती हैं, क्योंकि टॉम उन्हें अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और बढ़िया लुक्स की वजह से काफी क्यूट लगते हैं. पिता अलीक पद्मसी से एक्टिंग की प्रेरणा लेने वाली शजान का सबसे पसंदीदा डायलॉग है-अस्तालविस्ता बेबी. उन्हें हॉरर मूवीज वैसे तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन वे फिल्में उन्हें बहुत डराती हैं, जो किसी फिल्म का सिक्वल या रीमेक बनती हैं और हंसी का पात्र बन जाती हैं.

क़िस्मत पर निर्भर

इंडस्ट्री का क्यूट चेहरा अमृता राव इन दिनों फैशन शो, इवेंट्स और पार्टियों में ही नज़र आती हैं, लेकिन फिल्मों से वह दूर नहीं हुई हैं. विवाह में ट्रेडीशनल लड़की का रोल करने वाली अमृता राव एक बार फिर राजश्री के साथ काम कर रही हैं. आजकल वह लव यू मिस्टर कलाकार की शूटिंग में व्यस्त हैं. वह एक बार फिर सूरज बड़जात्या के साथ काम कर रही हैं. ज़ाहिर है, उनके साथ दोबारा काम करके वह बेहद ख़ुश हैं. कहती हैं, हमारी पिछली फिल्म विवाह हिट रही थी और आज भी चर्चा में है. ऐसे में उनके साथ काम करने से मैं कैसे इंकार कर सकती थी. मुझे एक बढ़िया फिल्म चाहिए थी, वह मुझे मिली, इसलिए मैं बेहद ख़ुश हूं. वैसे भी मैं किसी कैंप में विश्वास नहीं करती. मेरे लिए ऑफर किया गया रोल सबसे ज़्यादा मायने रखता है. मुझे नहीं पता कि दूसरी हीरोइनें नंबर वन की रेस में टॉप करने और फेमस होने के लिए क्या कर रही हैं, मैं सिर्फ़ अपने पर फोकस करती हूं. वैसे जहां तक मैं मानती हूं, आजकल इंडस्ट्री में नंबर 1-2-3 जैसी कोई चीज नहीं है. कई बार न्यूकमर्स आकर हिट्स दे देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे नंबर वन हो जाएं. फिर कोई नंबर वन एक्टर नीचे पायदान पर उतर कर दोबारा दो-तीन हिट देगा तो वह फिर से अपनी कुर्सी पर आ जाएगा. इसलिए मेरे खयाल से सब कुछ फिल्म निर्माताओं पर निर्भर करता है. अगर वे आपको भाव देंगे तो आप नंबर वन हो जाएंगे. हालांकि वास्तव में यह सब दर्शकों और कलाकारों की क़िस्मत पर निर्भर करता है. क्या करती हैं अमृता लीजर टाइम में? जवाब में वह बताती हैं, मैं खाली टाइम में पढ़ना, फिल्में देखना और दोस्तों से मिलना पसंद करती हूं. ज़ाहिर है, एक्टिंग के अलावा ये सब गतिविधियां आपको एक बेहतर एक्टर बनने में मदद करती हैं. वैसे मैं परिवार में घुलने-मिलने वाली इंसान हूं, इसलिए जब मैं घर पर होती हूं तो परिवार के आगे मेरे लिए कुछ भी महत्व नहीं रखता. दरअसल, असली अमृता मेरे सभी कैरक्टरों का मिश्रण है, जो मैंने अब तक निभाए हैं. मैं अभी तक सिंगल हूं और अपने लिए कोई पार्टनर नहीं खोज पाई हूं. मुझे लगता है, यह भी क़िस्मत पर ही निर्भर करता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

प्रीव्यू

पटियाला हाउस

फिल्म पटियाला हाउस का सारांश है जीवन में दूसरा मौक़ा मिलने पर अपने सपनों को पूरा करना, कहते हैं निर्देशक निखिल आडवाणी. इसमें अक्षय अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हुए क्रिकेटर बनते हैं. पटियाला हाउस एक ऐसे परिवार की कहानी है, जो चार पीढ़ियों से साउथ हॉल लंदन में रह रहा है. इस परिवार के मुखिया हैं बाबू जी (ऋषि कपूर), जिनके कुछ कायदे-क़ानून हैं, जिनका पालन करना परिवार के हर सदस्य के लिए अनिवार्य है, भले ही आप सहमत हों या नहीं. गोरों के देश में भी बाबू जी का परिवार भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत नज़र आता है. बाबू जी को अंग्रेजों और उनकी हर चीज से नफ़रत है. इसका कारण है 20 वर्ष पहले की एक घटना, जिसमें एक वरिष्ठ नेता एवं वकील मिस्टर सैनी की हत्या कर दी गई थी. सैनी को बाबू जी अपना आदर्श मानते थे. इस घटना के बाद वह ब्रिटिश शासन से चिढ़ने लगे. परिवार की नई पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन बाबू जी के प्रति प्यार और सम्मान की ख़ातिर उसे सपनों को एक तरफ़ रखना पड़ता है. परघट सिंह उर्फ गट्टू (अक्षय कुमार) एक उभरता हुआ तेज गेंदबाज है, जो इंग्लैंड की तरफ़ से क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन बाबू जी के कायदों की किताब में इसकी कोई जगह नहीं है. इस किरदार के लिए अक्षय ने बाकायदा एक गेंदबाज के तौर पर प्रशिक्षण

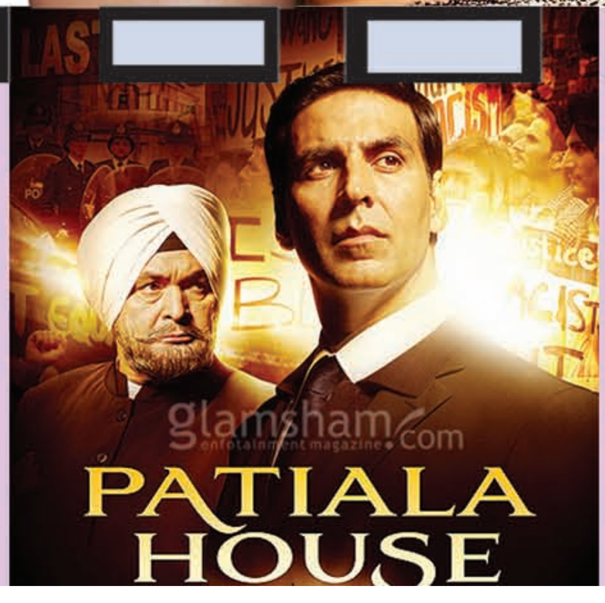

भी लिया. अक्षय के साथ कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर भी दिखाई देंगे. फिल्म में डिंपल कपाड़िया ने भी अभिनय किया है. अक्षय कुमार अपनी सास डिंपल कपाड़िया के साथ रुपहले पर्दे पर पहली बार नज़र आने वाले हैं. पटियाला हाउस इस साल रिलीज होने वाली अक्षय की पहली फिल्म होगी. डिंपल ने अक्षय की मां की भूमिका निभाई है. फिल्म का संगीत इसका मुख्य आकर्षण है. शंकर एहसान लॉय के संगीत से सजी फिल्म पटियाला हाउस में लगभग 12 गाने हैं. गीत-लौंग दा लस्कारा महालक्ष्मी अय्यर, हार्ड कौर एवं पॉप सिंगर जस्सी ने मिलकर गाया है. इनके अलावा सफकत अमानत अली, शंकर, अर्ल, मास्टर सलीम, विशाल ददलानी, सूरज जगन, लिसा, राज हंस और रिचा हंस ने भी अपनी आवाज़ का जादू चलाया है. जस्सी काफी दिनों के बाद वापसी कर रहे हैं. लौंग दा लस्कारा फिल्म का टाइटल गाना भी है. गीतकार अंविता दत्त गौतम हैं. पहले गाने के बाद रीमिक्स का दौर शुरू होता है, जिसमें क्या मैं जागूं बहुत ही मार्मिक है, जिसे गायक सफकत अमानत अली ने अपनी मधुर आवाज़ से दिलकश बना दिया है. इसके बाद रोला पी गया गीत को महालक्ष्मी अय्यर, हार्ड कौर, शंकर, अर्ल और मास्टर सलीम ने मिलकर गाया है. इसी तरह कई और भी गाने हैं जिनमें रीमिक्स का तड़का लगाया गया है. कुछ गाने तो मनोरंजक हैं और कुछ में पंच की ज़रूरत है. यह फिल्म आगामी 11 फरवरी को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

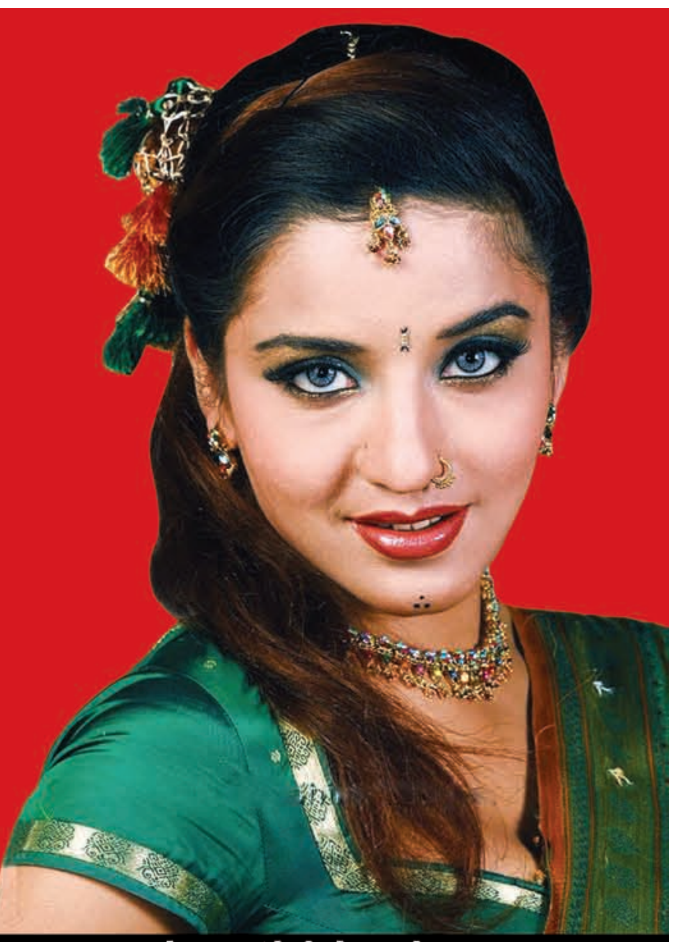

दिल्ली, 07 फरवरी-13 फरवरी 2011 www.chauthiduniya.com

कर्पूरी के बहाने पिछड़ा राग

कर्पूरी जयंती के बहाने अति पिछड़ों को रिझाने के लिए नीतीश और मोदी से लेकर लालू प्रसाद तक सभी ने लंबे-लंबे भाषण दिए. उनकी इस कोशिश से इतना तो साफ़ है कि वोट बैंक के बाज़ार में अति पिछड़ों का भाव काफ़ी चढ़ गया है. आने वाले दिनों में इसे लेकर जमकर राजनीति होगी, भले ही इससे अति पिछड़ों को कोई फ़ायदा हो या न हो.

सरोज सिंह

पिछले दिनों बिहार के बड़े नेताओं ने बड़ी शिद्दत से जननायक कर्पूरी ठाकुर को याद किया. शायद विधानसभा चुनाव का परिणाम इनको प्रेरित कर रहा था कि अति पिछड़ों का साथ ही जीत की गारंटी है और कर्पूरी जयंती के बहाने पिछड़ा राग अलापने से जो संदेश जाएगा, वह हर लिहाज़ से फ़ायदेमंद ही साबित होगा. यही वजह रही कि जदयू, भाजपा, राजद व लोजपा ने बड़े ही तामझाम से इस मौक़े को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. दरअसल नीतीश कुमार को मिले प्रचंड जनादेश में पिछड़ों व अति पिछड़ों की भूमिका से सभी नेता वाक़िफ़ हो चुके हैं. राजद व लोजपा ने चुनाव के बाद अपनी समीक्षा बैठकों में भी यह महसूस किया कि अतिपिछड़ों का जदयू व भाजपा की तरफ झुकाव उनको काफ़ी भारी पड़ा है. अगर ऐसा न हुआ होता तो नीतीश कुमार को सत्ता में वापस लौटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता. राजद सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि पिछड़े व अति पिछड़े हमेशा राजद के साथी रहे हैं. पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जो नीतीश के बहकावे में आ गए हैं या फिर किसी कारण से नाराज़ हैं, उन्हें हर हाल में दोबारा पार्टी के साथ ले आया जाए.

अब ज़रा कर्पूरी जयंती के दिन बड़े नेताओं के भाषणों पर एक नज़र डाल लें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पूरे तेवर में थे. अति पिछड़ों को गोलबंद करने में सफलता पा चुके नीतीश कुमार ने अपना तीर चलाते हुए कहा कि विधायिका में भी अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा में अति पिछड़ों की सीटें आरक्षित होनी चाहिए और इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए. एक क़दम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सेवाओं में भी अति पिछड़ों के लिए अलग से कोटा निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक दावा है और इसकी अब ज़रूरत है. नीतीश कुमार यह अच्छी तरह जानते हैं कि उनके विरोधी हरसंभव कोशिश करेंगे कि इस मज़बूत वोटबैंक को पहले तोड़ा जाए और उसके बाद इसे उनसे दूर कर अपने पाले में लाया जाए. यही वजह रही कि कर्पूरी जयंती के दिन ही नीतीश ने आरक्षण की मांग ज़ोर से उठा कर अपने विरोधियों को बैकफुट पर ला दिया. अति पिछड़ों को सत्ता का लाभ देने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाने की योजना है. सत्ता में इनकी उचित भागीदारी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है ताकि वे विरोधियों के किसी लोभ या प्रलोभन में न आ सकें. तैयारी ऐसी है कि अति पिछड़ों में सेंध लगाने की विरोधियों की कोई भी कोशिश पूरी तरह नाकाम हो जाए. इसी दिन लालू प्रसाद ने भी गहन मंथन के बाद अपने तरकश से कुछ तीर चलाए, जो उनके आगे की राजनीति की दशा व दिशा की तरफ इशारा करते हैं. उन्होंने कहा कि देश में राजनीति की एक ख़तरनाक डिजाइन चल रही है. हम इंसाफ़ की बात करते हैं तो लोग हमें जातिवादी कहते हैं. यह दुखद है कि आज के युवा मंडल की लड़ाई भूल गए हैं. उनको यह भी याद नहीं कि सामंतों के सामने उनके पूर्वजों को ज़मीन पर बैठना पड़ता था. आवाज़ तेज़ करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि हमने जातीय आधार पर जनगणना की बात की, तो लोग भला-बुरा कहने लगे. ऐसा कहने वालों को पता है कि बाबा साहेब अंबेदकर संविधान में आबादी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कर गए हैं. जनगणना में अनूसूचित जाति के साथ अति पिछड़ों की संख्या की वास्तविक जानकारी होगी और आरक्षण के कोटे को बढ़ाना होगा. लालू प्रसाद ने मंडल की बात की, अति पिछड़ों का कोटा बढ़ाने की बात की और पिछड़ों की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया. दरअसल जिस मंडल ने लालू प्रसाद को एक अदना नेता से बिहार का बेताज बादशाह बनाया और देश की राजनीति के खेल में रंग का गुलाम बनाया, उसे एक बार फिर वह यहां के युवकों को याद दिलाना चाहते हैं. लालू प्रसाद अति पिछड़ों को याद दिलाना चाहते हैं कि सामंतों ने उनके पूर्वजों को सम्मान नहीं दिया. विधानसभा चुनाव के परिणामों ने लालू प्रसाद को यह महसूस करा दिया कि अगड़ी जातियों को अपने पाले में लाने का उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया. यही वजह है कि वह अपने पुराने वोटबैंक की तरफ़ लौटना चाहते हैं. शायद यही लालू प्रसाद की ख़ासियत है कि वह बहुत जल्द अपने मुद्दे तय कर लेते हैं और उसे जनता की अदालत में ले जाकर बहस शुरू कर देते हैं. अति पिछड़ों का नीतीश के खेमे में जाना लालू को सता रहा है और इसी कारण से राजद ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसके बाद भाजपा कहां पीछे रहने वाली थी. कर्पूरी जयंती के बहाने इसने भी पिछड़ा राग अलापा. सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की कि अति पिछड़ों व महादलितों के लिए बिहार में जल्द ही अत्यंत पिछड़ा वित्त विकास निगम का गठन किया जाएगा. इसके ज़रिये यह जमात बैंकों से सहजता से ऋण प्राप्त कर अपना रोज़गार शुरू कर जीवन को खुशहाल कर सकेगी. उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने के लिए हर ज़िले में उनके नाम पर एक अति पिछड़ा कल्याण छात्रावास बनाया जाएगा. मोदी ने साफ़ किया कि भाजपा की सहमति से ही पंचायत चुनाव और सरकारी नौकरियों में अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिया गया. मतलब भाजपा चाहती है कि अगड़ों के साथ ही साथ पिछड़ों को भी अपने पाले में पूरी तरह रखा जाए ताकि जनाधार बढ़ सके. इसी तरह लोजपा नेताओं ने भी अति पिछड़ों को उनका वाजिब हक़ दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का ऐलान किया. रामचंद्र पासवान व पशुपति पारस ने कहा कि नीतीश सरकार समाज को तोड़ कर अपना उल्लू सीधा कर रही है. अति पिछड़ों के हालात और भी ख़राब हुए हैं. लोजपा हर कुर्बानी देकर उनके मान-सम्मान व हक़ की लड़ाई लड़ेगा. कर्पूरी जयंती के बहाने अति पिछड़ों को रिझाने के लिए इन चारों दलों की कोशिश से यह साफ़ है कि वोट बैंक के बाज़ार में अति पिछड़ों का भाव काफ़ी चढ़ गया है. आने वाले दिनों में इसे लेकर जमकर राजनीति होगी. भले ही इससे अति पिछड़ों को कोई फ़ायदा हो या न हो. एक बात जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी, जिनकी जयंती के बहाने यह सब हुआ. कर्पूरी जी ने हमेशा समाज को पूरी तरह सम्रगता में देखा. वह किसी एक जाति या वर्ग का विकास किसी दूसरी जाति व वर्ग की कीमत पर नहीं चाहते थे. अगर उन्होंने अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी तो अगड़ों के लिए भी आरक्षण चाहा. कर्पूरी चाहते थे कि एक गुलदस्ते की तरह बिहार खिले, जिसमें हर तरह के फूल हों. सबको रोज़ी-रोटी के साथ सम्मान मिले यह कर्पूरी का सपना था और इसके लिए उन्होंने जीवनभर लड़ाई लड़ी. आज उनको याद करने वाले नेताओं को भी कर्पूरी ठाकुर की इस भावना को समझना चाहिए. कुछ करने या बोलने से पहले उन्हें यह ज़रूर मनन करना चाहिए कि कर्पूरी यूं ही जननायक नहीं बन गए. उनकी सादगी देख बड़े से बड़े अंहकारी के भी सिर झुक जाते थे. एक बड़ी सोच व उसे ईमानदारी से पूरी करने की ललक ने कर्पूरी को जननायक बना दिया. चुनौतियों से जूझ रहे इस बिहार को फिर एक कर्पूरी का इंतजार है.

सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की कि अति पिछड़ों व महादलितों के लिए बिहार में जल्द ही अत्यंत पिछड़ा वित्त विकास निगम का गठन किया जाएगा. इसके ज़रिये यह जमात बैंकों से सहजता से ऋण प्राप्त कर अपना रोज़गार शुरू कर जीवन को खुशहाल कर सकेगी.

feedback@chauthiduniya.com

नर्सरी से पिछले दो वर्षों से पौधा ले जाने वालों की कमी हो गई है, जिसके कारण वन विभाग के इस नर्सरी में नए पौधे लगाने के लिए जगह की कमी हो गई है.

अभिकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है.

एक नज़र इधर भी

उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

फलों के उत्पादन में ज़िले को अग्रणी बनाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के प्रति विभाग पूरी तरह चौकस है. विभाग का प्रयास है कि आम, लीची, केला आदि के उत्पादन के मामले में ज़िला स्वावलंबी बने. इच्छुक किसान ज़िला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर कई हेक्टेयर भूमि में इन फलों के पौधे लगा रहे हैं. इसकी जानकारी देते हुए ज़िला उद्यान पदाधिकारी विजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में नई प्रजाति के केला, आम, लीची आदि की खेती 745 हेक्टेयर में कराने की योजना है. [illegible] 22 हज़ार 500 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है. [illegible] उपलब्ध कराई जाएगी.

गबनकर्ता रूद्रानंद धरे गए

अररिया ज़िले का घोटाला सरगना रूद्रानंद झा आख़िरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. इसके विरूद्ध ज़िले के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. [illegible] गिरफ़्तारी सहरसा ज़िले के सोनबर्षा पुलिस के सहयोग से पलासी पुलिस अररिया ने की. [illegible] ग्रामीण विकास विभाग की जांच टीम के द्वारा 26 करोड़ के मामले उजागर किए गये हैं. बताया जाता है कि घोटाले की राशि दोगुना भी हो सकती है. अब तक इन घोटालों को लेकर ज़िले में पदस्थापित 6 बीडीओ समेत एक दर्जन कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं. वहीं तत्कालीन डीडीसी साजिद अहमद तलहा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है. इन घोटालों की कड़ी में कई सफेदपोशों के नाम भी सामने आए हैं. जिनके ख़िलाफ़ निगरानी की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. *-विजयेन्द्र कुमार*

प्याज की तस्करी पकड़ी गई

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के जोगबनी अंतर्गत खुली सीमा क्षेत्रों से उर्वरक, नमक, चीनी समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ प्याज की भी तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है. हाल के दिनों में जहां नेपाली भंसार के चीनी राजस्व में काफी गिरावट आई है वहीं उर्वरक व प्याज की बढ़ती तस्करी से राजस्व में इजाफा होने की सूचना है. हालांकि, एसएसबी 24 बटालियन के जवान हरसंभव तस्करी पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं. एसएसबी के प्रभारी आरपी वर्मा के नेतृत्व में तस्करी पर लगाम लगाने का सफल प्रयास किया जा रहा है. नेपाल-भारत के पिलर सं.179/2 के रास्ते से तस्करी कर नेपाल ले जा रहे करीब आठ लाख रुपए की 350 बोरी प्याज को पकड़ने में एसएसबी के चौकसी कर रहे जवानों को भारी सफलता मिली है . *-दीप्ति भारती*

टीम वर्क से मिलेगी सफलता : डी.के. सिंह

सफलता पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता. एक बेहतर टीम वर्क और कड़ी मेहनत से ही मैं आगे बढ़ा हूं और जिसे भी आगे बढ़ना है उसे इसी रास्ते पर चलना होगा. हैरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड टूरिज्म के प्रमुख डी. के. सिंह ने बताया कि बिहार व झारखंड में होटल व्यवसाय की काफी संभावना है. हैरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड टूरिज्म कम ख़र्च पर छात्रों को बेहतर शिक्षा दे रहा है. मेरी कोशिश है कि बिहार व झारखंड की प्रतिभाओं को पूरा सम्मान मिले. इन दोनों राज्यों के काफी छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं और मैं चाहता हूं कि इन राज्यों के छात्रों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा मिल सके. इस दिशा में हैरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एण्ड टूरिज्म ने काफी अच्छा काम किया है और आगे भी बेहतर काम करने की कोशिश है. *-मोनिबा फातमा*

करोड़ों ख़र्च के बाद जलापूर्ति नहीं

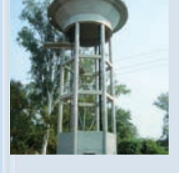

गया ज़िले के गुरूआ प्रखण्ड मुख्यालय समेत आसपास के गांव में पेयजल की समस्या को देखते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से करोड़ से अधिक रुपये ख़र्च कर जलमीनार तथा जलापूर्ति केन्द्र की स्थापना की गई. तत्कालीन पीएचईडी मंत्री डॉ. प्रेम कुमार द्वारा दो-दो बार इसके लिए शिलान्यास भी किया गया, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भी जलापूर्ति नही शुरू की जा सकी है. जबकि जलापूर्ति के लिए पाईप लाइन बिछाने का कार्य भी पूर्ण हो चुका है. *- डॉ. प्रमोद कुमार वर्मा*

वन विभाग की नर्सरी में सड़ रहे हैं पौधे

ज़िला शेरघाटी में जीटी रोड पर स्थित वन विभाग के नर्सरी से पौधा ले जाने वालों की कमी हो गई है. जिसके कारण शीशम, सागवान सहित कई प्रजाति के पौधे पेड़ का रूप लेते जा रहे हैं. बताया जाता है कि नाममात्र की राशि के मूल्य पर यहां से आम लोगों को वन विभाग की ओर से पौधे देने की व्यवस्था की गई है. वर्षों से संचालित इस नर्सरी से पिछले दो वर्षों से पौधा ले जाने वालों की कमी हो गई है. जिसके कारण वन विभाग की इस नर्सरी में नए पौधे लगाने के लिए जगह की कमी हो गई है. क्योंकि बड़े हो चुके पौधों को लोग नष्ट करना नहीं चाहते हैं. *-मिथलेश कुमार सिंह*

गुरारू-परैया रोड बदहाल

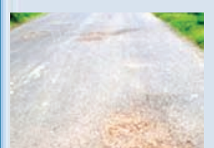

गया ज़िले के दो प्रखण्डों गुरारू और परैया को जोड़ने वाली सड़क वर्षों से बदहाली की स्थिति में है. परैया से गुरारू आने वाली सड़क का निर्माण कार्य वर्षों पहले शुरू हुआ था. लेकिन गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जांच के नाम पर इस सड़क का निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था, जो आजतक बंद है. इस सड़क पर शुरूआत में बिछाये गये बड़े-बड़े बोल्डरों पर लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. *- सुदर्शन कुमार*

सामुदायिक भवन में प्रखंड कार्यालय

गया ज़िले के कई प्रखण्डों में आज भी प्रखण्ड कार्यालय सामुदायिक भवन में चल रहा है. प्रखण्ड और अंचल कार्यालय के लिए भूमि व भवन उपलब्ध न होने के कारण ऐसी स्थिति बनी है. जीटी रोड पर स्थित डोभी प्रखण्ड कार्यालय भी अभी तक पंचायत के सामुदायिक भवन में चल रहा है. जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार की ओर से डोभी जैसे महत्वपूर्ण प्रखण्ड का कार्यालय अपने भवन में न होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी अपने घरों पर ही कागजात को रखते हैं तथा वहीं काम करते हैं. *-राजेश कुमार केसरी*

रोशन होगी शेरघाटी

शेरघाटी में निर्माणाधीन पावर सब-स्टेशन के निर्माण कार्य का काम तेज़ी से हो रहा है. इस स्टेशन के निर्माण हो जाने के बाद शेरघाटी अनुमण्डल मुख्यालय में बिजली की समस्या से निजात मिलने की संभावना है. *-सुशील कुमार*

अतिथि देवो भव : की अवधारणा पर काम करेंगे

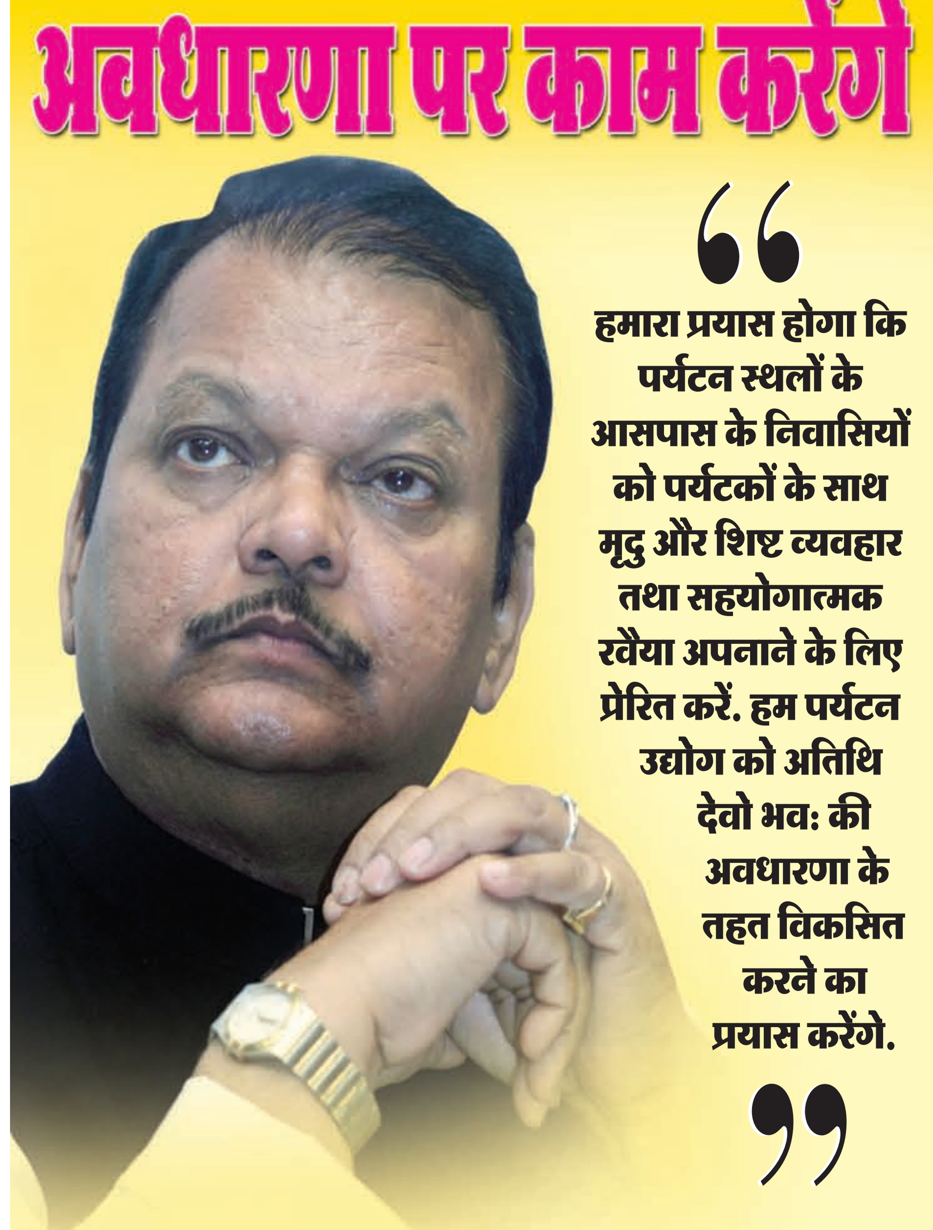

"हमारा प्रयास होगा कि पर्यटन स्थलों के आसपास के निवासियों को पर्यटकों के साथ मृदु और शिष्ट व्यवहार तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करें. हम पर्यटन उद्योग को अतिथि देवो भव: की अवधारणा के तहत विकसित करने का प्रयास करेंगे."

नवल किशोर सिंह

पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार की पर्याप्त संभावनाएं हैं. लेकिन उत्तर भारत की राज्य सरकारें इसके विकास के प्रति उदासीनता बरतती रही हैं. इसे कभी प्राथमिकता की सूची में नहीं रखा गया है. जबकि इसके ज़रिए आर्थिक-सामाजिक विकास के साथ काफ़ी मात्रा में राजस्व भी अर्जित किया जा सकता है. रांची के सांसद एवं भारत सरकार के नवनियुक्त पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद चौथी दुनिया के साथ विशेष बातचीत के क्रम में यह बातें कहीं.

सहाय ने कहा कि पर्यटन उद्योग को नक्सलियों या आतंकवादियों से नहीं राज्य सरकारों की विकास विरोधी नीतियों से ख़तरा है. कश्मीर जैसे आतंकवादियों के सघन प्रभाव वाले इलाक़ों में भी पर्यटन उद्योग पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है. आतंकवादी कभी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते. हां, स्थानीय लोगों की शरारत का वे ज़रूर शिकार बनते हैं. हमारा प्रयास होगा कि पर्यटन स्थलों के आसपास के निवासियों को पर्यटकों के साथ मृदु और शिष्ट व्यवहार तथा सहयोगात्मक रवैया अपनाने के लिये प्रेरित करें. हम पर्यटन उद्योग को अतिथि देवो भव: की अवधारणा के तहत विकसित करने का प्रयास करेंगे. केंद्रीय पर्यटन मंत्री सहाय के मुताबिक़ उत्तर भारत की राज्य सरकारें पर्यटन को उद्योग के रूप में नहीं लेती. उसके प्रति उदासीन रहती हैं. जबकि उत्तर भारत में स्प्रिच्युअल टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ईको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म सहित सभी तरह के पर्यटन केंद्रों के विकास की पर्याप्त संभावना है. इसके ज़रिये रोज़गार के अवसरों के विकास की भी पूरी गुंजाइश है. देश में कई जगहों पर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है. रांची में भी यह प्रस्तावित है, लेकिन ज़मीन की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण इसमें विलंब हो रहा है. उन्होंने कहा कि वे ग्रामीण इलाक़ों में रूरल ट्रेनिंग प्रोग्राम के कार्यक्रम के ज़रिये साक्षर और निरक्षर ग्रामीणों को पर्यटन उद्योग के लिये कुशल कर्मियों के रूप में प्रशिक्षित करेंगे. इन्हें हुनर से रोज़गार की ओर ले जाया जाएगा. वे फ़िलहाल उत्तर भारत में कुल विदेशी पर्यटकों के मात्र एक प्रतिशत को आकर्षित करना चाहते हैं. यह संख्या प्रतिवर्ष क़रीब एक करोड़ की होगी. देश में अभी कुल 38 टूरिस्ट सेक्टर हैं. हमारा उद्देश्य सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन का विकास करना है. भारत में अभी घरेलू पर्यटकों की संख्या 65 करोड़ प्रतिवर्ष के आंकड़े तक जा पहुंची है. यह काफ़ी उत्साहवर्द्धक है. यह आमलोगों की क्रयशक्ति में बढ़ोत्तरी के कारण संभव हुआ है. लेकिन पर्यटकों को आकर्षित करने का सरकारी स्तर पर प्रयास मात्र 0.58 प्रतिशत है. हम ऐतिहासिक स्थलों को थीम पार्क के रूप में विकसित करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड बिहार में बुद्ध सर्किट के विकास की पर्याप्त गुंजाइश है. झारखंड तो कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा है. जैन धर्म के लिये संवेद शिखरजी, हिंदुओं के कई मतों के लिये देवघर, तांत्रिकों के लिये रजरप्पा जैसे स्थल झारखंड में हैं. ईको टूरिज्म की भी यहां काफ़ी गुंजाइश है. सहाय ने कहा कि उनके पास पर्यटन विकास का एक ब्लूप्रिंट है, जिस पर वे काम करके बताएंगे कि पर्यटन का फलक कितना बड़ा है. सहाय के मुताबिक़ राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहते हुए भी साढ़े छह वर्ष की अवधि में मेगा फूड पार्क का निर्माण नहीं करा सके. वे निवेशकों को जुटाने में तो सफल रहे, लेकिन राज्य सरकार ने सब लीजिंग के लिए एनओसी नहीं दी. जिसके कारण एक भी उद्योग नहीं लग पाया. उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय बदल गया है, लेकिन वे रांची के सांसद के रूप में इस प्रोजेक्ट को शुरू कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाए रखेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

नौका दुर्घटनाएं कब रुकेंगी

राजेश सिन्हा

सात नदियों से घिरे खगड़िया ज़िले में लगातार नौका दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी तक न जाने कितनी की मांग उजड़ चुकी है तो किसी की गोद सूनी हो चुकी है. किसी के माथे से मां का साया छिन गया तो किसी ने अपने बाप को खो दिया है, लेकिन प्रशासनिक महकमे के लोगों की नींद तक नहीं खुल रही है. [illegible] से होकर प्रवाहित होने वाली सात नदियां सैकड़ों लोगों को लील चुकी हैं. ग़ैर सरकारी आंकड़े [illegible] हैं, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों पर ही ग़ौर [illegible] 8 में परबत्ता थाना अंतर्गत दुधैला में घटित [illegible] लोगों की मौत हुई थी, जबकि इसी वर्ष गोगरी [illegible] छह लोग नौका दुर्घटना के शिकार हुए. इसी [illegible] श्री रामविलास पासवान के गृह प्रखंड अलौली [illegible] बागमती नदी लगभग सौ लोगों को नौका [illegible] बात अलग है कि प्रशासनिक तौर पर महज [illegible] की पुष्टि की गई. इस वर्ष 2011 में गोगरी [illegible] में घटित नौका दुर्घटना में तीन लोगों के मारे [illegible] है. ख़बर लिखे जाने तक शवों की बरामदगी [illegible] की खोज जारी थी. यह तो सरकारी आंकड़ों [illegible] सरकारी आंकड़ों पर ग़ौर करें तो लगभग एक [illegible] की मौत नौका दुर्घटना में हो रही है. प्रसिद्ध [illegible] त्यागी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक [illegible] से अधिक [illegible] तक इस

ज़िले में कभी भी नौका दुर्घटना पर विराम लगा पाना संभव नहीं है. त्यागी के मुताबिक़ प्रशासनिक अमलों को न केवल यह पता करना होगा कि ज़िले होकर प्रवाहित होने वाली सात नदियों के कितने घाट पर नाव का परिचालन होता है बल्कि कितने घाटों पर अवैध रूप से नाव का परिचालन होता है और कितने पर वैध रूप से, अगर परिचालन होता है तो नाव मालिक और नाविक सरकारी नियमों का कितना पालन कर रहे हैं. उधर सरकारी घाटों के संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रभारी परिवहन पदाधिकारी अनुज कुमार ने कहा कि ज़िला परिषद के द्वारा खगड़िया प्रखंड के पांच, अलौली प्रखंड के बारह तथा चौथम प्रखंड के बारह सहित कुल 33 सरकारी घाटों पर नाव परिचालन की व्यवस्था है. जबकि जानकारों के मुताबिक़ सौ से अधिक घाटों पर क़ायदे क़ानून को ताक पर रखकर बाहुबलियों के द्वारा नाव का परिचालन अपने ढंग से कराया जा रहा है. वैसे अनुज के मुताबिक़ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को नौका परिचालन से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अगर सरकारी नियमों का पट्टेदार पालन नहीं करते हैं तो न केवल उनका लाईसेंस रद्द किया जाएगा बल्कि उनके विरूद्ध क़ानूनी कार्रवाई भी जाएगी. इतना ही नहीं बंगाल फेरी एक्ट 1885 के तहत उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी. बहरहाल, इस तरह की बातें तो सभी प्रशासनिक अमले कहते आए हैं और नौका दुर्घटना भी लगातार होती रही हैं, लेकिन अब भी क्या प्रशासनिक अमले नियमों का हवाला ही देते रहेंगे या किसी की मांग और गोद सूनी होने के बाद मातमपुर्सी करने के बजाए कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इस सवाल का जवाब पाने के लिए लोग बेताब हैं. लगातार हो रही नौका दुर्घटनाओं के बाद भी सरकारी अमलों की कानों पर आख़िर जूं तक क्यों नहीं रेंग रही है. यह सुलगता सवाल अब भी लोगों के दिलों में कौंध रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र इधर भी

पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है

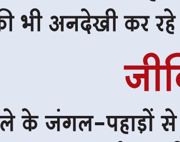

बिहार-झारखंड के सीमा पर स्थित गया ज़िले के बाराचट्टी के जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई तेज़ी से हो रही है. जीटी रोड से लगे जंगलों में स्थानीय लोगों की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई कर वाहनों से दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता है. आश्चर्य है कि वन विभाग के तमाम पदाधिकारी जीटी रोड पर हो रही खुलेआम ढुलाई की भी अनदेखी कर रहे हैं. *- सुनील कुमार सिंह*

जीविका का साधन बना पशुपालन

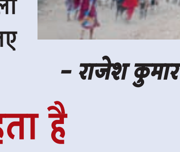

गया ज़िले के जंगल-पहाड़ों से घिरे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन भी जीविका का एक साधन बना हुआ है. ग्रामीण महिलाएं बकरी पालन कर इन दिनों अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं. हालांकि, इसके लिए महिलाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. महिलाएं बकरियों को लेकर सुबह जंगल में चली जाती हैं और गोधूली बेला में बकरियों को चराकर वापस लौटती हैं. इस बीच वे अपने घर के लिए जलावन की भी व्यवस्था कर लेती है. *- राजेश कुमार केसरी*

एनएच पेट्रोलिंग कार्यालय बंद रहता है

राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो पर आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न न हो इसकी देखरेख के लिए एनएचएआई का पेट्रोलिंग कार्यालय गया ज़िले के आमस प्रखण्ड अंतर्गत चंडी स्थान में बनाया गया है. लेकिन यह कार्यालय प्राय: बंद रहता है. जिसके कारण जीटी रोड पर घटना-दुर्घटना व अन्य कारणों से सड़क जाम होने की शिकायत लोग नहीं कर पाते हैं. जिससे इस मार्ग पर कभी-कभी घंटो आवागमन बाधित हो जाता है. जबकि इस कार्यालय का कार्य पेट्रोलिंग करते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या दो को आवागमन के लिए निर्वाध गति देना है. *- मिथलेश कुमार सिंह*

दो महीने बाद ही टूटने लगी सड़क

लगभग 20 वर्ष की लंबी जद्दोजहद के बाद सीवान के महाराजगंज-दारौंदा सड़क का निमार्ण तो हुआ, मगर मात्र दो माह के बाद ही सड़क जगह-जगह टूटनी शुरू हो गई. ज़िलाधिकारी लोकेश कुमार सिंह से इस मामले की जांच की मांग की गई है. लोगों का आरोप है कि अभिकर्ता एवं विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. यह सड़क पहले ज़िला परिषद के अधीन थी. काफ़ी मशक्कत के बाद सड़क को पथ निर्माण विभाग को सुपुर्द किया गया था. तब इस सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन दो माह बाद इसकी हालत ख़राब हो गई. *-धनंजय मिश्र*

शिव सैनिक लाईन होटल एवं शिव सैनिक गोदाम

एनएच- 31, बलदेव नगर, राजेन्द्र चौक, मौरकाही, खगड़िया

• दस हजार फीट छतदार गोदाम • सभी दृष्टिकोण से बेहद सुरक्षित स्थान

सुविधाएं • नो इंट्री की कोई कठिनाई नही • बिजली, पानी, शौचालय एवं हवा की 24 घंटे मुफ्त सुविधाएं • एक साथ 25 गाड़ियों के लाडिंग एवं अनलोडिंग की सुविधाएं

सच्चे मन से जनसेवा के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती

गोदाम के लिए सम्पर्क करें

प्रो0:- मनोज कुमार मनमौजी 9431287668, 9472472368

चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह
अध्यक्ष
झारखण्ड विधानसभा

रांची
दूरभाष-2440400, 2440075 (का.)
2440039 (आ.)
फैक्स 0651-2441712 (का.)
क्षेत्रीय आ. 0651-2215715
मोबाईल 9431170001

संदेश

अधिकार के लिए लड़ें, कर्त्तव्य पथ पर भी अड़ें।
होगा सबल गणतंत्र जब हम इस तरह आगे बढ़ें।।
अध्याय पूर्वजों का हम सब गर्व से मिल कर पढ़ें।।
आईये स्वर्णिम नया इतिहास गौरव का गढ़ें।।

गणतंत्र इस देश के लिए कोई नया शब्द नहीं । प्राचीन वैशाली का लघु गणतंत्र सैकड़ों वर्ष की गुलामी और इतिहास की त्रासदी झेलने के पश्चात देशभक्तों के रक्त से सिंचित हो कर भारत के विशाल गणतंत्र के रूप में 26 जनवरी, 1950 को पुनः प्रतिष्ठित हुआ। उसी दिन हमारा अपना संविधान प्रवर्त्तन से आया, जिसने स्वतंत्रता, समता और सामाजिक न्याय के अधिकारों से भारत के प्रत्येक नर-नारी को स्वाधीनता के उन्मुक्त वातावरण में स्वाभिमान के साथ जीने और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर दिया। 26 जनवरी 2011 को हम उसी गणतंत्र की 61 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस पवित्र दिवस पर हम अपनी उपलब्धियों का लेखा-जोखा तो करते हैं, लेकिन इस बात पर विचार करना भूल जाते हैं कि हमारा संविधान अधिकारों के मीठे फलों से लदा हुआ एक विशाल वृक्ष तो है, लेकिन उसके फलों को प्राप्त करने के साथ-साथ उसकी जड़ों को कर्तव्य के जल से सिंचित करना भी हमारा दायित्व है। आज हम सभी के मन में अधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ हठधर्मिता भी बढ़ी है, किन्तु कर्त्तव्य बोध का पक्ष उपेक्षित रह गया है, जिससे संविधान की मूल आत्मा आहत है।

तो आईये, इस गणतंत्र दिवस पर यह संकल्प लें कि हम सब अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने के साथ ही अपने दायित्वों के प्रति भी समर्पित रहेंगे तथा पूर्वजों की धरोहर इस महान् गणतंत्र पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। इस शुभ अवसर पर झारखण्ड के समस्त नागरिकों सहित सम्पूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

24/1/11
(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष
झारखण्ड विधानसभा, रांची

Directorate of Distance Education
Magadh University, Bodh-Gaya

Admission Notice

Directorate of Distance Education invites application from eligible candidates for admission to the following programmes/courses under distance learning mode :

Programme/Course	Session	Eligibility
1. M.A. in Education (Duration 2 yrs.)	2010-12	Graduate in any discipline from any recognised University or any other qualifications recgonised by Academic Council of M.U. as equivalent thereof.
2. Master of Library and Information Science (Duration 1 yr.)	2010-11	Degree in B.Lis.from any recognised Indian University or any examination recognised by the Academic Council of M.U. as equivalent thereof OR Graduate in any discipline with Diploma in Library and Information Sc.

Application Form for admission alongwith Prospectus can be obtained from 27th Jan. 2011 to 26th Feb. 2011 either from the DDE office M.U., BodhGaya or the Study Centres at (i) Gaya College, Gaya (ii) J.D. Women's College, Patna (iii) A. N. College, Patna (iv) Sri Arvind Mahila College, Patna (v) M.U. Branch Office, Patna (vi) Nalanda College, Biharsharif (vii) S. Sinha College, Aurangabad on payment of Rs. 500/- (for General/Other Categ.) and Rs. 250/- (for SC & ST Categ.) by Cash or through Bank Draft issued from Central Bank of India only in favour of **Director, DDE, M.U. BodhGaya** payable at **BodhGaya.** Forms may also be obtained by registered post directly from Directorate Office for which Rs. 50/- will be charged extra. Completed application form must reach on or before 28th Feb. 2011 by registered post or in person.

Reservation : Seats shall be reserved as per State Govt. rules applicable in academic institutions.

Note : *Downloaded application form (website www.mudde.org) will also be accepted with requisite fee Rs. 500/- & Rs. 250/- (for SC/ST) in the form of Demand Draft.*

Date of Counselling (For both the courses) : 03 to 07 March, 2011 at DDE Hqrs. M.U, Campus) All the applicants who have applied for the above course are requested to be present on the day of Counselling with all original degree/Certificate/Marks-sheet etc. & requisite course fee as mentioned in the prospectus. Eligible candidates will be admitted on the same day.

By the order of Hon'ble Vice-Chancellor
Dr. Md. Israil Khan
Director

एक नज़र इधर भी

प्लास्टिक एनीमिया का शिकार हुआ गोलू

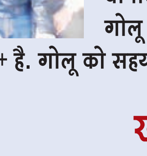

बुज़ुर्गों ने ठीक ही कहा है कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है. महनार प्रखंड के हसनपुर निवासी माधो झा का ग्यारह वर्षीय पुत्र गोलू प्लास्टिक एनिमिया का शिकार हो गया है. डॉक्टर के अनुसार, यह बीमारी करोड़ो में किसी एक को होती है. इससे पीड़ित मरीजों का ख़ून बनना बंद हो जाता है. आर्थिक विपन्नता के शिकार माधो झा इस बीमारी से पूरी तरह टूट चुके हैं. गोलू को प्रत्येक सप्ताह नया ख़ून चढ़ाना पड़ता है. जिसकी वजह से गोलू जिंदा है. पटोरी के एक स्वयं सेवी संगठन ने पच्चीस हजार रूपए दान दिए हैं. गोल का ब्लड ग्रुप AB+ है. गोलू को सहयोग करने के लिए इच्छुक व्यक्ति 9955926931 पर संपर्क कर सकते हैं. *- अंजूम परवेज*

खंडहर में तब्दील हुआ व्यापार मंडल भवन

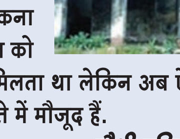

नवादा व्यापार मंडल सहयोग समिति अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. 1950-55 में निर्मित यह केंद्र अब खंडहर में तब्दील हो चुका है. किसानों को अनाज,कपड़ा, तेल, साबुन, आदि सरकारी दर पर यहां से मुहैया होता था. जब व्यापार मंडल सुचारू रूप से चल रहा था तब किसान इस केन्द्र की ओर खिंचे चले आते थे. परन्तु आज दो दशक से लोग इस केन्द्र की ओर झांकना भी पंसद नहीं करते हैं .ग्रामीण बताते हैं कि किसान अपनी फसल के अनुरूप अपने अनाज को व्यापार मंडल में रखते थे. विभिन्न किस्मों के बीज व खाद किसानों को उचित मूल्य पर मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. केन्द्र प्रबंधक सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि केन्द्र के नाम से अब भी ग्यारह रुपये खाते में मौजूद हैं. *-चौथी दुनिया ब्यूरो*

झारखंड व बिहारवासियों को गणतंत्र दिवस और वसंतपंचमी की हार्दिक शुभकामनायें

Harish Chandra Tiwari
Director
God Father Construction

God Father Constructions

।। विश्वास की ज़मीन पर रिश्तों की इमारत।।

Kishoreganj, Harmu Road, Ranchi, Jharkhand-834001
E-mail: shantiranchi@rediffmail.com, website : www.gfbuilder.com
Ph-09709700821, 9430752126, 9472779096

गणतंत्र दिवस व वसंतपंचमी की हार्दिक शुभकामनायें

मनोज सिंह
सहदेई बुजुर्ग

नववर्ष 2011, गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण के साथ-साथ खगड़िया की तमाम जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं!

सुनील चौधरी
प्रखंड अध्यक्ष
भाजपा, खगड़िया.

नववर्ष 2011, गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और खगड़िया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं!

शत्रुध्न प्रसाद भगत
जिला कार्यसमिति सदस्य
भाजपा सह जिला बीस सूत्री सदस्य
खगड़िया

सपनों का भारत बनाना है
नभ से आगे जाना है
देश को आगे बढ़ाना है
घर-घर में इसको लहराना है

गर्व से तिरंगा फहराना है....

जिंदल स्टील एण्ड पावर

Be A Proud Indian - Display Your TIRANGA

नवीन जिन्दल

God Father Constructions

विश्वास की ज़मीन पर रिश्तों की इमारत

पेश करते हैं

किश्त पर प्लॉट योजना

सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह दीजिए और पाइए

2000 वर्ग फुट का प्लॉट*

मालती नगर
Phase 1 & 2
Near ITI Bus Stand, Piska More, Ranchi

लोटस वैली
Ring Road, Rampur
Ranchi-Tata Highway, Ranchi

रोज़ सिटी
NH-33, Near Apollo Hospital
Ramgarh Road, Ranchi

Salient Features

- Park & Playground
- Community Hall
- Jogging Track
- Temple
- Shopping Space
- 24 Hrs Electricity
- Security Arrangements

जल्दी बुकिंग कराएं, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए

God Father Constructions
।। विश्वास की ज़मीन पर रिश्तों की इमारत ।।

Kishoreganj, Harmu Road, Ranchi, Jharkhand-834001
Email : shantiranchi@rediffmail.com, Website : www.gfbuilder.com
Phones : 09709700821, 9430752126, 9472779096, Maddy-8409380538, 8873102689
Vinod Rajpal-8873102690, Manish-8873102691, Maqsood-8873102692, Keshaw-8873102693, Ajay-8873102694, Sweety-8873102695, Mahesh-8873102696, Naveen-8873102697

*Conditions Apply

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश उत्तराखंड

दिल्ली, 07 फरवरी-13 फरवरी 2011

www.chauthiduniya.com

राहुल की सक्रियता से बसपा परेशान

राहुल गांधी का पूरा फोकस दलित, सवर्ण, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के युवाओं को आकर्षित करने पर है. अपनी लखनऊ यात्रा के दौरान आरक्षण के मसले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने ख़ुद सवाल दाग़ दिया कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो गया है?

सुरेंद्र अग्निहोत्री

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य भेदने के लिए 125 वर्ष पुरानी कांग्रेस पार्टी ने अपने युवराज राहुल गांधी को जंग के मैदान में सेनापति के रूप में उभारने का मन बना लिया है. कांग्रेस बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत शतरंज की बिसात सोच समझ कर बिछा रही है. कांग्रेस का एक-एक क़दम जहां माया सरकार को भय और ख़ौफ़ पैदा कर रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भर रहा है. इसकी बानग़ी अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पी.एल. पुनिया द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सम्मेलनों में उमड़ रही भीड़ से लग रहा है. इनकी सफ़लता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश के कार्यक्रमों में भाग लेने के दौरान सरकारी सुविधा में कटौती की घोषणा करके आरपार की लड़ाई के संकेत दिए हैं. लेकिन इस लड़ाई का दाव बहुजन समाज पार्टी के लिए उल्टा पड़ता नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस झांसी सांसद तथा केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने रिक्शे पर चलकर जता दिया है कि यह कटौती कांग्रेस को जनता के और पास जाने का मौक़ा दे रही है. कांग्रेस यूपी में 2012 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिहार से सबक ले रही है.

लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय समन्वय समिति की बैठक में बसपा की गहरी जड़ों को प्रदेश से उखाड़ फेंकने की रणनीति पर गहरा चिंतन मनन हुआ. कांग्रेस जान चुकी है कि प्रदेश में वापस आने का यह अच्छा मौक़ा है. जनता सपा के आतंक और बसपा के भी इसी ढर्रे पर चले जाने के कारण त्राहि-त्राहि कर रही है. बसपा से मुक़ाबला करने के लिए कांग्रेस अपने सेनापति के रूप में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है. अलीगढ़ के टप्पल में किसान आंदोलन से लेकर कानपुर के दिव्या कांड तथा बांदा के शीलू मामले में कांग्रेसजनों की सक्रियता के चलते मिले न्याय से जनता के मन में कांग्रेस के प्रति आशा जगी है. राहुल की इस पाठशाला में पढ़ाया गया यह पाठ बिहार के हवाहवाई कामों के बाद आया है. उनकी प्रदेश में बढ़ती सक्रियता से पहले बसपा तिलमिलाई थी, सपा ने भी राहुल के युवाओं से मिलने के कार्यक्रमों में अवरोध खड़ा करने के लिए सड़कों पर विरोध जताया. सपा समझ गई है कि राहुल के सेनापति के रूप में 2012 के चुनावी यज्ञ का मुख्यरथी बनना उनके लिए भारी पड़ सकता है. राहुल भी मजे हुए खिलाड़ी की तरह एक-एक शब्द नाप तौल कर बोल रहे हैं. उनका पूरा फोकस दलित, सर्वण, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के युवाओं को आकर्षित करने का है. आरक्षण के मामले पर लखनऊ यात्रा के दौरान युवाओं द्वारा पूछे गए प्रश्न पर प्रति प्रश्न करते हुए उन्होंने कहा कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों का विकास हो गया है? उन्होंने यह कहकर इशारे में अनेक बातें कह दी. जिनके निहतार्थ राजनैतिक धरातल पर राहुल गांधी की छवि को एक अलग दिशा दे गई. डॉ.पी.एल. पूनिया प्रदेश में दलित अत्याचारों के मामले में बसपा सरकार से लोहा लेने के लिए अपनी पूरी ताक़त झोक रहे हैं. उनका कहना है कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित पीड़ित है. बसपा के नेता तय करते है कि किसी दलित पीड़ित की थाने में रिपोर्ट लिखी जाए या नहीं. कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक पर लौटने के लिए कई दिशाओं में कोशिश कर रही है. प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा ने बताया कि पहली बार मात्र दो तीन सदस्यों को छोड़कर प्रदेश समन्वय समिति की बैठक में 68 सदस्य मौजूद रहे, जिनमें राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय महासचिव मोहसिना किदवई, रामनरेश यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, राष्ट्रीय सचिव परवेज हाशमी, अविनाश पांडेय, जयदेव जेना तथा सभी यूपी के केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक थे. बैठक में प्रदेश की राजनीतिक हालात के साथ ही केंद्र सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं 2012 के चुनाव के दृष्टिगत संगठन संबंधी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की. राहुल ने यूपी में केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं को सही ढंग से न लागू करने एवं बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सक्रिय योगदान दें. सोनिया गांधी के निर्देशानुसार इन योजनाओं की ज़िलेवार मॉनीटरिंग करें. जनता कांग्रेस के प्रति रुझान रखती है, उनसे सक्रिय संपर्क की आवश्यकता है तथा जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करें. उन्होंने कहा कि आप लोगों का यह सुझाव उचित है कि चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा शीघ्र होनी चाहिए. विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस पर प्रहार कर रहा है, इसलिए क्योंकि आज हर दल को कांग्रेस से ही ख़तरा है. कांग्रेस महाधिवेशन में सोनिया गांधी द्वारा संगठन के स्तर पर पांच बिंदु सुझाए गए थे. जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के लैगशिप प्रोग्राम मॉनीटरिंग हेतु प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी की अध्यक्ष रीता बहुगुणा होंगी तथा इसमें महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, तीन राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल एवं विधान परिषद दल के नेता शामिल होंगे. इस समिति द्वारा प्रत्येक ज़िले में एक-एक को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा. कमेटी प्रतिमाह लैगशिप प्रोग्राम की मॉनीटरिंग कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी. इसके अलावा सभी ज़िला, शहर कमेटियां, ज़िला, शहर स्तरीय सम्मेलन 31 मार्च के पहले आयोजित करेगी. इन सम्मेलनों में बूथ डेलीगेट, ब्लॉक डेलीगेट, ज़िला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, वार्ड डेलीगेट, फ्रंटल, विभाग और प्रकाष्ठों के ज़िला एवं ब्लॉक अध्यक्ष भाग लेंगे. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तथा यूपी के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने चौथी दुनिया से बातचीत में यूपी की रणनीति का ख़ुलासा किया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया 31 मई तक पूरी कर लेगी. दस केंद्रीय पर्यवेक्षक आगामी 30 मार्च तक पूरे प्रदेश भर में घूम-घूम कर संभावित प्रत्याशियों के नाम खाजेंगे. कांग्रेस की ज़िला इकाई, को-ऑर्डिनेटर तथा केंद्रीय पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट की महत्व देंगी. सिंह ने लोकसभा की तरह राज्य विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे मिलने की बात कही. सिंह की बात के पीछे राहुल गांधी की रणनीति नज़र आ रही है. केंद्रीय मंत्रीमंडल के विस्तार में जिस तरह क्षेत्रीय संतुलन जाति समीकरणों को महत्व देते हुए सलमान खुर्शीद तथा श्रीप्रकाश जायसवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा और बेनी प्रसाद वर्मा को इस्पात मंत्रालय का प्रभार सौंपा है. जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह के मंत्रालयों में बदलाव करके उनके क्षेत्रीय समीकरणों को अनुकूल करने की कवायद की गई है. महंगाई के दैत्य से लड़ने के लिए आयकर विभाग के छापों जैसी रणनीति अपना चुकी केंद्र सरकार यूपी के मामले में राहुल के इशारे को समझ रही है. इसीलिए प्रदेश में केंद्र सरकार का ख़जाना खुल रहा है. कांग्रेस ने समन्वय समिति की बैठक के बहाने मिशन 2012 के लिए ब्लू प्रिंट के लिए सभी निर्वाचित सांसदों और विधायकों की बात खुली सभा में सुनकर नई रणनीति अंजाम देने का मन बनाया है. कांग्रेस यूपी में आने के लिए दो रणनीतियों पर काम कर रही है, जिनमें एक ओर बसपा सरकार सपा से समान दूरी बनाकर अपने आप को अलग होने का संकेत दे रही है, दूसरी ओर रालोद, मोमिन कांफ्रेंस, पीस पार्टी तथा भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे दलों को अपने साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जुगत में लगी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद का संग कांग्रेस की जंग को मजबूत धार दे सकता है. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव माया सरकार की संवेदनहीनता पर हमला बोलते हुए कहते है कि यह सरकार इतनी ग़ैर जिम्मेदार है कि तीन वर्षों में सिर्फ़ 15 ग़रीब मरीजों को इलाज़ हेतु अनुदान दिया गया है. सरकारी दस्तावेज चीख-चीख कर माया सरकर की नाक़ामियों को उजागर कर रहा है. यूपी की जनता जाग चुकी है. कोरे आश्वासनों के बल पर इसे बरगलाया नहीं जा सकता है. बुंदेलखंड और पूर्वांचल की बदहाली तथा बुनकरों की मजबूरी को विशेष रूप से फोकस करके कांग्रेस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए तैयार है. वह कहती है कि प्रदेश की सियासी तस्वीर को बदलने के लिए तैयार जनता अब ठगे जाने को तैयार नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

ये हैं प्रोटोकॉल के नए नियम

नए नियमों के तहत सरकार ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों को राज्य अतिथि घोषित करने की तीन श्रेणियां बनाई है. पहली श्रेणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य राज्यों के राज्यपाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को रखा गया है. इन सभी को शासकीय एवं निज़ी कार्य से प्रदेश में आने पर राज्य अतिथि माना जाएगा. जबकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तिगण एवं न्यायमूर्तिगण, अन्य राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तिगण एवं न्यायमूर्तिगण, लोकसभाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, योजना आयोग उपाध्यक्ष एवं सदस्य, राज्यसभा व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों के मंत्रिमंडल सचिव, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त को शासकी कार्य से प्रदेश में राज्य अतिथि घोषित किया जाएगा. इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी अति विशिष्ट व्यक्ति को प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय कार्यवश पधारने पर राज्य अतिथि घोषित किया जाना प्रदेश सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा. निजी यात्रा पर आए केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्य अतिथि का दर्ज़ा नहीं दिया जाएगा. राज्य के तीर्थस्थलों की यात्रा पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों को तब तक राज्य अतिथि नहीं माना जाएगा जब तक राज्य सरकार न चाहें.

चौथी दुनिया

दीनानाथ क्रांतिकारी के मुताबिक ज़मीन में एक दर्जन से ज़्यादा निज़ी और सरकारी नलकूप लगे हैं, जिससे सिंचाई होती है.

औद्यानिक मिशन के तहत किसानों का उत्पादन बढ़ा अधिक लाभ दिलाना है. योजना के पहले चरण में किसानों को बीज, जैविक उर्वरक के अलावा सिंचाई के लिए धन मुहैया कराया गया है.

चौथी दुनिया

सबसे सक्रिय सांसद हैं सतपाल महाराज

संसद में जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप उनसे जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के कारण सांसद सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के अपने साथी सांसदों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है. पौढ़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद सतपाल महाराज संसद में न सिर्फ़ अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को प्रथम प्राथमिकता से उठा रहे हैं, बल्कि राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनैतिक मसलों पर भी केंद्र सरकार का ध्यान लगातार आकर्षित कर रहे हैं. पहाड़ में रेल पहुंचाने का सपना हो या फिर राज्य के पहाड़ी इलाक़ों में प्रचलित भाषाओं को पहचान और सम्मान दिलवाने का. महाराज गंभीरता से अपनी भूमिका निभाने में जुटे हुए हैं. राज्य से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाकर सतपाल महाराज ने न केवल अपने साथी सांसदों को पीछे छोड़ दिया, बल्कि उत्तराखंड कोटे से केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हरीश रावत से भी बाज़ी मार ली. भाषाओं का मुद्दा हो या फिर राजधानी का मसला, दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जहां सतपाल महाराज मुखर रहे, वहीं हरीश रावत कन्नी काटते नज़र आए.

गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज द्वारा गढ़वाली तथा कुमाऊंनी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने की मांग के बाद इन भाषाओं का नाम राष्ट्रीय स्तर पर उभर आया है. महाराज ने गढ़वाली तथा कुमाऊंनी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए संसद में बकायदा अपने सहयोगी सांसदों से लिखित सहयोग भी मांगा. विभिन्न दलों के दर्जनों सांसदों ने महाराज को अपना समर्थन भी दिया है. इसी तरह ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण के लिए 4300 करोड़ रुपए रेल बजट 2010-11 में स्वीकृत करवाया. वर्ष 1996 में रेल राज्य मंत्री के रूप में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का सर्वे करा चुके महाराज के प्रयासों से अब इस रेल लाइन के लिए रेल मंत्री ने 4300 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं. इतना ही नहीं 140 किलोमीटर के इस रेल लाइन के डिटेल सर्वे के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत भी हो गई है. फरवरी 2011 में सर्वे का कार्य शुरू हो जाएगा. देश की सेवा में लगे सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी सांसद सतपाल महाराज की अध्यक्षता में संसद की रक्षा संबंधी स्थाई समिति ने कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं. बतौर अध्यक्ष सतपाल महाराज ने वन रैंक वन पेंशन जैसी महत्वपूर्ण मांग को लागू करने को लेकर उन्होंने स्थाई समिति के माध्यम से सिफ़ारिश की. अधिकारी स्तर से नीचे के पूर्व सैनिकों की पेंशन में 2200 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी करवाकर उन्होंने 12 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को फ़ायदा पहुंचाया. रक्षा संबंधी स्थाई समिति के माध्यम से सैनिकों के लिए मैरिड एकोमोडेशन का प्रस्ताव पास करवाने का श्रेय भी गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज को ही जाता है.

कांग्रेस भले ही राज्य की स्थाई राजधानी के मसले पर मौन है और पार्टी के सांसद इस मसले पर मुंह खोलने का साहस न जुटा पा रहे हों, लेकिन सतपाल महाराज ने संसद में गैरसैण में विधानसभा का एक सत्र आयोजित किए जाने की मांगकर, केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मुहैया कराने का अनुरोध कर मजबूती से अपना पक्ष रखा. उनकी इस मांग पर केंद्र सरकार के 13वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड सरकार को राज्य में विधानसभा भवन बनाने के लिए 88 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर कर दी है. जिम कार्बेट नेशनल पार्क में बसे लोगों के पुनर्वास के लिए महाराज ने 25 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करवाकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एक स्थाई पीठ स्थापित किए जाने को लेकर भी सांसद महाराज ने लोक सभा में मांग उठाई. उत्तराखंड में ए.पी.एल और बी.पी.एल परिवारों के लिए व्याप्त खाद्यान्न की कमी को भी महाराज संसद तक ले गए और राज्य में खाद्यान्न प्रसंस्करण की 36 ईकाईयों के लिए और मेगा फूड पार्क के निर्माण के लिए 1001.8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई. राज्य के विद्यार्थियों को स्तरीय शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए खैरासैण में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए स्वीकृत करवाए. अपने प्रयासों से सांसद महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण के लिए 1 अरब 45 लाख से ज़्यादा की राशि केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृत करवाई. रामनगर को मॉडल सिटी बनाने के लिए महाराज ने वहां सीवरेज व पेयजल योजनाओं के लिए 145 करोड़ रुपए ए.डी.बी. से स्वीकृत करवाए शीघ्र ही विस्तृत कार्य योजना बन इस पर कार्य आरंभ हो जाएगा.

उत्तराखंड में समुचित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज ने सांसद निधि के 54 लाख 70 हज़ार 287 रुपए से 9 एंबुलेंस जनता को समर्पित कर एक नई पहल की. इसके साथ ही 85 लाख की सांसद निधि से 14 एंबुलेंस प्रस्तावित हैं, जो शीघ्र ही जनता को समर्पित की जाएगी. राज्य के निवासियों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं राज्य में ही मिले, इसके लिए उन्होंने ऋषिकेश में ए.आई.आई.एम.एस. के शीघ्र निर्माण का मुद्दा भी संसद में उठाया. अपने अथक प्रयासों से सांसद महाराज ने पौढ़ी चिकित्सालय के लिए सी.टी. स्कैन मशीन स्वीकृत करवाई. उत्तराखंड और वहां के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सतपाल महाराज ने पहली बार राज्य में वायुसेना की भर्ती रैली आयोजित करवा 850 स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया. इससे पहले थल सेना और नौसेना की सफ़ल भर्ती रैलियां आयोजित करवा हज़ारों उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को सेवायोजित करवाया. उत्तराखंड के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों की आपूर्ति, पहाड़ों पर बढ़ती वनाग्नि की समस्या, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आबंटित धनराशि का सही उपयोग जैसे मुद्दों को भी सतपाल महाराज ने संसद के भीतर बख़ूबी उठाया. दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता दिलाने के लिए भी गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज सबसे आगे रहे. अपने संसदीय क्षेत्र के जनपद पौढ़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी तथा नैनीताल के रामनगर इलाक़े का महाराज ने भ्रमण किया. संसद के शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने उत्तराखंड सरकार को अक्षम बताते हुए प्रधानमंत्री से आपदा पीड़ितों के लिए मुआवज़ा राशि मुहैया कराने की अपील की.

देश की सेवा में लगे सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी सांसद सतपाल महाराज की अध्यक्षता में संसद की रक्षा संबंधी स्थाई समिति ने कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं. बतौर अध्यक्ष सतपाल महाराज ने वन रैंक वन पेंशन जैसी महत्वपूर्ण मांग को लागू करने को लेकर स्थाई समिति के माध्यम से सिफ़ारिश की. अधिकारी स्तर से नीचे के पूर्व सैनिकों की पेंशन में 2200 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी करवाकर उन्होंने 12 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को फ़ायदा पहुंचाया.

सतपाल महाराज उत्तराखंड से लोक सभा सांसद होने के साथ–साथ रक्षा संबंधी स्थाई समिति के अध्यक्ष हैं और लोक लेखा समिति, रेलवे परामर्शदात्री समिति, भारतीय संसदीय दल, भारत नेपाल मैत्री समूह, भारत–जापान मैत्री समूह, राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य भी हैं. जिनके कार्यकलापों में वह सक्रिय रूप से व्यस्त रहते हैं. इन्हीं समितियों के माध्यम से वह क्षेत्र की जनता की आवाज़ अपेक्षित स्तर तक उठाते हैं. समय मिलते ही वह अपने क्षेत्र का भ्रमण कर समय–समय पर वहां की जनता की समस्याओं से अवगत हो उनके निवारण के प्रति क्रियाशील रहते हैं. सतपाल महाराज ने दो वर्ष से भी कम कार्यकाल में जिस तेजी से उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को उठाया इससे उनकी एक नई छवि जनता के बीच बन गई है. लगता है वह इस तथ्य को भली भांति समझने लगे हैं कि श्रद्धालुओं के बीच महाराज की छवि से अलग एक जन सेवक की छवि का निर्माण करके ही वह अपना जनाधार और व्यापक कर सकते हैं.

उर्मिला बलूनी
feedback@chauthiduniya.com

किसानों पर राजनीति कब तक

प्रियंका प्रियम तिवारी

उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला अब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गया है. कॉरपोरेट पूंजीवाद ने किसानों की उपजाऊ ज़मीन हड़पने और इसे अधिक से अधिक पैसा कमाने का ज़रिया बना दिया है. पिछले दिनों ऐसे कई मामले देखने को मिले. इसी क्रम में करछना पावर प्लांट के लिए अधिग्रहीत ज़मीन के उचित मुआवज़े की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों के तेवर को देखकर लगता है कि अब किसान चुप बैठने वाले नहीं हैं. करछना पॉवर प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण के तहत उचित मुआवज़ा न मिलने से गुस्साए किसानों ने करछना के कचरी गांव में जमकर हंगामा किया. उचित मुआवज़े को लेकर यहां किसान कई दिनों से अनशन पर बैठ रहे, उनकी मांगे माने बिना उन्हें जबरदस्ती उठाने से किसान और उग्र हो गए तथा पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर हमला बोल दिया. जिसमें बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और महिलाओं ने अधिकारियों पर पथराव किया. इसके बाद उनपर लाठीचार्ज किया गया जिससे भागने के बजाय किसान और क्रोधित हो गए. कई गांवों के किसान, महिलाएं एकजुट होकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और दिल्ली–हावड़ा रेल मार्ग जाम कर दिया. पटरियों पर जगह–जगह अवरोध लगा दिए गए और महिलाएं पटरी पर लेट गईं. कुछ किसानों ने इलाहाबाद–मिर्जापुर हाइवे को भी जाम कर दिया. पुलिस ने किसानों को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की तो नाराज़ किसानों ने रेलवे के पावर हाउस में आरएएफ के आधा दर्जन से ज़्यादा जवानों को बंधक बना लिया और एडीएम, एसडीएम, एएसपी और सीओ की पिटाई भी की. यही नहीं उन्होंने अधिकारियों की जीप और कार भी आग के हवाले कर दी. प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उनकी मांगे मानने के आश्वासन के बाद ही हंगामा शांत हुआ.

करछना में प्रस्तावित मेगावाट के पावर प्लांट के लिए ज़िला प्रशासन ने आठ गांवों देवरी, कचरा, देहली भगेसर, ढोलीपुर, कचरी, मेंडरा, भिटार, गढ़वा कला के सौ किसानों की कई हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहीत कर जेपी ग्रुप को सौंपी है, लेकिन उन्हें ज़मीन का पूरा मुआवज़ा नहीं दिया गया. जिन्हें मुआवज़ा मिल गया वे टप्पल की तर्ज़ पर अधिक मुआवज़ा देने की मांग कर रहे हैं. किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन उनकी मांगे मानना नहीं चाहती. अधिक मुआवज़े को लेकर पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति के बैनर तले दीनानाथ क्रांतिकारी के नेतृत्व में काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा था. पुनर्वास किसान कल्याण सहायता समिति का आरोप है कि उनकी जिस ज़मीन में धान, गेंहू समेत विभिन्न फ़सलें होती हैं उसे प्रशासनिक अफसरों के इशारे पर बंजर और असिंचित दर्शा दिया गया. दीनानाथ क्रांतिकारी का कहना है कि इसे लेकर अफसरों, जन प्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक से शिकायत की गई थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई. क्रांतिकारी के मुताबिक ज़मीन में एक दर्जन से ज़्यादा निज़ी और सरकारी नलकूप लगे हैं, जिससे सिंचाई होती है. उन्होंने बताया कि जिस समय ज़मीन के मुआवज़े का सर्वेक्षण किया जा रहा था, उसी समय कंपनी के लोगों तथा अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ गई थी. क्रांतिकारी का कहना है कि सौ से ज़्यादा ऐसे किसान हैं, जिनके पास ज़मीन देने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, यही नहीं बहुत से किसान तो बेघर भी हो जाएंगे. बेली अस्पताल में बेड पर पड़े किसान नेता दीनानाथ कहते हैं कि लंबे अनशन के बाद ज़िला प्रशासन ने दो मांगों को छोड़कर सभी मांगे मान ली थीं, लेकिन उसके बाद नियत बदल गई. उन्होंने कहा कि किसानों की लाखों की ज़मीन को तीन लाख रुपए प्रति बीघे की दर से एक फार्म भरवाकर प्रशासन ने क़ब्ज़ा कर लिया, जबकि इनका बाज़ार भाव तेरह लाख रुपए है. सरकार जब तक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवज़ा और पुनर्वास नीति लागू नहीं करती तब तक किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे.

पर यहां अपने हक़ की लड़ाई लड़ते किसानों पर भी राजनेता राजनीतिक रोटी सेंकने से बाज़ नही आए. पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के दौरान गुलाब विश्वकर्मा नाम के किसान की मौत हो गई. जहां तमाम नेता सहानुभूति जताते नज़र आए. अमर सिंह ने उनकी पत्नी सोना देवी को एक लाख रुपए दिए और पुनर्वास किसान सहायता कल्याण समिति की सभा में उन्होंने कहा कि टप्पल के किसानों को लाख मिल सकते हैं तो करछना के किसानों को क्यों नहीं. उन्होंने कहा कि मायावती, मुलायम सिंह और रेवती रमण सिंह ने मिलकर किसानों की सोना उगलने वाली ज़मीन जेपी ग्रुप को कौड़ियों के भाव दे दी. रीता जोशी भी वहां पहुंची और कहा कि दृढ़ता और साहस के बल पर किसानों ने लड़ाई जीती है, साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही. उन्होंने भी गुलाब की पत्नी को एक लाख रुपए का चेक दिया. इन सबके साथ ही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. पीएल पुनिया ने करछना के मसले को और हवा दे दी. उन्होंने संकेत किया कि इस मुद्दे पर संघर्ष होगा. पुनिया ने कहा कि सामान की क़ीमत हमेशा बनाने वाला तय करता है, न कि ग्राहक. उसी तरह ज़मीन की क़ीमत तय करने का हक़ किसान का है, लेकिन बसपा सरकार लगातार इसके ख़िलाफ़ चल रही है. उन्होंने मांग की कि करछना के किसानों को हरियाणा की तर्ज़ पर मुआवज़ा दिया जाए या फिर दरों को लेकर किसानों से सहमति ली जाए.

अधिग्रहीत की गई ज़मीन के मुआवज़े को लेकर किसानों के संघर्ष का यह कोई पहला मामला नहीं है, जैसा करछना में हो रहा है. गंगा एक्सप्रेस के तहत जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था तो यह क्षेत्र किसानों और प्रशासनिक संघर्षों का पर्याय बन गया. इसी तरह वर्ष 2004 में रिलायंस के दादरी प्रोजेक्ट के लिए जब किसानों को 2500 एकड़ ज़मीन पर कम मुआवज़ा दिया गया तो उन्होने पूर्व प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में आंदोलन किया. जिसमें उन्हे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत मिली. ममता बनर्जी ने भी कोलकाता के सिंगुर में टाटा के नैनो प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ सफ़ल आंदोलन चलाया. अभी हाल में ही बुंदेलखंड के बांदा जनपद में ग्राम पल्हरी व गुरेह के किसानों ने भी लगातार एक माह तक क्रमिक अनशन और अन्य अहिंसात्मक कार्यवाई करके प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर जान देंगे पर ज़मीनें नहीं देंगे के बैनर द्वारा आंदोलन किया. बहरहाल वित्तमंत्री, प्रणव मुखर्जी ने अब घोषणा की है कि ज़मीन अधिग्रहण पर मंत्रियों का एक समूह विचार कर रहा है और इस बारे में शीघ्र ही एक विधेयक लाया जाएगा.

असल में आज भी जिस भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 के तहत ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, दरअसल वह अंग्रेजी हुकूमत की देन है. इस क़ानून की नींव फोर्ट विलियम हंटर ने 1824 में बंगाल प्रांत में डाली, जिसकी सहायता से अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, सड़क, नहर और अन्य जन्य सुविधाओं के लिए किया गया. पर जब रेल लाइनों के बिछाने की बात आई तो 1894 में सरकार को और मजबूत करने के लिए इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए. यह विडंबना है कि आज भी इसी क़ानून के मुताबिक केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां अथवा राज्य सरकारों द्वारा अधिगृहित कंपनियां किसान आंदोलनों को कुचलते हुए उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर महज़ मुआवज़ा देकर खाना पूर्ति करते हैं. अमूमन यह अधिग्रहण अस्पताल, सड़क, फैक्ट्री, सेज जैसे व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी इस क़ानून की बैशाखी थाम ली जाती है. 1978 में इसे तब और मजबूती मिली जबकि 44वें संविधान संशोधन के ज़रिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया. इस तरह सरकार कभी भी, कहीं भी किसी की भी ज़मीन, भवन का अधिग्रहण की हक़दार हो गई.

आज भी जिस भूमि अधिग्रहण क़ानून 1894 के तहत ज़मीनों का अधिग्रहण हो रहा है, दरअसल वह अंग्रेजी हुकूमत की देन है. इस क़ानून की नींव फोर्ट विलियम हंटर ने 1824 में बंगाल प्रांत में डाली, जिसकी सहायता से अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, सड़क, नहर और अन्य सुविधाओं के लिए किया गया. पर जब रेल लाइनों के बिछाने की बात आई तो 1894 में सरकार का हाथ मजबूत करते हुए इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए. पर आज भी इसी क़ानून के मुताबिक़ केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां अथवा राज्य सरकारों द्वारा कंपनियां किसान आंदोलनों को कुचलते हुए उनकी ज़मीनों पर अतिक्रमण कर महज़ मुआवज़ा देकर खाना पूर्ति करती हैं.

priyankapriyamtiwari@chauthiduniya.com

केले की खेती ने किया मालामाल

गत वर्ष दो एकड़ में केले की खेती की थी, इस बार तीन एकड़ में. बैंक से रिटायर्ड होने के बाद पूरी तरह से खेती की तरफ़ ध्यान लगाया. पहले गन्ना की खेती करता था, जिसमें एक मुश्त रक़म मिल जाती थी. लेकिन रिटायर्ड होने के बाद बढ़ती महंगाई ने ख़र्च बढ़ा दिया. आसपास की जा रही केले की खेती में हाथ आजमाया और अब इसी में फ़ायदा नजर आ रहा है. यह कहना है पड़रौना के इंद्रजीत मिश्रा का. कुछ इसी तरह का रूझान देवरिया, पड़रौना, कुशीनगर और आसपास के किसान दिखा रहे हैं. कभी यह क्षेत्र गन्ना के उत्पादन में अग्रणी था. आसपास चीनी मिलों की अच्छी तादाद से उन्हें गन्ने की फ़सल को बेचने में परेशानी नहीं होती थी. नगदी फ़सलों में गन्ने की खेती कर किसान पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा कर लेते थे. एक के बाद एक बंद होती चीनी मिले और सरकारी नीति से तंग आकर किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होने लगा है.

कभी दस से बाहर एकड़ में गन्ने बोने वाले किसान अब या तो गन्ने की खेती छोड़ ही चुके हैं या फिर एक–आध एकड़ में बिजाई कर रहे हैं. समय के साथ क्षेत्र के मेहनतकश किसान परंपरागत खेती को छोड़ उन्नत किस्म के केले की आधुनिक खेती कर न सिर्फ़ अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं बल्कि बदलते परिवेश में अन्य किसानों के लिए प्रेरणाश्रोत बन रहे हैं. बिहार की सीमा से सटे होने के चलते छोटे किसान अपनी फ़सल निकटवर्ती ज़िलों में बेच देते हैं, वहीं बड़े पैमाने पर खेती करने वालों को लिए दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर के व्यावसायी अच्छी क़ीमत देने को तैयार बैठे रहते हैं. क्षेत्र की दोमट व समतल मिट्टी केले के खेती के लिए माकूल है. किसान टीसू कल्चर, अल्पान, मालभोग जी नाईल आदि किस्म के केलों की बिजाई कर रहे हैं. केले का सीजन जुलाई से नवंबर तक होता है जबकि बुवाई मानसून आते शुरू हो जाता है. एक एकड़ में 1620 पौधा लगाया जाता है, जिसमें 30 से 35 हज़ार तक ख़र्च आता है. यदि फ़सल अच्छी रही तो 50 से लेकर 100 रु. प्रति घौद की आमदनी होती है. यानी प्रति एकड़ 70 हज़ार से लेकर एक लाख रुपए की आमदनी हो जाती है. जो किसान स्वय मंडी में ले जाने को सक्षम होते हैं उनको लाभ कुछ ज़्यादा मिल जाता है. केले की खेती के साथ सह खेती भी की जा सकती है, जिससे अच्छी आमदनी हो सकती है. वहीं, गन्ने की एक एकड़ में खेती करने वाले किसानों को 35 से 40 हज़ार की ही आय होती है.वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल करके एक हेक्टेयर में 100 टन केला उगा सकते हैं. कर्नाटक के सिरसी ज़िले के बनवासी गांव में रहने वाले अब्दुल शेख एक किसान है. जिन्होंने गन्ने की खेती में मिसाल क़ायम की है. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के प्रोग्रेसिव किसानों की सूची में इनका नाम प्रमुखता से आता है. इसकी वजह यह है कि अब्दुल शेख ने केले की खेती को नया आयाम दिया है. भारत में पैदा होने वाले कुल फलों में केले का योगदान 32 फ़ीसदी है. देश में अभी हर साल कुल दो करोड़ टन केले का उत्पादन होता है. मांग बढ़ने के साथ ही क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में केले की खेती से जुड़ रहे हैं. अच्छी आमदनी से किसानों ने मोटे अनाज की खेती करना कम कर दिया है. भले ही यह कम क्षेत्रफल में हो लेकिन हर किसान के खेत में केले की खेती हो रही है. क़रीब दो वर्ष पूर्व टिशू कल्चर के केले की खेती शुरू हुई. लोगों ने जब इसके फ़ायदे समझे तो अब तो टिशू कल्चर के केले की खेती जनपद में आर्थिक क्रांति के रूप में बढ़ती जा रही है. क्षेत्र का पढ़ा लिखा युवा वर्ग नौकरी पेशा करने की बजाय केले की खेती को एक व्यवसायिक रूप दे रहा है. केले की महंगाई ने इस वर्ष किसानों को और मालामाल कर दिया. केले की खेती से जुड़े किसानों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि अब उन्हे मौसम की मार से होने वाले आर्थिक नुक़सान से निजात मिल सकेगा. कृषि वैज्ञानिकों ने केले की नई प्रजाति विकसित की है. नई प्रजाति टिशू कल्चर मौसम की मार जैसे तेज बारिश और आंधी सहने में सक्षम है. केले की इस नई प्रजाति के पौधों की ऊंचाई चार से पांच फिट के बीच होगी. जिससे कि गर्मी के दिनों में चलने वाली तेज हवाओं, आंधी और बारिश से फ़सल सुरक्षित रह सके.

बौनी किस्म के इस प्रजाति के पौधे लगवाकर किसानों के उत्पादन बढ़ाने की ज़िला उद्यान विभाग ने कवायद शुरू कर दी है. ग़ौरतलब है कि केले की अब तक लगाई जाने वाली प्रमुख किस्मों में हार्वेस्टा समेत अन्य फ़सल की ऊंचाई सात से नौ फिट तक की होती है. जिससे तेज हवा और बारिश में इनके गिरने की आशंका बनी रहती है. पौधों के गिरने से किसानों को भारी आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ता है. योजना के पहले चरण में किसानों को बीज, जैविक उर्वरक के अलावा सिंचाई के लिए धन मुहैया कराया गया है. किसानों को प्रशिक्षण दिला इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है. विकल्प के रूप में शुरू की गई केले की खेती से हो रही आमदनी को देख किसानों का रुझान तेजी से इस ओर बढ़ रहा है.

मनीष कुमार श्रीवास्तव
feedback@chauthiduniya.com

गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री मायावती और राज्यपाल बनवारी लाल जोशी.

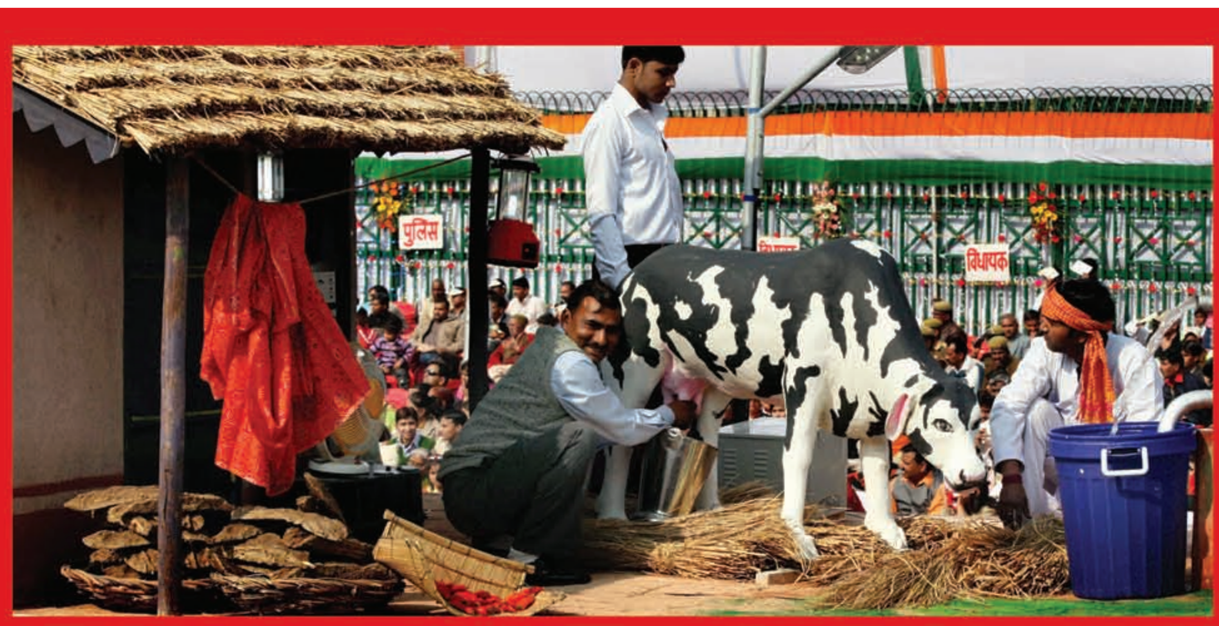
इस अवसर पर आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं.

गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी कैडेट ने भी परेड में भाग लिया.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च डॉ. आर एस शर्मा की मानें तो सरोगेट मांओं का स्वास्थ चिंता का विषय है. हालांकि इस कारोबार से कुछ लोग सकारात्मक पहलू भी निकालते हैं.

बुंदेलखंड

किराए की कोख, मजबूरी या शौक़

बुंदेलखंड में महिलाओं और लड़कियों को रोज़ी-रोटी की मार ने इतना मजबूर कर दिया है कि वे अपनी कोख का सौदा करने पर आमादा हैं. यानी सरोगेट मदर बनना अब उनके लिए रोज़गार का एक ज़रिया बन गया है. उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हैं कि इस तरह से कोख का सौदा कर वह अपना ही स्वास्थ्य बिगाड़ रही हैं.

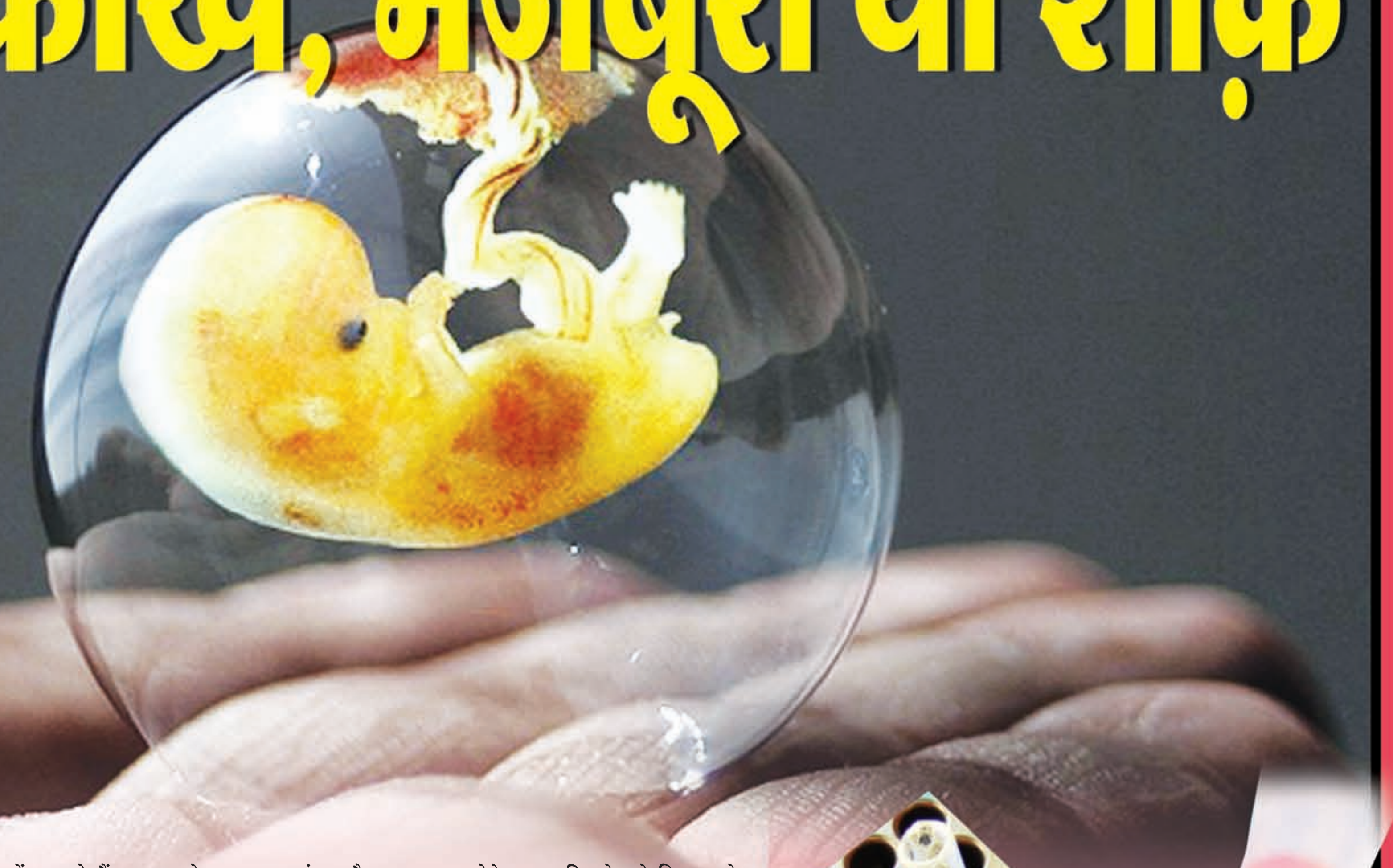

राजेश कुमार

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर समस्याओं की बात की जाए तो काफ़ी लंबी फ़ेहरिस्त बनती है. जिसमें बेरोजगारी, सूखा, भुखमरी और दस्यु सरगनाओं जैसी कई समस्याएं हैं. इन्हीं वजहों से बुंदेलखंड का सामाजिक और आर्थिक ढांचा चरमराया हुआ है. इन सबके बीच यहां के लोग किस तरह जीवन बसर करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है. ज़्यादातर भूमिहीन किसान मजदूरी के वास्ते यहां से पलायन कर चुके हैं और महिलाएं किसी तरह से रोज़ी-रोटी का इंतेज़ाम करने में लगी हैं. लेकिन अब रोजगार और रोज़ी-रोटी की मार ने यहां की महिलाओं और लड़कियों को इतना मजबूर कर दिया है कि वे अपनी कोख का सौदा करने पर अमादा हैं. यानी सरोगेट मदर बनकर पैसा कमाने को रोजगार बना रही हैं.

जी हां, भारत में सरोगेसी का यह कारोबार अब बुंदेलखंड में भी फैल रहा है. आर्थिक हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अब बुंदेलखंड के विभिन्न इलाक़ों की कुंवारी लड़कियां अपनी कोख किराए पर देकर अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हैं. सरोगेसी की सबसे बड़ी वजह है ग़रीबी. जिसकी बुंदेलखंड में कोई कमी नहीं है. ग़रीब महिलाओं की पैसों की चाहत उन्हें इस कारोबार में उतरने को मजूबर करती है. यह मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसे पुरुष ग़रीबी से तंग आकर अपना ख़ून और किडनी बेचने को तैयार हो जाते हैं, ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके. वैसे ही महिलाएं भी ग़रीबी के कारण अपनी कोख को किराए में देकर अपनी जान जोखिम में डालती हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे के बच्चे को पालती हैं.

इससे पहले सरोगेसी भारत के कुछ ही राज्यों जैसे उड़ीसा, भोपाल, केरल, तमिलनाडु, मुंबई आदि में फैली थी. पर अब इस विदेशी कारोबार ने यहीं भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं. विदेशी कारोबार इसलिए, क्योंकि अब तक सरोगेट मदर बनने की घटनाएं सिर्फ़ विदेशों में ही सुनने को मिलती थीं. यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि सरोगेसी ऐसे राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलती थी, जहां पर्यटक ज़्यादा आते थे. पर अब सरोगेसी के मामले बुंदेलखंड में भी मेट्रो सिटीज की तरह बढ़ रहा है. आलम यह है कि यहां कई अन्य राज्यों समेत विदेशों से दंपत्ति सरोगेट मदर की तलाश में आ रहे हैं. इस कारोबार का सबसे बूरा पक्ष यह है कि इसमें अविवाहित लड़कियों की भी बड़ी संख्या सामने आ रही है, जो पैसों की खातिर बिन ब्याही मां बनने को भी तैयार हैं. अभी भी देश में बिन ब्याही मां बनना समाज के लिए कलंक माना जाता है. पर अब चंद रुपयों की खातिर लड़कियां घर से महीनों दूर रहकर कोख किराए पर देने जैसा जोखिम भरा काम कर रही हैं. जब इस तरह की लड़कियों से ऐसा करने की वजह पूछी जाती है तो सबका अलग-अलग जवाब होता है. अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाने को तैयार ये लड़कियां बड़ी बेबाकी से कहती हैं कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं है. आज हमें कुछ महीनों में ही लाखों रुपए मिल रहे हैं, वो भी बग़ैर कोई ग़लत क़दम उठाए, तो फिर इसमें हर्ज़ क्या है? बुंदेलखंड की रमा (परिवर्तित नाम) की बचपन में ही शादी हो गई. गौने से 3 महीने पहले ही पति ने दूसरी शादी कर ली. अब वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, लेकिन इसमें ग़रीबी आड़े आ रही है. विभा ने इसके लिए सरोगेट मदर बनने का रास्ता चुना. इसी तरह सुनीता (परिवर्तित नाम) के माता-पिता की मृत्यु हो गई है. अब वह एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट है. पर इस नौकरी से वह संतुष्ट नहीं है. उसने आत्मनिर्भर होने के लिए सरोगेट मदर बनने का निर्णय लिया है. जब उससे यह पूछा गया कि क्या उसे ऐसा करने में समाज से डर नहीं लगता है. तो उसने कहा, जब मुझे भूख लगती है तो कोई पुछने नहीं आता, ऐसे में डरे किससे? क्या उस समाज से डरूं, जो मेरी मदद नहीं कर सकता. इस तरह न जाने कितनी लड़कियां है, जो अपनी जिम्मेदारी और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी कोख का सौदा कर रही हैं. आगरा की झुग्गी बस्ती में काम करने वाले एक ग़ैर सरकारी संगठन ने क़रीब एक साल पहले एक सर्वेक्षण कराया. इस सर्वे में यह बात सामने आई थी कि वहां की अधिकांश महिलाएं मजबूरी में किराए की कोख पालती हैं. कुछ महिलाएं घरवालों की मर्ज़ी से ऐसा कर रही हैं. उन महिलाओं का दर्द असहनीय था, जो चुपके -चुपके ऐसा करते पाई गईं. वह घरवालों को बता नहीं सकतीं. पति कमाता नहीं है, इसलिए बिना बताए ही किसी धनवान जोड़े के लिए बन जाती हैं सरोगेट मदर. ऐसी महिलाओं को समाज की भी चिंता रहती है. अपने पास रह रही औलाद की भी चिंता कचोटती रहती है. फिर भी दूसरों की औलाद को पैदा होने से पहले पालती हैं. अब आपको बताते हैं कि यह कारोबार कैसे होता है. सरोगेट मदर को अपनी कोख की कितनी क़ीमत मिलती है और कैसे यह बुंदेलखंड तक पहुंचता है. दरअसल, सरोगेट मदर की खोज के लिए पहले डॉक्टर की सलाह ली जाती है, फिर विभिन्न अख़बारों में और आज-कल तो इंटरनेट पर भी सरोगेट मां की खोज की जाती है. उसके बाद महिला की पूरी मेडिकल जांच की जाती है कि कहीं उसे कोई रोग तो नहीं है. सरोगेट मां की उम्र अमूमन 18 साल से 35 साल के बीच होती है. सरोगेट मां का सारा ख़र्च वही लोग उठाते हैं, जिन्हें बच्चा चाहिए और रही बात क़ीमत की तो, किराए पर कोख लेने का ख़र्च भारत में जहां तीन-चार लाख तक होता है, वहीं दूसरे देशों में कम से कम 35-40 लाख रुपए तक ख़र्च आता है. वजह साफ़ है कि क्यों विदेशी भारत कर रुख कर कर रहे हैं. इसके अलावा बांझपन भी सरोगेसी की एक बड़ी वजह मानी जाती है. बांझपन के कारण महिलाएं भी अपने पति का इस कृत्य में साथ देने को तैयार हो जाती हैं. भारत के दक्षिणी इलाक़ों से शुरू हुआ यह कारोबार बुंदेलखंड जैसे इलाक़े तक पहुंच गया है.

हालांकि बीच-बीच में ख़बरें आती रहती हैं कि सरकार इस कारोबार को नियंत्रित रखने के लिए कई प्रावधान बना रही है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक़ भारत में सरोगेसी इसलिए भी आसान है, क्योंकि हमारे यहां अधिक क़ानून नहीं हैं, और जो हैं उनकी नज़र में यह मान्यता प्राप्त है. यही वजह है कि आज सरोगेसी एक विवादास्पद मुद्दा बनता जा रहा है. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सरोगेट मदर ने बच्चा पैदा होने के बाद भावनाओं के आवेश में आकर बच्चे को उसके क़ानूनी मां-पिता को देने से इंकार कर दिया. इसके अलावा सबसे ज़्यादा गंभीर मामले तब पैदा होते हैं, जब सरोगेट मां की कोख से पैदा हुआ बच्चा विकलांग हो या फिर करार एक बच्चे का हो और जुड़वा बच्चे हो जाएं. ऐसे में जेनेटिक माता-पिता बच्चे को अपनाने से इंकार करने लगते हैं. साथ ही भारत में एक बात और विवाद का विषय है. वह है विदेशी ग़े-दंपतियों को बच्चा कैसे दिया जाए? टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के एक संचालक कहते हैं कि कोख किराए पर देने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ने की असली वजह, इनके लिए उपलब्ध मार्केट है. वहीं उच्च वर्ग की महिलाएं अपने फिगर को मेंटेन रखने, गर्भपात होने से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए सरोगेट मदर की मदद लेना ज़्यादा बेहतर समझती हैं. गर्भधारण का अनुभव प्रमाण सहित होना ज़रूरी है. इसके लिए विवाहित होने की बाध्यता नहीं है. अविवाहित लड़िकयां भी गर्भधारण का अनुभव होने पर सरोगेट मदर बन सकती हैं. हालांकि इसमें विवाहिता के पति की अनुमति ज़रूरी है. अविवाहिता और तलाकशुदा के लिए केवल उसकी अपनी मर्ज़ी ही काफ़ी है, जबकि तलाक के लंबित मामलों में महिला कोख किराए पर नहीं दे सकती. महिला को ऐसी कोई बीमारी न हो, जिसके बच्चे में स्थानांतरित होने की आशंका हो और उसकी उम्र 21 से 45 साल के बीच हो. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च डॉ. आर.एस. शर्मा की मानें तो सरोगेट मांओं का स्वास्थ्य चिंता का विषय है. हालांकि इस कारोबार का कुछ लोग सकारात्मक पहलू भी निकालते हैं. डॉक्टर पटेल के मुताबिक गर्भ धारण न कर पाना किसी भी दंपत्ति के लिए बहुत दुखद होता है. इसके लिए सरोगेसी एक अच्छा ज़रिया है. लेकिन अब भारत सरकार सरोगेसी के इर्द-गिर्द कुछ नियम बनाने वाला है. क्योंकि इस कारोबार के बढ़ने के साथ-साथ इसमें होने वाली कुछ गड़बड़ियों को भी बढ़ावा मिल सकता है.

सरकार तो खैर इन नियमों में समय-समय पर संशोधन करती रहेगी, लेकिन तब तक बुंदेलखंड में इस तरह के मामलों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा. क्योंकि यह मसला इतना साधारण नहीं है जितना इसे समझा जा रहा है. क्योंकि अगर बुंदेलखंड की ज़्यादातर महिलाएं और लड़कियां अपनी-अपनी मजबूरी का वास्ता देकर शॉर्टकट में पैसे कमाने के इस कारोबार के जुड़ जाएंगी तो परिणाम घातक होंगे. इससे न सिर्फ़ सामाजिक ढांचा बिगड़ेगा बल्कि जान का भी जोखिम होगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

क्या है सरोगेसी

सरोगेसी के अगर शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है किसी और को अपने काम के लिए नियुक्त करना. इस प्रक्रिया में वास्तविक मां की जगह एक दूसरी औरत बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख किराए पर देती है. सरोगेसी को वह महिलाएं अपनाती हैं, जो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होती हैं. इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणुओं को निषेचित कराकर भ्रूण को उस महिला की कोख में डाल दिया जाता है. इसमें एक प्रतिशत अंश भी सरोगेट मदर का नहीं होता है. इस प्रक्रिया से बच्चों के साथ उनका जेनेटिक संबंध बरकरार रहता है. इस प्रक्रिया से जन्मे बच्चे का रंग, लंबाई, बालों का रंग और प्रकृति, आनुवांशिक गुण आदि सभी जेनरिक मां-बाप के होते हैं. यानी की कोख सरोगेट मां की होती है, पर बच्चे का आनुवांशिक संबंध अपने असल माता-पिता से होता है.

कुछ नियम भी हैं

1. सरोगेसी कांट्रेक्ट में सरोगेट मां के जीवन बीमा का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाना चाहिए.
2. बच्चे के जन्म-प्रमाण पत्र में केवल जेनेटिक माता-पिता का ही नाम होना चाहिए.
3. सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे पर जेनेटिक माता-पिता का हक़ होगा. गोद लेने वाले मामलों की तरह इसमें किसी घोषणा की ज़रूरत नहीं होती.
4. किसी वजह से सरोगेट बच्चे की डिलीवरी से पहले जेनेटिक माता-पिता की मृत्यु हो जाती है या फिर उनके बीच तलाक हो जाता है या उनमें से कोई भी बच्चे को लेने से मना कर दे, तो बच्चे के लिए आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की जाए.